राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 64

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

लार्ड्स टेस्ट में केएल राहुल ने ठोका शतक

>> 12

कोरोना संक्रमितों की सेवा के लिए टाल दी शादी

बठिंडा : कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्करों ने निजी हितों को पीछे रख कर मरीजों की रक्षा को प्राथमिकता दी। डा. हरजोत ने संक्रमितों की सेवा के लिए अपनी शादी टाल दी। स्वजन समझाते रहे, लेकिन उन्होंने मरीजों की देखभाल को ही अहमियत दी। (पेज-6)

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए दोगुनी हुई ऋण सीमा

नई दिल्ली : सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा को दोगुना कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला उद्यमियों के लिए 1,600 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करते हुए कहा, महिला स्वयं सहायता समूह को अब तक जहां 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलता था, उसे अब 20 लाख रुपये कर दिया गया है। (पेज-3)

औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, खुदरा महंगाई भी कम हुई

नई दिल्ली : जून के औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 13.6 फीसद की वृद्धि हुई है। मैन्यूफैक्चरिंग में भी 13 फीसद का इजाफा हुआ जो मांग की बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। वहीं, इस वर्ष जुलाई की खुदरा महंगाई दर गिरावट के साथ 5.59 फीसद रह गई, जो जून में 6.26 फीसद थी। जुलाई में खाने-पीने की चीजों के खुदरा दाम में भी कमी आई। (पेज-7)

पहले दिन से संसद ठप करने का मन बना चुका था विपक्ष

मंत्रियों ने मानसून सत्र में विपक्ष की कारगुजारियों का दिया ब्योरा

- विपक्षी सदस्यों ने शीशा तोड़ने, वीडियो बनाने, धक्कामुक्की करने जैसे आपत्तिजनक कृत्य किए
- विपक्ष ने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाओं को कुचलने का निम्नतम स्तर पार किया
- सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी तो फिर राज्यसभा में कोरोना पर कैसे चर्चा हुई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शोरशराबे व हुड़दंग की घटनाओं के बीच संसद का मानसून सत्र तय समय से दो दिन पहले ही समाप्त हो चुका है और सत्ता पक्ष व विपक्ष एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष पहले दिन से ही सत्र को ठप करने का मन बना चुका था। फिर भी बार-बार समझाने की कोशिश की गई, नेताओं से संपर्क साधे गए, लेकिन विपक्ष ने विरोध के क्रम में शीशा तोड़ने, सदन की मेज पर चढ़कर वीडियो बनाने, धक्कामुक्की करने जैसे आपत्तिजनक कृत्य किए, जिसके लिए उन्हें दंड मिलना चाहिए। राज्यसभा के सभापति से इसकी अपील भी की गई है।

गुरुवार को जहां विपक्ष ने सरकार को घेरा, वहीं सरकार के आठ मंत्रियों-पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रल्हाद जोशी, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, मुरलीधरन व अर्जुनराम मेघवाल ने आरोपों को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि यह साबित करने का प्रयास किया कि विपक्ष ने संसदीय मर्यादाओं को कुचलने का निम्नतम स्तर पार कर दिया।

जोशी ने कहा, पहले ही दिन से विपक्ष का रवैया अवरोध का था। नए मंत्रियों का सदन के अंदर परिचय कराने से रोका गया। बात करने की कोशिश हुई तो पता चला कि विपक्ष ने वाकआउट का फैसला कर लिया है। पीयूष गोयल ने कहा, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चर्चा को तैयार नहीं थी तो फिर रास में कोरोना पर कैसे चर्चा हुई? ओबीसी बिल पर दोनों सदनों में चार दर्जन से ज्यादा सदस्यों ने हिस्सा लिया।

नई दिल्ली में गुरुवार को आठ केंद्रीय मंत्रियों (बाएं से) अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, प्रल्हाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और वी मुरलीधरन ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष की कारगुजारियों का ब्योरा दिया। पीआइबी

मंत्री के हाथ से कागज छीनकर उछाला गया

प्रल्हाद जोशी ने कहा कि लगता है कि राहुल गांधी कुछ लिंक मिस कर जाते हैं, शायद इसीलिए वह ऐसी बात कर रहे हैं। पेगासस पर सरकार के मंत्री खुद वक्तव्य देने आए थे, लेकिन विपक्ष को तो सुनना ही नहीं था। उन्हें केवल अवरोध पैदा करना था। इसलिए उनके हाथ के कागज छीनकर उछालने का असंसदीय काम किया।

चर्चा से भागने के लिए सारा उपक्रम कर रहा था विपक्ष

अनुराग ठाकुर और भूपेंद्र यादव ने कहा कि दो दिन पहले जिस तरह विपक्षी दलों ने टेबल पर चढ़कर वीडियो बनाया, उसकी कोई माफी नहीं हो सकती है। विरोध करने का तरीका होता है, लेकिन उन्हें उपद्रव करना था। चर्चा से भागने के लिए ही विपक्ष ने सारे उपक्रम किए थे। विपक्ष के सांसदों ने दरवाजे के शीशे को तोड़ दिया, जिससे एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गई। विपक्षी सांसदों ने संसद को सड़क में बदल दिया।

ऐसी सजा मिले कि भविष्य के लिए डर बना रहे

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चोरी और सीनाजोरी जैसा आचरण कर रहा है। उसे अब डर सता रहा है कि इस आचरण का दंड भुगतना होगा। उन्हें इस तरह दंडित किया जाना चाहिए कि भविष्य में हर सदस्य भयभीत रहे।

विपक्ष ने सहयोग नहीं किया तो पारित कराने पड़े विधेयक : संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, संसद जनता का काम करने और विधेयक पारित करने के लिए है। जब विपक्ष ने अवरोध पैदा करने का फैसला सुना दिया तो सरकार को कुछ विधेयक पारित कराने पड़े। टैक्सेशन ला, साधारण बीमा कारोबार, लिमिटेड लैबिलिटी पार्टनरशिप जैसे विधेयक पारित हुए तो केंद्रीय विवि संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता व प्रबंध संस्थान विधेयकों को मंजूरी दी गई। इसी तरह सामाजिक न्याय व सुधार के लिए ओबीसी विधेयक, किशोर न्याय संशोधन विधेयक, अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन जैसे विधेयक पारित कराए गए।

कांग्रेस ने भी शोर-शराबे में पारित कराया था विधेयक : प्रल्हाद जोशी ने बताया कि कांग्रेस के काल में 17 ऐसे विधेयक थे, जो एक मिनट से चार मिनट के अंदर पारित कराए गए थे। आंध्र प्रदेश के बंटवारे से जुड़े विधेयक समेत आधा दर्जन से अधिक विधेयक शोरशराबे के बीच पारित कराया गया था।

सांसदों के साथ मारपीट होने का दावा कर सड़क पर उतरा विपक्ष

- राज्यसभा में हुई घटना के खिलाफ 15 विपक्षी दलों ने निकाला विरोध मार्च
- राहुल ने कहा, बाहर से बुलाए लोगों को नीली वर्दी में उतार कर की गई मारपीट

राज्यसभा में बीमा बिल पारित कराने के दौरान हुए घमासान के विरोध में गुरुवार को विपक्षी दलों के मार्च की अगुआई करते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद का घमासान सड़क पर उतर आया है। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में उनके सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। विपक्ष के 14 नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा, बाहर से लोगों को लाकर विपक्ष के सांसदों, जिसमें महिला सांसद भी शामिल हैं, के साथ मारपीट कर सदन की गरिमा को तार-तार किया गया। राज्यसभा में हुई इस घटना के खिलाफ 15 दलों के विरोध मार्च की अगुआई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, जबरन बिल पारित कराने का विरोध कर रहे सांसदों को पीटा गया। सदन में बोलने से रोक कर लोकतंत्र की हत्या की गई। देश के 60 फीसद लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष की आवाज नहीं सुनी गई। इस आबादी के लिए संसद सत्र तो हुआ ही नहीं।

राज्यसभा में बुधवार शाम ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद बीमा विधेयक पारित कराने के दौरान हुए घमासान के खिलाफ आक्रोशित विपक्षी दलों ने संसद भवन में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और विजय चौक तक मार्च निकाला। राहुल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, पहली बार राज्यसभा में बाहर से बुलाए लोगों को नीली वर्दी में उतार कर सांसदों के साथ धक्का-मुक्की, मारपीट की गई। राहुल के मुताबिक, संसद में विपक्ष को बोलने से इसलिए रोका जा रहा है कि सरकार जिन दो-तीन उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रही है, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। इसीलिए किसानों, बेरोजगारी, इंश्योरेंस या पेगासस जैसे मुद्दों पर विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया गया और हमें सड़क पर आना पड़ा है। संसद के संग्राम को लेकर राज्यसभा के सभापति व लोकसभा अध्यक्ष के दुखी होने के प्रश्न पर राहुल ने कहा, उनकी जिम्मेदारी है सदन चलाने की और उन्होंने सदन क्यों नहीं चलाया?

ऐसा लगा मार्शल ला लगाकर पारित किया गया बीमा बिल पेज>>3

राहुल के बाद कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी ब्लाक

- महासचिवों के साथ 5,000 नेताओं, कार्यकर्ताओं के भी अकाउंट बंद
- विपक्षी पार्टी ने ट्विटर पर मोदी सरकार के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद ट्विटर ने पार्टी के आधिकारिक अकाउंट को भी ब्लाक कर दिया है। साथ ही बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ट्विटर हैंडल भी बंद कर दिया है। कुछ दिन पहले ही कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या की शिकार अनुसूचित जाति की नौ वर्षीय लड़की के परिवार की तस्वीर ट्वीट करने पर ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट ब्लाक कर दिया था।

कांग्रेस के इंटरनेट मीडिया विभाग प्रमुख रोहन गुप्ता ने कहा, ट्विटर ने पार्टी के आधिकारिक अकाउंट व 5,000 नेताओं व कार्यकर्ताओं के अकाउंट को ब्लाक कर दिया है। ट्विटर सरकार के दबाव में आकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ काम कर रही है। उसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष द्वारा साझा की गई वैसी ही तस्वीर को कुछ दिनों तक नहीं हटाया था।

कांग्रेस ने कहा, पार्टी महासचिवों-रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, लोस में पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के अकाउंट ब्लाक किए गए हैं। सुरजेवाला ने कहा, ट्विटर को धमकाकर नरेंद्र मोदी सरकार उनकी आवाज दबाने में कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा, आप पुलिस के इशारे पर ट्विटर को कितना डराएंगे? यह सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं है। यह अनुसूचित जाति की गरीब लड़की के लिए आवाज उठाने का मुद्दा भी है। जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिल जाता, हम आवाज उठाते रहेंगे।

कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सचिव प्रणव झा ने ट्वीट किया कि हर गलत काम के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या मोदी यह नहीं समझते हैं कि कालापानी के दिनों से कांग्रेस की संघर्ष करने की परंपरा रही है। हालांकि, देर रात उनका अकाउंट भी ब्लाक कर दिया गया।

ट्विटर ने कहा, नियमों के उल्लंघन के चलते बंद किए गए अकाउंट

ट्विटर ने कहा है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं के अकाउंट इस वजह से बंद किए गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी तस्वीर पोस्ट की थी, जिससे उसके नियमों का उल्लंघन हुआ था। यह कार्रवाई लोगों की निजता की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई। ट्विटर के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा, कंपनी के नियमों को सभी के लिए विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से लागू किया गया है। हमने उन सैकड़ों ट्वीट पर तत्परता के साथ कार्रवाई की है, जिनमें एक ऐसी तस्वीर डाली गई थी, जो हमारे नियमों का उल्लंघन करती है।

खर्च का हिसाब नहीं देने वाले पांच प्रत्याशी तीन साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

राज्य ब्यूरो, रांची

निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 में झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पांच प्रत्याशियों के अगले तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, क्योंकि उन्होंने चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं दिया। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कई अन्य प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की अर्हता समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

जिन लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है, उनमें मांडू क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सुंदर लाल मरांडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान) की प्रत्याशी बबीता देवी व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली सजदा खातून शामिल हैं। इनके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी रामलाल दिनकर व भानु राम भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आदेश पर झारखंड में जारी हुई अधिसूचनाएं

दरअसल, इन प्रत्याशियों ने चुनाव में खर्च का ब्योरा आयोग को नहीं सौंपा था। इस बारे में भेजे गए नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुशंसा पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इनके चुनाव लड़ने पर तीन साल के लिए रोक लगा दी।

हिंसा रोकने पर तालिबान को सत्ता में हिस्सेदारी का प्रस्ताव

- खुद राष्ट्रपति गनी ने की पेशकश, दोहा में वार्ताकारों को भेजा गया संदेश
- अफगानिस्तान में मारकाट जारी, कई और शहर सरकार के हाथ से निकले

काबुल, एएनआइ : अफगानिस्तान में मारकाट को रोकने के लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को सत्ता में भागीदारी का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अपना संदेश दोहा में वार्ताकारों तक पहुंचा दिया है। इस बीच गुरुवार को हेरात और गजनी जैसे शहरों पर तालिबान का कब्जा हो गया। दस प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुके तालिबान लड़ाके तेजी के साथ काबुल की ओर बढ़ रहे हैं। मीडिया आउटलेट एआरवाई न्यूज ने बताया कि गनी के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान सरकार ने सत्ता के बंटवारे के सौदे की पेशकश की जिसमें उसने तालिबान से नागरिकों पर हमले रोकने के लिए कहा है।

अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा, सरकार ने कतर के दोहा में चल रही बैठक के दौरान तालिबान के क्रूर हमलों पर गंभीर चिंता जताई। इन हिंसक घटनाओं के कारण देश में युद्ध अपराध, मानवाधिकारों का उल्लंघन व भारी तबाही हुई है। बैठक में अमेरिका, रूस, चीन व पाक शामिल थे। बैठक का उद्देश्य अंतर-अफगान शांति वार्ता को फिर सार्थक तरीके से शुरू करना था। (संबंधित खबरें-पेज-11 पर)

कतर की राजधानी दोहा में शांति वार्ता के बाद होटल से निकलते अफगान सरकार के वार्ताकार अब्दुल्ला-अब्दुल्ला (दाहिने से तीसरे)। एएफपी

हिंसाग्रस्त क्षेत्र से निकाले गए तीन भारतीय इंजीनियर

नई दिल्ली, प्रेट्र : काबुल में भारतीय दूतावास के अनुसार, अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त क्षेत्र से तीन भारतीय इंजीनियरों को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाला गया। दूतावास ने इंजीनियरों के बचाव का हवाला देते हुए नई सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। इसमें अफगानिस्तान में मौजूद सभी भारतीयों से एक बार फिर सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है। दूतावास ने बताया कि ये इंजीनियर एक बांध प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस इलाके पर सरकारी सुरक्षा कर्मियों का नियंत्रण नहीं है। इन्हें हवाई मार्ग से काबुल लाया गया। भारतीय दूतावास ने इससे पहले 29 जून, 24 जुलाई और 10 अगस्त को अलग-अलग एडवाइजरी जारी कर भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की है।

कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा नहीं देने पर हाई कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार

- फ्रंटलाइन वर्करों के अधिकारों को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश
- टीकाकरण शिविरों के बारे में भी अच्छी तरह से जागरूकता फैलाने को कहा

राज्य ब्यूरो कोलकाता

कोरोना से हुईं फ्रंटलाइन वर्करों की मौतों का सही आंकड़ा नहीं देने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाई है। इस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने फ्रंटलाइन वर्करों के अधिकारों को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा, टीकाकरण शिविरों के बारे में भी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए।

राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 बीमा के बारे में जनजागरूकता नहीं फैलाने समेत कई अन्य मामलों को लेकर दायर याचिकाओं पर खंडपीठ गुरुवार को सुनवाई कर रही थी। इस दौरान ममता सरकार ने कहा, राज्य में कोरोना से 180 फ्रंटलाइन वर्करों की ही मौत हुई है। अदालत ने इस पर आश्चर्य जताते हुए कहा, मृतकों का आंकड़ा इतना कम नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के प्रोपेगेंडा से किसी की मदद नहीं मिलेगी।

सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने का आरोप : याचिकाकर्ताओं ने कहा, कोविड-19 बीमा योजना व राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं के लिए तय शुल्क के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है। कई मामलों में अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई या जो संक्रमित हुए, उन्हें कई मामलों में मुआवजा नहीं मिला।

महाधिवक्ता ने दी यह दलील : सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा, राज्य की कोविड-19 बीमा योजना फ्रंटलाइन वर्करों के लिए लागू है। मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख रुपये और संक्रमित होने पर एक लाख रुपये दिए जाते हैं।

खंडपीठ ने दिया यह निर्देश पेज>>6

कक्षा में स्थापित नहीं हो सका इसरो का निगरानी उपग्रह

- क्रायोजेनिक इंजन में आई तकनीकी गड़बड़ी से विफल हुआ मिशन
- भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाना था स्वदेशी उपग्रह

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में गुरुवार को सेटेलाइट ईओएस-03 को लेकर राकेट जीएसएलवी-एफ10 ने उड़ान भरी। लेकिन पांच मिनट के बाद इंजन में आई तकनीकी गड़बड़ी से मिशन विफल हो गया। रायटर

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के भू-स्थिर कक्षा से पृथ्वी की निगरानी करने वाले पहले उपग्रह (सेटेलाइट) जीआइएसएटी-1 या ईओएस-03 की लांचिंग का मिशन गुरुवार को पूरा नहीं हो सका। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण के बाद जीएसएलवी-एफ10 राकेट ने दो चरण सफलतापूर्वक पूरे किए, लेकिन पांच मिनट के बाद क्रायोजेनिक इंजन के चरण में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। क्रायोजेनिक इंजन से आंकड़े मिलने बंद हो गए। इसके कुछ देर बाद इसरो ने मिशन पूरा नहीं होने की घोषणा कर दी।

सुबह 5.43 बजे भरी थी उड़ान : इसरो के अनुसार, 51.70 मीटर लंबे राकेट जीएसएलवी-एफ10 ने 26 घंटे की उलटी गिनती समाप्त होने के तुरंत बाद सुबह 5.43 बजे श्रीहरिकोटा के दूसरे लांच पैड (प्रक्षेपण स्थल) से सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। मिशन कंट्रोल सेंटर के वैज्ञानिकों ने बताया कि पहले और दूसरे चरण में राकेट का प्रदर्शन सामान्य रहा था। इसरो के चेयरमैन के. सिवन ने बताया, 'मिशन को पूरी तरह संपन्न नहीं किया सका क्योंकि क्रायोजेनिक चरण में एक तकनीकी विसंगति पाई गई।'

फरवरी में ब्राजील का सेटेलाइट किया था लांच : फरवरी में ब्राजील के भू-निगरानी उपग्रह एमेजोनिया-1 और 18 अन्य छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के बाद 2021 में इसरो का यह दूसरा मिशन था।

अंडमान सागर में गिरा सेटेलाइट : ईओएस-03 को भूमध्य रेखा पर करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाना था। भारतीय उपमहाद्वीप पर नजर रखने के लिए विज्ञानियों ने इस पर एक बड़ा टेलीस्कोप लगाया था। एक अमेरिकी खगोल विज्ञानी जोनाथन मैक्डोवेल ने बताया कि राकेट और सेटेलाइट संभवतः थाईलैंड के पश्चिम में अंडमान सागर में गिर गए।

फिर से तय किया जा सकता है प्रक्षेपण कार्यक्रम : जितेंद्र सिंह

2,268 किग्रा वजनी ईओएस-03 मिशन विफल रहने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्यमंत्री और अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा, 'इसरो अध्यक्ष डा. के. सिवन से बात की और विस्तार से चर्चा की। पहले दो चरण ठीक रहे, लेकिन उसके बाद क्रायोजेनिक अपर स्टेज में दिक्कत आ गई। मिशन का कार्यक्रम फिर से तय किया जा सकता है।'

कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान पेज>>5

राहत की बात

कुछ सालों में बच्चों की बीमारी बन कर रह जाएगा कोरोना

अमेरिका और नार्वे की संयुक्त टीम ने अपने अध्ययन में किया दावा, संक्रमण की चपेट में आने व टीकाकरण से मजबूत हो रहा इम्यून सिस्टम, 10 लाख लोगों की जान लेने वाला रूसी फ्लू अब शिशुओं की बीमारी बना

वाशिंगटन, प्रेट्र : दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना के अगले कुछ सालों में बच्चों की बीमारी बनकर रह जाने की संभावना है। गुरुवार को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कोरोना वायरस (सार्स-सीओवी-2) अगले कुछ वर्षों में अन्य सामान्य जुकाम वाले कोरोना वायरसों की तरह व्यवहार कर सकता है। यह ज्यादातर उन छोटे बच्चों को प्रभावित करेगा, जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है।

इस अध्ययन में शामिल अमेरिकी-नार्वेजियाई टीम ने देखा कि कोविड-19 की गंभीरता आमतौर पर बच्चों में कम होने के कारण इस बीमारी से खतरा कम होने की उम्मीद है। इस वायरस के नए-नए वैरियंट सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाले देशों में संक्रमण की रफ्तार को तेज कर रहे हैं।

नार्वे में ओस्लो विश्वविद्यालय के ओटार ब्योर्नस्टेड ने कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद तेजी से गंभीर परिणामों और उम्र के साथ घातक होने का स्पष्ट संकेत मिला है। फिर भी, हमारे माडलिंग परिणाम बताते हैं कि संक्रमण का खतरा बड़ों से बच्चों की तरफ शिफ्ट होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वयस्क आबादी ने या तो टीका लगवाकर या वायरस के संपर्क में आकर खुद के अंदर इम्युनिटी विकसित कर ली है।

साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि इस तरह के बदलाव अन्य कोरोना और इन्फ्लूएंजा वायरस में देखे गए क्योंकि वे भी ऐसे ही तेजी से फैले और बाद में पूरी दुनिया में थम गए। ब्योर्नस्टेड ने कहा, श्वसन रोगों के ऐतिहासिक रिकार्ड से संकेत मिलते हैं कि नई महामारी कुछ सालों बाद स्थानिक बीमारियों में बदल गई।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जीनोमिक अध्ययन से पता चलता है कि 1889-1890 एशियाटिक अथवा रूसी फ्लू के नाम से चर्चित महामारी ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को प्रभावित किया था। इस बीमारी से तब दस लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। यह बीमारी एचसीओवी-ओसी43 वायरस के कारण फैली थी। अब यह एक सामान्य बीमारी बन गई है और सात माह से 12 माह की उम्र के शिशुओं को ही होती है।

हालांकि ब्योर्नस्टैड ने आगाह किया कि अगर वयस्कों में सार्स-सीओवी-2 के फिर से संक्रमण के लिए प्रतिरक्षा कम रहती है, तो बीमारी का खतरा बना रह सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार वयस्क आबादी के कोरोना वायरस के संपर्क में ज्यादा आने से बीमारी की गंभीरता कम हो जाएगी।

उन्होंने कहा, लोगों में टीकाकरण से पैदा हुई इम्युनिटी, सार्स-सीओवी-2 के संपर्क में आकर पैदा हुई इम्युनिटी से बेहतर है। ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया कि लंबे समय तक चलने वाले इम्यून परिदृश्य में युवाओं में संक्रमण की उच्चतम दर की संभावना रहेगी क्योंकि उम्रदराज लोगों के पुराने संक्रमणों की चपेट में आकर नए संक्रमणों से निपटने में ज्यादा सक्षम होंगे।

अमेरिका के प्रिंसटन विवि में सहयोगी प्रोफेसर जेसिका मेटकाफ ने कहा, यह अनुमान तभी साकार हो सकता है जब दोबारा होने वाला संक्रमण केवल हल्की बीमारी पैदा करे। हालांकि उन्होंने यह भी हिदायत दी कि समय के साथ यदि प्राथमिक संक्रमण बुजुर्गों में पुनः संक्रमण होने से नहीं रोकता है या गंभीर बीमारी का खतरा कम नहीं करता तो मौत के आंकड़ों में बदलाव मुश्किल होगा।

कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी दिलाने की कोशिश जारी पेज>>6

49 नए मामले राजधानी में कोरोना के गुरुवार को मिले। संक्रमण दर 0.07 फीसद है। 41 मरीज ठीक हुए। लगातार दूसरे दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 13 अगस्त, 2021

न्यूज गैलरी

डीयू खोलने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय ने 16 अगस्त से विज्ञान वर्ग के छात्रों को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने व कक्षाएं चलाने संबंधी आदेश जारी किया तो छात्र खुश हो गए, लेकिन 24 घंटे से भी कम समय के अंदर डीयू ने आदेश वापस ले लिया। इसके बाद से ही छात्र संगठन नाराज हैं। स्टूडेंट फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआइ) के नेतृत्व में गुरुवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान माक कक्षाएं आयोजित की गईं। छात्रों ने कहा कि परिसर बंद होने की वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है। टीकाकरण की व्यवस्था कर परिसर खोलना चाहिए। (जासं)

रिश्वतखोरी में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक गिरफ्तार

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने सिविक सेंटर में स्थित शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र कुमार भदौरिया को उनके कार्यालय में छापा मार दो लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। कार्यालय में छापा मारने के बाद उसके आवास पर भी सीबीआइ ने छापेमारी की और वहां से काफी दस्तावेज बरामद किए। जब्त दस्तावेज की जांच की जा रही है। यह पहला मौका है जब सीबीआइ ने निगम के मुख्यालय में छापा मार किसी बड़े अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। (जासं)

फर्जी काल सेंटर का भंडाफोड़, नौ युवती समेत 16 गिरफ्तार

नई दिल्ली : उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस की साइबर सेल टीम व मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सुभाष प्लेस व मुखर्जी नगर थाना क्षेत्र में चल रहे दो फर्जी काल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। बेरोजगारों को फर्जी डिग्री दिलाकर विदेश भेजने के बहाने ठगने वाली नौ युवती समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने काल सेंटर से छह कंप्यूटर, दो लैपटाप, 12 मोबाइल बरामद किए हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपितों ने अभी तक कितने लोगों को ठगा है। (जासं)

तेज धूप कर रही परेशान, राहत के नहीं आसार

नई दिल्ली: बारिश थमने के बाद अब गर्मी बढ़ रही है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के पूर्वानुमान से इतर सुबह ही तेज धूप होती है। इसके कारण उमस बढ़ने लगती है। मौसम विभाग की मानें तो अभी कमोबेश सप्ताह भर तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 36.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 50 से 77 फीसद रहा। (राब्यू)

विदेश की तर्ज पर दिल्लीवासियों को अगले साल से जारी होगा हेल्थ कार्ड

समीक्षा ▶ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ योजना को लेकर की बैठक

कहा, सरकार लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अरविंद केजरीवाल। फाइल फोटो

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआइएमएस) योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि दिल्ली के लोगों को हेल्थ कार्ड व हेल्पलाइन जारी करने के लिए वेंडर चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसे लागू करने के लिए कैबिनेट में रखने की तैयारी चल रही है।

वहीं, बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि अगले साल की शुरुआत में यह योजना लागू कर दी जाएगी और हर व्यक्ति को क्यूआर कोड आधारित हेल्थ कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इससे विदेश की तर्ज पर दिल्लीवासियों के पास भी अपना हेल्थ कार्ड होगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि देश में यह अपनी तरह का इकलौता सिस्टम होगा। हेल्थ कार्ड में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को तय समय पर इस योजना का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हेल्थ कार्ड की शुरुआत होने पर लोगों को परेशानी मुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट नोट के मसौदे को स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी के बाद उस पर अंतर विभागीय विचार-विमर्श के लिए भेजा गया है। एचआइएमएस योजना के पहले चरण का कार्य साल के अंत कर पूरा कर लिया जाएगा। इसके तहत अगले तीन माह में काल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों की समस्या का निदान होगा।

अस्पताल में लाइनों में लगने से मिलेगी मुक्ति : योजना लागू होने पर मरीजों को अस्पतालों में लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। मरीज घर बैठे आनलाइन एप्वाइंटमेंट ले सकेंगे। वे निर्धारित समय पर जाकर ओपीडी में डाक्टर से परामर्श ले सकेंगे। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं में भी मदद मिलेगी।

हेल्थ कार्ड बनाने के लिए किया जाएगा सर्वे

लोगों को हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए अस्पतालों या दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए दिल्ली में सर्वे किया जाएगा। साथ ही अस्पतालों व अन्य निर्धारित स्थानों पर भी हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। इसके बाद घर-घर सत्यापन कर हेल्थ कार्ड वितरित किए जाएंगे। मतदाता पहचान पत्र व जनसंख्या रजिस्ट्री के आधार पर यह कार्ड जारी किया जाएगा। हेल्थ कार्ड का फायदा यह होगा कि एचआइएमएस से जुड़े किसी अस्पताल में इलाज कराया जा सकेगा। चरणबद्ध तरीके से इस योजना से निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जाएगा। इससे निजी अस्पतालों में भी इलाज कराना आसान हो जाएगा।

आक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में रार जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र
- उपमुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र दिल्ली सरकार की जांच समिति को मंजूरी दे
- बिना किसी जांच के आक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा बताना मुश्किल

दिल्ली में दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन की कमी से कोरोना के मरीजों की मौतों के मामले में रार जारी है। पहले मौतों के आंकड़े मांगने को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद हुआ है। अब दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा उपराज्यपाल के माध्यम से इस मामले में गठित समिति भंग करवा दिए जाने से जांच नहीं हो पा रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से भंग की गई समिति बहाल करने की मांग की है।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई या नहीं हुई, बिना कोई जांच करवाए इसकी पुष्टि करना मुश्किल होगा। इस बाबत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा। सिसोदिया ने पत्र में अपील की कि दिल्ली सरकार दिल्ली में आक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करना चाहती है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने हेल्थ-एक्सपर्ट्स की उच्च स्तरीय जांच समिति भी बनाई थी, जिसे उपराज्यपाल द्वारा खारिज कर दिया गया। यदि केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में आक्सीजन की कमी से हुई मौतों के सही आंकड़े सामने आएं तो दिल्ली सरकार द्वारा गठित समिति को मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि समिति की जांच के बाद ही दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी काम करती।

उपमुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर लिखे गए पत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में आक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, ये मानना गलत होगा। उन्होंने कहा कि हमें ये मानना होगा कि दिल्ली में आक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक लगभग 25 हजार लोगों की मौत हुई है। लेकिन, उनमें आक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुईं इसकी जानकारी नहीं है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केंद्र सरकार ने यह मानने से इन्कार कर दिया था कि देश में आक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। लेकिन, अदालत की फटकार के बाद अब राज्यों से आंकड़े मांग रही है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा नांगल राया और मयूर विहार दुष्कर्म मामले का केस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली पुलिस के साथ गृह मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में हुआ फैसला
- गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों मामलों की समीक्षा का दिया था निर्देश

दिल्ली के नांगल राया और मयूर विहार में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस 30 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करेगी। इसके साथ ही इन दोनों मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनिश्चित की जा सके। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के साथ इन दोनों मामलों की जांच की समीक्षा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया।

गृह मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय को इन दोनों मामलों की जांच की समीक्षा करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। उसके बाद गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारियों को तलब किया। समीक्षा बैठक में दिल्ली पुलिस ने एफआइआर दर्ज होने के 30 दिन के भीतर दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल करने का भरोसा दिया। ध्यान देने की बात है कि नांगल राया इलाके में बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है, वहीं मयूर विहार में बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है।

पुराना नांगल राया की मुख्य सड़क यातायात के लिए पूरी तरह खुली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में गुरुवार को धरना दे रहे लोगों को समझाने पुलिस उपायुक्त इंगित प्रताप सिंह स्वयं पहुंचे। उन्होंने लोगों से कहा कि वे पुलिस पर भरोसा करें, पुलिस अपना कार्य कर रही है। यदि किसी को पुलिस से कोई नाराजगी है तो उसे आपसी सामंजस्य से दूर किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि पुराना नांगल राया से गुजरने वाली मुख्य सड़क का जो हिस्सा यातायात के लिए बंद था, उसे भी यातायात के लिए खोल दिया गया। अब पुराना नांगल राया की मुख्य सड़क पूरी तरह यातायात के लिए खुल चुकी है।

बता दें, मुख्य सड़क पर जारी धरने को लेकर सेना ने धरना दे रहे लोगों को नोटिस भी जारी किया था, जिसमें 15 अगस्त को देखते हुए सड़क पर धरना को समाप्त करने का आग्रह किया गया था। यह कहा गया था कि इससे क्षेत्र की सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

सैन्य वाहनों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद सड़क के एक हिस्से को यातायात के लिए खोल दिया गया था।

इस बीच, त्रिलोकपुरी में दरिंदगी की शिकार हुई छह साल की मासूम बच्ची की हालत में सुधार होने पर गुरुवार को कोर्ट में उसके और उसकी मां के बयान दर्ज कराए गए। मासूम की कुछ जांचें होनी थीं, इसलिए उसे फिर से एम्स भेज दिया गया।

फर्जी पासपोर्ट वेबसाइट बनाकर ठगी, चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- गिरोह ने 15 हजार लोगों को साढ़े चार करोड़ रुपये का लगाया चूना

मध्य जिला पुलिस की साइबर सेल ने फर्जी पासपोर्ट वेबसाइट बनाकर करीब 15 हजार लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने अब तक साढ़े चार करोड़ रुपये की ठगी की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दरियागंज इलाके के रहने वाले मोहम्मद शोएब के पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो रही थी। उन्होंने गूगल से पासपोर्ट की वेबसाइट तलाशी और उस पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया तो उनसे फार्म भरवाकर बैंक खाते में तीन हजार रुपये जमा करवा लिए गए। काफी समय बीत जाने के बाद उन्होंने उक्त वेबसाइट पर दिए गए ई मेल आइडी पर संपर्क किया तो पता चला कि ई मेल फर्जी है। इस पर उन्होंने दरियागंज थाने में शिकायत दी थी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच साइबर सेल के एसआइ कमलेश व अली अकरम को सौंपी गई। पुलिस ने उक्त वेबसाइट की जांच की। इसके बाद पुलिस टीम ने एक आरोपित आलोक शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में आरोपित ने बताया कि उसके साथ भावनगर गुजरात निवासी विशाल शामिल है। फिर टीम ने उसे गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के बाद आरोपित अनुज और अंकुर को पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। अनुज और अंकुर सिम कार्ड विक्रेता हैं। ये सिम लेने वाले लोगों से दो बार फिंगर प्रिंट लेकर सिम अपने लिए एक्टिव करा लेते थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह गिरोह दो साल से ठगी कर रहा था। इन्होंने करीब 15 हजार लोगों से ठगी की थी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठगी की रकम कम रहती है इसलिए पीड़ित पुलिस से शिकायत नहीं करते थे। जांच में पता चला है कि आरोपितों के फर्जी वेबसाइट पर 20 हजार से अधिक लोगों ने खुद को पंजीकृत किया हुआ है।

विशाल और आलोक ने बनाई थी फर्जी वेबसाइट

जांच में पता चला है कि विशाल और आलोक ने ही फर्जी वेबसाइट बनाया था। और वही उसका संचालन कर रहे थे। आरोपित विशाल आइटी से बीटेक है। वहीं आलोक ने इलेक्ट्रानिक्स में डिप्लोमा किया हुआ है।

'एसएमए के तहत शादी करने वालों के घर नोटिस भेजना कोर्ट की अवमानना'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अदालत के आदेश के बावजूद विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत शादी करने वाले व्यक्ति के घर पर नोटिस भेजने के मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करके सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना की है। अंतर-धार्मिक दंपती की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने एसडीएम को नोटिस जारी कर पूछा है कि न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। मामले में अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी।

पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर कोई युगल एसएमए के तहत शादी पंजीकृत कराना चाहता है तो उसके आवास पर नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इस तरह के नोटिस पर रोक लगाई गई है जो कि आवेदकों की योजनाओं को खतरे में डाले या उनके जीवन के लिए खतरा बन जाए। पीठ ने अप्रैल 2009 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया। इसके तहत एसएमए के तहत शादी करने के इच्छुक आवेदकों के घर पर नोटिस भेजने के बजाय उसे नोटिस जारीकर्ता को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ही प्रदर्शित करने का आदेश दिया था।

दूसरी मंजिल पर छिपे बदमाश घंटों बाद मुठभेड़ में हुए ढेर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- खजूरी खास की श्रीराम कालोनी में हुई वारदात, दो कांस्टेबल भी घायल

राजधानी के खजूरी खास इलाके में तीन मंजिला मकान में छिप कर बैठे दो कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारे गए बदमाशों की पहचान लोनी निवासी आमिर खान और वजीराबाद औद्योगिक क्षेत्र निवासी राजमन के रूप में हुई है। उनके कमरे से दो आटोमैटिक पिस्तौल, चार मैगजीन, 60 कारतूस और डेढ़ लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। इस दौरान बदमाशों की गोली लगने से दो पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। उनको जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उत्तर पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सेन ने बताया कि बुधवार रात करीब 11:30 बजे खजूरी खास थाने के एसएचओ को बेगमपुर थाना प्रभारी ने श्रीराम कालोनी में बदमाशों के छिपे होने की जानकारी दी। इस पर एसएचओ पवन कुमार के नेतृत्व में खजूरी खास और बेगमपुर थाने की टीम ने श्रीराम कालोनी में गली नंबर-नौ स्थित मकान नंबर सी-216 को घेर लिया। इसके मालिक जालंधर प्रसाद गुप्ता ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में दो बदमाशों के होने की पुष्टि की। बताया कि मकान में 18 परिवार किराये पर रहते हैं। ऐसे में करीब दो घंटे तक पुलिस बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए समझाती रही, लेकिन बदमाश नहीं माने। यही नहीं, बदमाश गोला बारूद से मकान को उड़ाने की धमकी देने लगे। बदमाशों को आक्रामक होता देख पुलिस ने बगल वाले कमरे की खिड़की से उनके कमरे में झांका। देखा कि दोनों बदमाशों ने अपनी कनपटी पर पिस्तौल लगा रखी थी।

बदमाशों ने जब खिड़की से झांकते पुलिसकर्मियों को देखा तो गोली चला दी। इससे बगल के कमरे में मौजूद एक बच्चा बाल-बाल बच गया। दोनों तरफ से 30 से 35 राउंड गोलियां चलीं। इसके बाद तड़के करीब तीन बजे दोनों बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया।

अल्पसंख्यक आयोग के खाली पदों को 30 सितंबर तक भरें : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के खाली पदों पर व्यक्तियों को नामित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक का समय दिया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि इससे पहले केंद्र सरकार को 31 जुलाई तक खाली पदों को भरने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने गुरुवार को यह आदेश तब दिया जब केंद्र सरकार ने पदों को भरने के लिए तीन माह का समय और देने का अनुरोध किया। अदालत ने 23 अप्रैल को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि खाली पदों पर व्यक्तियों को 31 जुलाई तक नामित किया जाए। पीठ ने कहा कि उक्त नियुक्तियां की जाएं ताकि आयोग का कुशलतापूर्वक कार्य करना सुनिश्चित किया जा सके। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।

याचिकाकर्ता अभय तन बौद्ध के वकील ने कहा कि अगर खाली पदों को भरने के लिए केंद्र को उचित समय सीमा विस्तार दिया जाता है तो वे विरोध नहीं करेंगे।

मानवाधिकार सबका हक, चाहे दलित हो या महिला : रामदास आठवले

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (आरपीआइ) के अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि मानवाधिकार सबका हक है। चाहे वह दलित हो या महिला। अब माहौल बदल रहा है, हालांकि कुछ लोग हैं, जो अहंकार के कारण दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। वह कांस्टीट्यूशनक्लब में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन (एनएचआरओ) द्वारा आयोजित आजाद भारत कान्क्लेव को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि दलित समुदाय में पढ़ाई को लेकर गंभीरता आई है। कई युवा पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने के बढ़ते मामलों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके मंत्रालय द्वारा 100 युवाओं की विदेश में पढ़ाई का खर्च उठाया जाता है, जबकि आवेदन 200-300 आ रहे हैं।

कांस्टीट्यूशन क्लब में एनएचआरओ द्वारा आयोजित आजाद भारत कान्क्लेव को संबोधित करते केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले। जागरण

एनएचआरओ के अध्यक्ष रवि जायसवाल ने कहा कि देश का सर्वांगीण विकास तभी होगा, जब देश में किसी के अधिकार नहीं मारे जाएंगे। इसके लिए हम सभी को साथ आना होगा। जैसे कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा समाज साथ आया। कान्क्लेव में कई अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखें।

कांग्रेस के एससी विभाग के धरना में शामिल हुए राहुल गांधी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: रायसीना मार्ग स्थित युवा कांग्रेस के मुख्यालय के नजदीक अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के एससी विभाग द्वारा आयोजित धरना-प्रदर्शन में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।

राहुल ने कहा कि संसद में विपक्षी दलों को लोगों के हक में आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन, पूरे देश में गरीब, दलित, महिला, किसान और मजदूरों की आवाज बढ़ रही है। यह आवाज एक दिन तूफान बन जाएगी जो केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब व महात्मा गांधी ने इस देश को एक बात सिखाई है कि डरो मत। जिस दिन हिंदुस्तान डरना बंद कर देगा, ये (मोदी सरकार) भाग जाएंगे।

एनईपी लागू करने की कवायद

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा डीयू

रोडमैप तैयार करने के लिए नौ सदस्यीय समिति गठित, आगामी सत्र से दाखिला प्रक्रिया में भी होगा बदलाव

संजीव कुमार मिश्र, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष भी पूर्व की भांति मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जा रहा है, लेकिन आगामी सत्र से डीयू दाखिला प्रक्रिया में बदलाव दिखाई देगा। दाखिले संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा (सीयूसेट) से होंगे तो नई शिक्षा नीति (एनईपी) की छाप विभिन्न पाठ्यक्रमों पर दिखेगी। हालांकि एनईपी लागू करने से पहले डीयू डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) विकसित करेगा। इसके लिए रोडमैप तैयार करने के लिए नौ सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति डीयू कैंपस और कालेजों में एक समान डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाएगा।

विस्तृत कार्ययोजना के लिए समिति गठित: दिल्ली यूनिवर्सिटी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फार कालेज एंड डिपार्टमेंट नाम से समिति बनाई गई है। समिति में शामिल कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रो. संजीव सिंह ने बताया कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह समिति कालेज और विभाग के बीच सेतु की तरह काम करेगी। डीयू और कालेजों में अभी डिजिटल बुनियादी ढांचा अलग हैं। साफ्टवेयर के स्तर पर भी भिन्नता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि शिक्षकों को अलग-अलग साफ्टवेयर के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। ऐसे में एक समान व्यवस्था होगी तो आसानी होगी। नई शिक्षा नीति में भी आनलाइन पाठ्यक्रमों एवं क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था है। इसके लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा, ताकि आनलाइन पढ़ाई संभव हो सके। यह समिति इस दिशा में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगी।

बनाए जाएंगे स्टूडियो : प्रारंभिक चरण में डीयू के 15 कालेजों में स्टूडियो बनाए जाएंगे। कालेज कमरा उपलब्ध कराएंगे। डीयू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेटअप तैयार करेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय। फाइल फोटो

बनाई जाएगी वीडियो लाइब्रेरी

डिजिटल बुनियादी ढांचे में वीडियो लाइब्रेरी अहम होगी। चूंकि डीयू के अधिकतर छात्र स्मार्टफोन धारक हैं। इसलिए डीयू वीडियो लाइब्रेरी बनाएगा, ताकि पढ़ाई क्लास रूम की मोहताज न रहे। छात्र जब चाहेगा, पाठ्यक्रम संबंधी वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकेगा। वन डीयू प्रोग्राम के तहत शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी में पाठ्यक्रम का वीडियो रिकार्ड करेंगे। कक्षा में पढ़ाई के माफिक ही हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो होगा। इसके लिए अलग वेबसाइट भी बनाई जाएगी, जहां पाठ्यक्रमों की सूची होगी। जिस पर क्लिक करते ही पाठ्यक्रम संबंधित सभी वीडियो और उनका विवरण एक अलग पेज पर खुलेगा। छात्र जिस चैप्टर को चाहेगा देख सकेगा।

गर्भवती के पैंक्रियाज कैंसर की सर्जरी कर बचाईं दो जिंदगियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अफगानिस्तान से इलाज के लिए दिल्ली पहुंची फाहिमा नामक छह माह की गर्भवती महिला के पैंक्रियाज कैंसर की चार घंटे में सर्जरी कर डाक्टरों ने दो जिंदगियां बचा ली हैं। वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल के डाक्टरों ने एक अगस्त को यह सर्जरी की थी। सर्जरी के बाद महिला के स्वास्थ्य में सुधार है और गर्भस्थ शिशु भी ठीक है। डाक्टरों का दावा है कि पहली बार गर्भवती महिला की इस तरह की सर्जरी हुई है।

अस्पताल के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आंकोलाजी विभाग के विशेषज्ञ डा. अमित जावेद ने कहा कि गर्भावस्था के करीब पांचवें महीने में महिला को पता चला कि उन्हें पैंक्रियाज का कैंसर है। वह जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंची तब गर्भावस्था के करीब छह माह हो चुके थे। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में सर्जरी करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन छह माह की गर्भवती की सर्जरी करना जोखिम भरा होता है। समस्या यह थी कि सर्जरी के लिए प्रसव का इंतजार करने पर कैंसर ज्यादा फैल सकता था। ऐसे में मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता था।

इसलिए सर्जरी करने का फैसला किया गया। गर्भावस्था के कारण यूट्रस भी बढ़कर पैंक्रियाज तक पहुंच चुका था। इससे सर्जरी में इस बात का ध्यान रखना था कि गर्भस्थ शिशु को नुकसान न होने पाए। इसलिए यह सर्जरी बेहद चुनौतीपूर्ण थी। हालांकि, भ्रूण को हिलाए बिना यह सर्जरी की गई। सर्जरी के दौरान पैंक्रियाज के प्रभावित हिस्से, गाल ब्लाडर, छोटी आंत सहित पेट के हिस्से को निकालना पड़ा।

49 स्टेशनों के पुनर्विकास की जिम्मेदारी रेलवे ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को सौंपी है। इनमें मथुरा, आगरा फोर्ट, कुरुक्षेत्र, अमरावती, राजकोट व भोपाल आदि शामिल हैं।

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए दोगुनी हुई ऋण सीमा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पीएम से बातचीत

- महिला उद्यमियों के लिए जारी की 1,600 करोड़ से अधिक धनराशि
- कहा, छह-सात वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या तीन गुना बढ़ी

नई दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 'आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद' कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल और पशुपति कुमार पारस भी मौजूद रहे। प्रेट्र

महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा को सरकार ने बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। महिला स्वयं सहायता समूहों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि पिछले छह-सात वर्षों के भीतर ही देश में ऐसे समूहों की संख्या में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। महिला उद्यमियों के लिए 1,600 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह को अब तक जहां 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलता था, उसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं की उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लाखों महिला उद्यमियों को बिना गारंटी का आसान ऋण उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा वित्तीय मदद दी जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का बिना गारंटी वाला ऋण दिया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत में बने खिलौनों को भी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए हरसंभव मदद भी दी जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों की बहनें तो पारंपरिक रूप से इससे जुड़ी हैं। इसमें भी स्वयं सहायता समूहों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए स्वयं सहायता समूहों की दोहरी भूमिका पर मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता बढ़ानी है और इसके विकल्प के लिए भी काम करना है। महिला स्वयं सहायता समूहों के पिछले सात वर्षों के दौरान बैंकों को ऋण वापसी में शानदार प्रदर्शन को प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज जी बता रहे थे कि पहले नौ फीसद तक कर्ज फंस जाता था, वह घटकर अब दो-ढाई फीसद रह गया है। उन्होंने महिला उद्यमियों से कहा कि कृषि और कृषि आधारित उद्योग ऐसा क्षेत्र है जहां महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अनंत संभावनाएं हैं। वे सीधे किसानों के खेतों से उपज को खरीदकर बाजार में अपनी पैकिंग के साथ बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने महिला समूहों से कहा कि वे आजादी के 75वें साल में कम से कम 75 घंटे इस 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक कोई सामाजिक जागरूकता वाला कार्य करें। इसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है। लोगों को बीमारियों के प्रति सचेत करने और कुपोषण से बचाने के उपायों जैसी जानकारी गांव अथवा अपने मुहल्ले के लोगों को दी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों की महिला उद्यमियों से उनकी उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा की।

बुंदेलखंड वीरांगनाओं की धरती

जागरण संवाददाता, हमीरपुर

आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उप्र के बुंदेलखंड के पांच जिलों में संचालित बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की डायरेक्टर हमीरपुर के बांकी गांव निवासी उमाकांती से झांसी में वर्चुअल संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड वीरांगनाओं की धरती है। आप सबका काम सराहनीय है। इस मौके पर हमीरपुर के ही कुंडौरा निवासी अंजनी देवी भी मौजूद रहीं। हालांकि, उनसे संवाद नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री और उमाकांती के बीच संवाद के अंश

प्रधानमंत्री : नमस्ते उमाकांती जी।

उमाकांती : प्रधानमंत्री जी, मैं बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की डायरेक्टर हूं। इसके माध्यम से बुंदेलखंड के पांच जिलों के 601 गांवों की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 25 हजार महिलाएं दुग्ध उत्पादन का काम कर रहीं हैं। प्रतिदिन 70 हजार लीटर दूध एकत्र कर मदर डेयरी भेजती हैं। दो वर्ष में कंपनी ने 110 करोड़ रुपये का काम किया।

प्रधानमंत्री : आप अपनी कंपनी में जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की बहनों को भुगतान कैसे करती हैं।

उमाकांती : पर्ची मिलती है मशीन से, फैट के साथ उसमें ब्योरा होता है। सखी का कोड, रुपये, डेट आदि सब दर्ज होता है। फिर उनके खाते में माह की तीन, 13 व 23 तारीख को भुगतान भेजा जाता है। इससे कारोबार बढ़िया चलता है।

प्रधानमंत्री : आपका उत्साह इतना है कि आपके आशीर्वाद के लिए आभार, मैं एक काम और बताता हूं। खादी मिशन द्वारा बाक्स दिए जाते हैं, जिससे बहनों को शहद उत्पादन का काम भी कराया जा सकता है। उसे कोई ब्रांड का नाम दे अच्छा शहद उपलब्ध करा सकती हैं।

उमाकांती : जी प्रधानमंत्री जी, हम सब बहनें इसके लिए हिम्मत के साथ तैयार हैं।

ग्रोथ सेंटर से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर : प्रधानमंत्री

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद' कार्यक्रम के तहत बेकरी ग्रोथ सेंटर संचालिका चंद्रमणि दास से छह मिनट बात की। कहा कि यह स्वयं सहायता समूह महिलाओं के उत्थान में कारगर साबित होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2020 में रुद्रपुर में बेकरी ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ हुआ था। प्रदेश में यह सेंटर नंबर वन पर है। सेंटर की संचालक नारी शक्ति समूह की अध्यक्ष चंद्रमणि दास से पीएम ने उपलब्धि के बारे में पूछा। चंद्रमणि ने बताया कि सेंटर में 35 महिलाएं काम कर रही हैं। अब तक कुल 89 लाख रुपये का टर्नओवर हो चुका है। इसमें से सभी महिलाओं को साढ़े सात हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने के बाद 10,30,000 रुपये का शुद्ध लाभ आठ माह में हुआ है। पीएम ने मडुए व सोयाबीन से बने बिस्किट के बारे में भी पूछा। सेंटर को सरकार से मिली मदद, इस कार्य से अब तक अपने व गांव के आसपास की बहनों के जीवन में परिवर्तन के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने चंद्रमणि से कहा कि आप महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। गांव व आसपास की अन्य महिलाओं को भी इसी तरह आत्मनिर्भर बनाएं।

नायडू और बिरला ने संसद में कुछ सदस्यों के व्यवहार पर चिंता जताई

नई दिल्ली, प्रेट्र : उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को हाल में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान कुछ सांसदों के व्यवहार पर चिंता जताई। कहा कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के एक दिन बाद बिरला ने नायडू से मुलाकात की और दोनों ने सत्र के दौरान संसद में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ट्वीट किया कि दोनों ने कुछ सांसदों के कामकाज में बाधा डालने वाले बर्ताव पर गहन चिंता प्रकट की। ट्वीट में कहा गया, उनका मानना है कि ऐसे नियम विरुद्ध व्यवहार को सहा नहीं जाना चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी ने यहां उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। नायडू ने सदन में अप्रिय स्थिति बनने पर बुधवार को रुंधे गले से विपक्ष के कुछ सदस्यों के कृत्य की तुलना लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किए जाने से की।

विपक्ष को गोलबंद करेंगी सोनिया गांधी

कवायद ▶ कांग्रेस अध्यक्ष ने 20 अगस्त को बुलाई वर्चुअल बैठक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विपक्षी सियासत की कमान कांग्रेस के ही हाथ में रहे यह सुनिश्चित करने की कोशिश के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को मजबूत करने के साथ ही एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लंबी सियासी जंग की साझी रणनीति पर बातचीत की संभावना है। विपक्षी गोलबंदी की इस पहल के लिए कांग्रेस नेतृत्व की तत्परता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से लेकर एमके स्टालिन तक को खुद फोन करके इस बैठक के लिए न्योता दिया।

यह बैठक वर्चुअल होगी। संकेत हैं कि इस दौरान सियासी मुद्दों पर चर्चा के साथ ही विपक्षी दिग्गजों के एक मंच पर जल्द ही इकट्ठा होने की तारीख भी तय होगी। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व ने विपक्षी नेताओं को 23 से 25 अगस्त के बीच भोज पर चर्चा के लिए आमंत्रित करने का योजना बनाई थी, लेकिन कुछ नेताओं की उपलब्धता की व्यहारिक दिक्कतों को देखते हुए लंच या डिनर पर

सोनिया गांधी ने संभाली कमान। फाइल

बैठक की जगह वर्चुअल बैठक बुलाने पर सहमति बनी। समझा जाता है कि सोनिया ने इस पहल के तहत सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को फोन कर न्योता दिया। इसके बाद राकांपा प्रमुख शरद पवार, द्रमुक प्रमुख व तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से उनकी बात हुई। सोनिया ने शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को भी विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रास में शिवसेना के नेता संजय राउत ने इसकी पुष्टि की कि सोनिया ने उद्धव से बात करके उन्हें विपक्षी नेताओं की बैठक में आमंत्रित किया है। ठाकरे इस वर्चुअल बैठक में शिरकत भी करेंगे। समाजवादी पार्टी को भी इस बैठक का न्योता भेजा गया है, मगर बसपा को आमंत्रण पर कांग्रेस की ओर से अभी तस्वीर साफ नहीं की गई है।

विपक्ष के एकजुट होने से संसद के मानसून सत्र में सरकार को मिली चुनौती जहां विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाने की एक प्रमुख वजह है। वहीं, 2024 में पीएम मोदी को सियासी चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों का मजबूत विकल्प बनाने की विपक्ष के अंदर से उठ रही आवाजों को देखते हुए भी कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बढ़ रहा है। खासकर कांग्रेस के ही असंतुष्ट जी-23 के एक प्रमुख नेता कपिल सिब्बल के रात्रिभोज पर जुटे विपक्षी दिग्गजों के बीच अगले आम चुनाव में विपक्ष के मजबूत विकल्प के स्वरूप को लेकर जिस तरह शुरुआती चर्चाएं हुईं, उससे भी हाईकमान पर दबाव बढ़ा है। सोनिया के विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाने की यह ताजा पहल काफी हद तक सिब्बल के रात्रिभोज में हुए जुटान से बढ़े सियासी दबाव का भी असर है। वैसे ममता ने दो हफ्ते पहले दिल्ली आकर जिस तरह विपक्षी नेताओं के साथ 2024 में एकजुटता को लेकर चर्चा की पहल शुरू की, वह भी कांग्रेस के लिए चुनौती है और पार्टी इसे भली-भांति समझ रही है।

ऐसा लगा, मार्शल ला लगाकर पारित किया गया बीमा बिल

राज्यसभा में बीमा विधेयक पारित कराए जाने के दौरान हुए घमासान के विरोध में गुरुवार को नई दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं ने सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू को ज्ञापन सौंपा। एएनआइ

प्रथम पृष्ठ से आगे

विपक्षी मार्च में शामिल शिवसेना नेता संजय राउत और राजद नेता मनोज झा ने कहा कि बीमा बिल को मार्शल के सहारे नहीं, ऐसा लगा कि मार्शल ला लगाकर पारित किया गया। राउत ने कहा कि मार्शल की पोशाक में बाहर के लोगों ने महिला सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मार्शलों को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि सदन नहीं वे पाकिस्तान बार्डर पर खड़े हैं। सपा, माकपा, भाकपा, आरएसपी, द्रमुक, राकांपा, आइयूएमएल आदि के नेताओं ने भी विपक्षी सांसदों के साथ मारपीट को अभूतपूर्व और शर्मनाक बताते हुए सरकार के रवैये की निंदा की।

विपक्षी नेताओं ने नायडू से मिलकर की **कार्रवाई की मांग :** विपक्षी नेता विरोध मार्च के बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिले और मारपीट की घटना के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। नायडू से मिलने गए विपक्षी नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राकांपा नेता शरद पवार भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि सरकार संसदीय जवाबदेही में विश्वास नहीं रखती और उसने अपने अहंकार और घमंड में विपक्षी दलों की चर्चा की मांग नहीं सुनी।

टकराव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया : मानसून सत्र के टकराव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्ष ने कहा है कि अपने करनी पर पर्दा डालने के लिए सरकार विपक्ष को बदनाम करने का दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रही है।

औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं 15 करोड़ बच्चे और युवा : प्रधान

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि करीब 15 करोड़ बच्चे व युवा देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं और लगभग 25 करोड़ आबादी साक्षरता की बुनियादी परिभाषा के नीचे है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) द्वारा 'रोजगार सृजन एवं उद्यमिता' विषय पर आयोजित एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा, 'अगर हम तीन से 22 वर्ष के बीच की उम्र के बच्चों और युवाओं की संख्या पर गौर करें जो सरकारी, निजी एवं धर्मार्थ स्कूलों; आंगनबाड़ियों; उच्च शिक्षण संस्थानों और कौशल विकास की पूरी व्यवस्था में पंजीकृत हैं तो उनकी कुल संख्या करीब 35 करोड़ है जबकि इस उम्र समूह के लोगों की आबादी लगभग 50 करोड़ है। इसका मतलब है कि कम से कम 15 करोड़ बच्चे एवं युवा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं। हम उन्हें शिक्षा व्यवस्था में लाना चाहते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादक कार्यबल सुनिश्चित करना जरूरी है।' प्रधान ने कहा कि आजादी के बाद कराई गई जनगणनना में यह पाया गया कि आबादी का 19 प्रतिशत हिस्सा साक्षर है। आजादी के 75 वर्ष बाद देश में साक्षरता दर 80 प्रतिशत पहुंच गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि 20 प्रतिशत आबादी या करीब 25 करोड़ लोग साक्षरता की बुनियादी परिभाषा के नीचे है।

सराहनीय कार्य करने वाले युवाओं और संगठनों को दिया गया पुरस्कार

नई दिल्ली, एएनआइ : युवा मामलों और खेल मंत्रालय की ओर से गुरुवार को 2017-18 और 2018-19 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये पुरस्कार दिए।

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2021 के मौके पर आयोजित इस समारोह में कृषि आधारित उद्यमों से जुड़ी युवाओं की दस टीमों और सामाजिक उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहे युवाओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की ओर घोषित अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कैलेंडर में दर्ज एक तिथि नहीं है, यह भारत के युवाओं को उनकी मेधा के लिए सम्मानित करने का दिन है। यह उन युवाओं के कार्यों को सम्मानित करने और सराहे जाने का दिन है जो भारत के भविष्य हैं। यह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में किए गए प्रयासों की प्रशंसा का दिन है। ठाकुर ने कहा, इस बार के अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस का विषय खाद्य व्यवस्था में बदलाव का है। युवा इस बदलाव को नई दिशा दे सकते हैं। तकनीक आधारित कृषि के जरिये युवा

नई दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुग्राम की देविका मलिक को पुरस्कार प्रदान किया। प्रेट्र

सफलता की नई कहानी लिख सकते हैं। समारोह में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार व्यक्तिगत तौर पर और संगठनों को दिए गए हैं। 2017-18 के लिए कुल 14 पुरस्कार दिए गए। इसमें से दस पुरस्कार व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए और चार संगठनों के उल्लेखनीय प्रदर्शनों के लिए दिए गए हैं। जबकि आठ पुरस्कार 2018-19 के लिए दिए गए। उनमें सात व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए और एक संगठन के प्रदर्शन के लिए दिया गया। व्यक्तिगत तौर पर पुरस्कार में पदक, प्रमाण पत्र और एक लाख रुपये नकद दिए गए। जबकि संगठन को पदक और प्रमाण पत्र के साथ तीन लाख रुपये की धनराशि नकद रूप में दी गई। समारोह में युवा मामलों के मंत्रालय की सचिव ऊषा शर्मा और संयुक्त सचिव असित सिंह भी मौजूद थे।

पेगासस पर बंगाल के जांच आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : पेगासस जासूसी मामले की पड़ताल के लिए बंगाल सरकार द्वारा गठित जांच आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और बंगाल सरकार के 27 जुलाई के नोटिफिकेशन को रद करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो आयोग का गठन क्यों किया गया? इसमें आयोग की जांच पर रोक की मांग भी की गई है।

बंगाल सरकार ने 27 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर व कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मयी भट्टाचार्य इसके सदस्य हैं। इस जांच आयोग में शामिल दोनों पूर्व जज बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकार्डिंग के आरोपों की जांच करेंगे। इधर, सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की एसआइटी जांच को लेकर दस याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों पर खास फोकस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- इनमें समग्र शिक्षा सहित शिक्षा मंत्रालय की अन्य योजनाओं को प्रमुखता से किया जाएगा लागू
- यूजीसी ने देश के 374 जिलों को किया है चिह्नित, इनमें उत्तर प्रदेश के भी 41 जिले हैं शामिल

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अमल के साथ सरकार का फोकस देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े उन 374 जिलों पर भी है, जहां मौजूदा समय में उच्च शिक्षा के साथ स्कूली शिक्षा का भी सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय इन जिलों में राज्यों के साथ मिलकर विशेष मुहिम शुरू करने की तैयारी में जुटा है। इस दौरान इन सभी जिलों में समग्र शिक्षा सहित उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। साथ ही इन जिलों को शैक्षिक पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाने की समयसीमा भी तय की जाएगी।

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों को चिह्नित करने का यह काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने किया है। इन जिलों को जिन प्रमुख मानकों के आधार पर चुना गया है उनमें सकल नामांकन दर का राष्ट्रीय औसत से कम होना, जिले की 18 से 23 वर्ष की कुल जनसंख्या में महाविद्यालयों का अनुपात

शिक्षा मंत्रालय की मुहिम। फाइल/इंटरनेट मीडिया

और प्रति महाविद्यालय के औसत नामांकन शामिल हैं। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश के 41 जिले शामिल हैं। वहीं बिहार के 25 जिले, मध्य प्रदेश के 39 जिले, पंजाब के 13 जिले और झारखंड के 12 जिले शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े इन सभी जिलों के लिए जल्द ही राज्यों के साथ मिलकर मंत्रालय अभियान शुरू करने की तैयारी में है। वैसे भी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों में शैक्षणिक सुधार व बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का काम चल रहा है, ऐसे में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों पर विशेष फोकस रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक, इस मुहिम को भी आकांक्षी (विकास की दौड़ में पिछड़े) जिलों के पैटर्न पर शुरू करने की तैयारी है। जहां इसके अमल पर केंद्र पैनी नजर रखेगा। साथ ही इन सभी जिलों में नए डिग्री कालेजों को खोलने की पहल की जा सकती है। वैसे भी शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले चिह्नित होने के बाद सरकार ने इनमें से 194 जिलों में माडल डिग्री कालेजों को खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से 64 जिलों में यह कालेज यूजीसी द्वारा और 130 जिलों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत किए गए हैं। मंत्रालय की कोशिश है कि इन कालेजों में जल्द ही पढ़ाई शुरू की जाए। स्कूली शिक्षा से जुड़ी समग्र शिक्षा योजना के नए चरण में इन जिलों पर फोकस करने की तैयारी है।

साफगोई

सीजेआइ एनवी रमना ने कहा, सीमित संसाधनों के बीच करते हैं अथक परिश्रम, जस्टिस आरएफ नरीमन को समारोह पूर्वक दी गई विदाई

'न्यायाधीशों के बारे में गलत धारणाओं को खत्म करना जरूरी'

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) एनवी रमना ने गुरुवार को कहा कि लोगों की इस गलत धारणा को खत्म करने की जरूरत है कि न्यायाधीशों का जीवन बहुत आसान होता है। न्यायाधीश बनने में जाहिर तौर पर सबसे बड़ा त्याग आर्थिक रूप से होता है, लेकिन इस तरह के फैसले में जनसेवा की भावना होती है।

जस्टिस आरएफ नरीमन की सेवानिवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने कहा, 'लोगों में यह गलत धारणा होती है कि न्यायाधीश बड़े बंगले में रहते हैं। सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक काम करते हैं और छुट्टियों का आनंद उठाते हैं। यह असत्य है। एक सप्ताह में 100 से अधिक मामलों के लिए तैयारी करना, दलीलों पर सुनवाई करना तथा प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निष्पादन आसान नहीं है। हम देर रात तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। छुट्टियों में भी काम करते हैं। इसलिए, न्यायाधीशों के बारे में गलत धारणाओं को सहना मुश्किल होता है। हम अपना बचाव नहीं कर सकते। बार की जिम्मेदारी है कि इन गलत बातों को खारिज करे और लोगों को सीमित संसाधनों के साथ न्यायाधीशों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताए।'

सीजेआइ एनवी रमना। जागरण आर्काइव

न्यायपालिका में नियुक्ति में योग्यता हो सर्वोपरि : नरीमन

जस्टिस नरीमन ने कहा, 'मेरा मानना है कि शीर्ष अदालत से न्याय की अपेक्षा रखना लोगों का हक है। लोग यहां इस अपेक्षा के साथ आते हैं कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण न्याय मिलेगा। इसलिए, अन्य पहलुओं के बजाय योग्यता ही सर्वोपरि हो। यह समय है कि इस पीठ में और अधिक सीधी पदोन्नतियां हों। जिन्हें सीधी नियुक्ति का अवसर मिले वे इन्कार न करें। उनकी जिम्मेदारी है कि इस पेशे से जितना मिला है, उसे लौटाएं।' उन्होंने अपने अनुभवों का हवाला देते हुए कहा, 'न्यायाधीश होना वकील होने से ज्यादा कठिन है। आपको बहुत पढ़ना होता है। मैंने फैसले लिखने का आनंद उठाया और अंत में सबकुछ ठीक रहा।' अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल व बार अध्यक्ष विकास सिंह ने भी विचार रखे।

'न्यायिक संस्था की रक्षा करने वाले एक शेर को खो रहा हूं'

सुप्रीम कोर्ट में दोपहर की रस्मी सुनवाई के लिए निवर्तमान जस्टिस आरएफ नरीमन व जस्टिस सूर्यकांत के साथ पीठ में मौजूद चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, 'भाई नरीमन की सेवानिवृत्ति के साथ मुझे लगता है कि मैं न्यायिक संस्था की रक्षा करने वाले शेरों में से एक को खो रहा हूं।' चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस नरीमन को वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया ने नियम में संशोधन करके 45 की जगह 37 वर्ष की आयु में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया था। वह शीर्ष अदालत की पीठ में सीधे पदोन्नत होने वाले पांचवें वकील हैं। जस्टिस रमना अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने परंपरा से परे जाकर सालिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह व अन्य वकीलों को बात रखने की अनुमति दी।

13 अगस्त, 1956 को जन्मे जस्टिस नरीमन सात जुलाई, 2014 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए थे। उन्होंने 13,565 मामले निपटाए। शायरा बानो प्रकरण, निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने, गिरफ्तारी की शक्ति देने वाले आइटी अधिनियम के प्रविधान को निरस्त करने, सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटाने, सभी उम्र की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने समेत कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए।

कह के रहेंगे माधव जोशी

16 अगस्त को तीन दिवसीय दौरे पर ओडिशा आएंगे केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। ओडिशा से राज्यसभा सदस्य चुने जानेवाले वैष्णव रेलमंत्री बनने के बाद पहली बार ओडिशा आएंगे। माना जा रहा कि रेलमंत्री कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 13 अगस्त, 2021

उप्र में दांव पर सियासत की नई पीढ़ी की साख

जितेंद्र शर्मा, लखनऊ

▸ योगी, अखिलेश, प्रियंका और जयंत के रणनीतिक कौशल की होगी परीक्षा

▸ विधानसभा चुनाव में अपने-अपने दल के 'सेनापति' बनकर उतरेंगे मैदान में

योगी आदित्यनाथ।

अखिलेश यादव।

प्रियंका गांधी वाड्रा।

जयंत चौधरी। फाइल

उप्र में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि देश और प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव डालने वाली नई सियासी पीढ़ी की साख भी दांव पर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा या जयंत चौधरी, इनके रणनीतिक कौशल की बड़ी परीक्षा यह चुनाव लेने जा रहे हैं। ऊर्जा और जुनून से चमकते लगभग हमउम्र यह नौजवान नेता इस बार अपने-अपने दल के सेनापति के रूप में मैदान में होंगे। योगी को बुलंद भगवा झंडा थामे रखना है तो बाकी प्रतिद्वंद्वियों के सामने पार्टी का अस्तित्व बचाने की चुनौती है।

विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगातार चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल कर रही भाजपा आत्मविश्वास से लैस है, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस जातिगत गणित बिठाने में लगी हैं। गठबंधन की खुली घोषणा अभी किसी ने नहीं की, लेकिन छोटे-छोटे दलों को जोड़ने की जुगत के बीच एक-दो बड़े दल फिर साथ आ जाएं तो उससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। हर दल का अपना संगठन है, जिसे मजबूत करने में वह जुटे हैं। दिलचस्प यह है कि प्रमुख दलों में सिर्फ बसपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के झंडाबरदार नई पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं। बात सत्ताधारी दल से ही शुरू करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद गोरखपुर के पांच बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। साढ़े चार वर्ष तक योगी ने अपने अंदाज में काम किया। डेढ़ वर्ष की कोरोना आपदा के बावजूद कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कीं। यही वजह है कि भाजपा उन्हीं के चेहरे पर 2022 में चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले चुनाव में भाजपा 403 में से 312 विधानसभा सीटें जीती। इस जीत को दोहराने की जिम्मेदारी अब योगी के कंधों पर है।

जगजाहिर है कि मुलायम सिंह यादव की मेहनत से ही समाजवादी पार्टी सत्ता हासिल करती रही। 2012 का विस चुनाव भी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम के नेतृत्व में ही लड़ा गया। बहुमत पर उन्होंने बेटे अखिलेश यादव को सीएम की गद्दी सौंप दी। इसके बाद पार्टी और परिवार में मतभेद हुए और अखिलेश ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। 2017 का विधानसभा चुनाव वह कांग्रेस तो 2019 का लोकसभा चुनाव बसपा के साथ गठबंधन कर लड़े। दोनों बार निराशा हाथ लगी। अब बसपा जैसी सोशल इंजीनियरिंग के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति के साथ अखिलेश मैदान में हैं। देखना होगा कि 2017 में मात्र 47 सीट जीतने वाली सपा अब 400 सीटें जीतने का दावा कर कहां तक पहुंचती है?

प्रदेश में तीन दशक से सत्ता से बेदखल कांग्रेस के लिए उम्मीद बनकर प्रियंका गांधी वाड्रा सूबे की सियासत में सक्रिय हैं। वह पहले चुनाव प्रचार में आती रहती थीं, लेकिन पहली बार उन्होंने उप्र की जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पर संभाली है। 2017 में उनकी पार्टी मात्र सात सीटें जीत सकी तो 2019 के लोस चुनाव में एक सीट पर सिमट गई। प्रदेश में सक्रिय प्रियंका ने संगठन को अपने हिसाब से तैयार किया है। ऐसे में उनकी साख खास तौर पर दांव पर है। वहीं, चौधरी अजित सिंह के हाल ही में निधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष के रूप में उनके बेटे जयंत चौधरी को नई पारी शुरू करनी है। पिछले चुनाव में एक सीट जीतने वाला यह दल इससे अधिक जितनी सीट पाए, वही बढ़त होगी।

सहकारी बैंक धोखाधड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप पत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विवेकानंद शंकर पाटिल व अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सभी पर पनवेल स्थित सहकारी बैंक से 512 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है।

अभियोजन पक्ष ने मुंबई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है, जो ईडी की तरफ से प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत दाखिल मुकदमे की सुनवाई कर रही है। चार बार विधायक रहे पाटिल को एजेंसी ने इस मामले में जून में गिरफ्तार किया था। ईडी ने नवी मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से पिछले साल फरवरी में पाटिल व करीब 75 अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। आर्थिक अपराध शाखा की प्राथमिकी में पाटिल व अन्य पर मुंबई के पड़ोसी जिले रायगढ़ के पनवेल स्थित करनाला नगरी सरकारी बैंक में 512.54 करोड़ रुपये की अनियमितता बरतने का आरोप है। किसान व कामगार पार्टी के नेता पाटिल बैंक के पूर्व चेयरमैन हैं।

आरसीपी के स्वागत के बहाने जदयू में मुखर हो रहा एक खेमा

राज्य ब्यूरो, पटना

▸ 16 को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में होंगे आरसीपी सिंह, स्वागत की जोरदार तैयारी

जदयू में खेमेबाजी की चर्चा मुखर होने पर पार्टी के दिग्गजों को सामने आकर यह कहने की नौबत आ रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं। हालांकि अब जिस तरह से पोस्टरों की बड़ी श्रृंखला पटना में दिख रही वह पार्टी के भीतर एक नए ट्रेंड की गवाही दे रही। आपस में ही शक्ति प्रदर्शन को लेकर स्पर्द्धा स्वभाविक रूप से नजर आ रही है।

जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद छह अगस्त को राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पहली बार पटना पहुंचे थे। उनके स्वागत में जिस तरह से शहर में पोस्टर लगे और हवाई अड्डे से लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक भीड़ उमड़ी, उसने एक बड़ी लकीर खींची। अब पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पटना आ रहे। उनके स्वागत को लेकर भी पार्टी के कुछ लोग बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे।

आरसीपी सिंह के स्वागत में बने बड़े फ्लेक्स को पिछले दिनों पार्टी दफ्तर के बाहर लगाया गया था। उसमें ललन सिंह की तस्वीर व नाम नजर नहीं आने के बाद थोड़ी तल्खी आई, लेकिन फ्लेक्स लगाने वाले व्यक्ति के माफी मांगने के बाद मामला शांत हो गया। वह शांति संभवतः तात्कालिक थी। अब फिर से बड़ी संख्या में नए पोस्टर व फ्लेक्स पटना के कई हिस्सों में दिख रहे।

वैसे आरसीपी सिंह ने तकनीकी तौर पर अपने समर्थकों को यह संदेश भिजवाया है कि पार्टी दफ्तर में मेरे कार्यक्रम को स्वागत समारोह नहीं कहा जाए। समारोह का आधार यह रहे कि वह पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार पार्टी दफ्तर में उनका संबोधन भी होगा। कार्यक्रम की तैयारी में लगे जदयू के लोगों का कहना है कि 16 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे आरसीपी पहुंचेंगे। समर्थकों का बड़ा जत्था उनका स्वागत करेगा और काफिले की शक्ल में वह पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। अगले दिन वह अपने गांव जाएंगे।

मोदी-शाह का एजेंडा पंजाब में लागू कर रहे हैं कैप्टन : माली

आरोप ▸ नवजोत सिद्धू के सलाहकार ने किया मुख्यमंत्री पर हमला

जागरण संवाददाता, जालंधर

नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब उनके सलाहकारों ने भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमले शुरू कर दिए हैं। सिद्धू के सलाहकार नियुक्त किए गए मालविंदर माली ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट डालकर कैप्टन पर आरोप लगाए हैं कि वह पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एजेंडा लागू कर रहे हैं।

दैनिक जागरण के साथ बातचीत में माली ने कहा, 'मैं गुरचरण सिंह टोहड़ा से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह व प्रकाश सिंह बादल का सलाहकार रहा हूं। पंजाब के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार खुलकर व्यक्त करता हूं। अगर सिद्धू पंजाब के हित के लिए कोई अच्छा एजेंडा ला रहे हैं तो कैप्टन को उसका समर्थन करना चाहिए।'

माली ने कहा कि कैप्टन सिद्धू की राह में भी कांटे बिछा रहे हैं। कैप्टन सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनवाने के बजाए अकालियों की मदद कर सुखबीर को मुख्यमंत्री बना देंगे। यह गलत है। कैप्टन ने तो सिद्धू व पाकिस्तानी जनरल बाजवा की जफ्फी को मुद्दा बनवा दिया और अब मोदी के राष्ट्रवाद के एजेंडे को पंजाब में लागू करना चाहते हैं। इससे पहले माली ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालते हुए कैप्टन की बुधवार को प्रधानमंत्री व मंगलवार को अमित शाह के साथ हुई बैठकों पर भी निशाना साधा। कहा कि कैप्टन ने शाह के साथ पांच किसान नेताओं की बात की है और मंदिरों पर हमले की आशंका जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कैबिनेट में बदलाव का प्रपोजल लेकर गए कैप्टन को सलाह दी थी कि वह पंजाब में सिद्धू के साथ मिलकर काम करें। परंतु कैप्टन ने अपना एजेंडा मोदी और शाह को दे दिया। कैप्टन ने पंजाब में अर्द्धसैनिक बलों की 25 कंपनियों की तैनाती मांगी है। इसका खर्च भी पंजाब सरकार को उठाना पड़ सकता है। इससे कर्ज में डूबे पंजाब पर और आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

विस सत्र में रद कराएंगे बिजली समझौते : सिद्धू

जागरण संवाददाता, अमृतसर

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अमृतसर में आगमन से पहले ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू करीब दो साल बाद कर्मभूमि पर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र में बिजली समझौते रद कराए जाएंगे और पंजाब के लोगों को हर हाल में तीन से पांच रुपये में बिजली दी जाएगी। कहा कि कृषि कानूनों में संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि इन्हें रद कराया जाएगा।

करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ करने के बाद सिद्धू ने कहा कि चाहे उनकी जन्मभूमि पटियाला है, लेकिन अमृतसर उनकी कर्मभूमि है और इसे वह नहीं छोड़ सकते। गुरुनगरी का विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। इसके लिए उन्हें चाहे सब कुछ त्यागना पड़े। उन्होंने कहा कि बदले की भावना की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 17 रुपये प्रति यूनिट में बिजली ब्लैक में खरीदी थी। उन्होंने पंजाब पर 65 हजार करोड़ रुपये कर्जा चढ़ा दिया और आठ हजार करोड़ रुपये बिना बिजली खरीदे ही कंपनियों को दे दिया जो सरासर गलत है।

कांग्रेस ने की जैन समाज की समस्याओं पर चर्चा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) के अल्पसंख्यक विभाग के सम्मेलन में जैन समाज की समस्याओं पर चर्चा हुई और उन्हें दूर करने का संकल्प लिया गया।

कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित सम्मेलन में 10 राज्यों से आए जैन समाज के पार्टी प्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुरोध ललित जैन ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की पहल पर पहली बार जैन समाज के लोगों को बुलाकर उनकी समस्याओं को हल करने, संगठन में जगह दिलाने एवं अन्य सामाजिक विषयों को लेकर विचार मंथन हुआ। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नगालैंड से पहुंचे विभिन्न प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार रखे। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष एवं पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने कहा कि कांग्रेस समाज को जोड़ के रखने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने विश्वास दिलाया कि जैन समाज के लोगों को अल्पसंख्यक विभाग में उनकी संगठन क्षमता के अनुसार जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, एआइसीसी के पूर्व सचिव संजय बाफना, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के महासचिव बाबूराम गुप्ता, समाजसेवी गजेंद्र सिंघवी व अन्य मौजूद थे।

स्वास्थ्य, बेरोजगारी व शिक्षा पर होगा उप्र कांग्रेस घोषणापत्र का फोकस

राजीव दीक्षित, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र तैयार करने की खातिर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाएगी। पार्टी की कोशिश है कि उसका घोषणापत्र जन अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का आकर्षक वैकल्पिक निदान भी प्रस्तुत करे। घोषणापत्र के लिए जनता की नब्ज टटोलने की खातिर पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी मंडलवार दौरे करेगी। इसकी शुरुआत कांग्रेस और लखनऊ मंडल मुख्यालयों से होने जा रही है।

चुनाव घोषणापत्र तैयार करने के लिए कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर गठित मैनिफेस्टो कमेटी इसके लिए प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के बाद अब लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं और अपेक्षाएं जानेगी।

मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बताया कि पार्टी का मत है कि उसका चुनाव घोषणापत्र लोगों के बीच से आए। इसके लिए कमेटी सोशल सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा कर चुकी है। कमेटी ने अब तक की कवायद में पाया है कि उप्र की जनता मुख्यतः दो समस्याओं से सबसे ज्यादा त्रस्त है। इनमें से एक स्वास्थ्य और दूसरी बेरोजगारी है। शिक्षा इस लिहाज से तीसरे नंबर पर है।

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए हमें घोषणापत्र में भरपूर प्रविधान करने होंगे। इसके अलावा गवर्नेंस, महिलाओं की सुरक्षा व कानून व्यवस्था आदि से जुड़े मुद्दे भी होंगे। कांग्रेस की कोशिश होगी कि इन क्षेत्रों से जुड़ी जनसमस्याओं को हल करने के लिए पार्टी अपने घोषणापत्र में आकर्षक विकल्प और निदान पेश कर सके। समाज के विभिन्न तबकों व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए मैनिफेस्टो कमेटी 14 अगस्त को कानपुर जाएगी। इसके दो-तीन दिन बाद वह लखनऊ जाएगी। खुर्शीद ने बताया कि कोशिश होगी कि कमेटी दो महीने में सभी मंडलों के दौरे पूरे कर ले।

गांवों में जड़ें मजबूत करने को 90 लाख लोगों से संवाद करेगी पार्टी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

गांवों में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के 30 हजार गांवों और वार्डों में जय भारत महासंपर्क अभियान चलाएगी। 19 से 21 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता गांवों और वार्डों में तीन दिन के प्रवास के दौरान 90 लाख लोगों से सीधा संवाद करेंगे। यह अभियान पार्टी के दिवंगत नेता व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती (20 अगस्त) के मौके पर आयोजित होगा। उप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गुरुवार को बताया कि इस दौरान गांवों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

पार्टी के नेता व कार्यकर्ता गांवों में श्रमदान करेंगे। प्रवास के दौरान 'मेरा गांव, मेरा देश' संवाद कार्यक्रम के जरिये ग्रामीण जीवन की समस्याओं, खेतीबाड़ी, महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा पशुओं की समस्या आदि मुद्दों पर गांववासियों से संवाद होगा।

न्यूज गैलरी

लोकायुक्त के खिलाफ हाई कोर्ट गए विधायक प्रदीप

कटक (ओडिशा) : ओडिशा के कटक स्थित गोपालपुर क्षेत्र के विधायक प्रदीप पाणिग्रही ने लोकायुक्त अजीत सिंह एवं सचिव मानस त्रिपाठी के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया है। विधायक ने कहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश की फर्जी कापी के आधार पर लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जिसपर प्राथमिक सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार को मीडिया से बातचीत में विधायक के वकील पीतांबर आचार्य ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विधायक प्रदीप पाणिग्राही के खिलाफ दायर मामले में लोकायुक्त की इंक्वायरी विंग प्राथमिक जांच करेगी। हाई कोर्ट के निर्देश में यह स्पष्ट था। इस निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए लोकायुक्त कार्यालय की ओर से हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था। उस रिव्यू पिटीशन को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने पांच अप्रैल 2021 को खारिज कर दिया था। उसी निर्देश के खिलाफ लोकायुक्त कार्यालय के सचिव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। हाई कोर्ट में छह पन्ने वाले खारिज निर्देश को एसएलपी में चुनौती दी गई थी, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट ने दो पन्ने का का आदेश जारी किया था। (जासं)

विद्यार्थियों को नामांकन में आरक्षण देने की मांग

भुवनेश्वर (ओडिशा) : ओडिशा में आठ हजार आबादी वाली कोटिया पंचायत क्षेत्र पर आंध्र प्रदेश द्वारा कब्जे की लड़ाई जारी है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यहां कराए गए चुनाव में निर्वाचित गंजेईपदर पंचायत के सरपंच ने वहां की सरकार को पत्र लिखकर स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन के लिए आरक्षण देने की मांग की है। सरपंच के पत्र ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को नए सिरे से हवा दे दी है। आशंका जताई जा रही है कि आंध्र प्रदेश सरकार 15 अगस्त तक क्षेत्र को कब्जे में ले लेगी। इधर, ओडिशा सरकार ने भी निपटने की तैयारी कर रखी है। आरोप है कि आंध्र प्रदेश सरकार भाषाई आधार पर लोगों को बरगला रही है। इसके मद्देनजर ओडिशा सरकार ने कोटिया इलाके के गांवों में कई विकास परियोजनाओं को शुरू कर दिया है। वहीं, सीमा क्षेत्र के 22 गांवों पर कब्जा जमाने के लिए आंध्र प्रदेश लगातार प्रयासरत है। (जासं)

नंदीग्राम मामले में ममता का इंतजार बढ़ा, हाई कोर्ट ने 15 नवंबर तक टाली सुनवाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

पिछले दिनों संपन्न हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी से मिली हार को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इंतजार और बढ़ गया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए टाल दी है। दूसरी ओर, इस मामले को बंगाल से बाहर हस्तांतरित करने के लिए सुवेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दरअसल, सुवेंदु ने नंदीग्राम से ममता को करीबी मुकाबले में 1,956 मतों से हरा दिया था। इसके बाद ममता ने मतगणना में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए इस सीट के चुनाव परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले 14 जुलाई को हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नंदीग्राम में चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड व दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। उधर, सुवेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर कहा है कि बंगाल में इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई असंभव है। इसीलिए उन्होंने इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के अलावा देश के किसी भी दूसरे कोर्ट में करने की अपील की है। सुवेंदु के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शंपा सरकार की एकल पीठ ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए इसकी अगली तारीख 15 नवंबर तय कर दी।

बंगाल में एक नवंबर से पहले हो सकते हैं सात विस सीटों पर उपचुनाव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल की सात विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव एक नंबर से पहले हो सकते हैं। राज्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के सूत्रों से यह खबर मिली है। यह भी पता चला है कि आयोग ने इस बाबत तैयारियां शुरू कर दी है। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस जल्द से जल्द उपचुनाव चाहती है। इसे लेकर वह चुनाव आयोग को पत्र भी लिख चुकी है। इसकी बड़ी वजह भी है। कोलकाता की भवानीपुर विस सीट से सीएम ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वह नंदीग्राम से चुनाव हार गई थीं। हालांकि उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए छह महीने के अंदर उपचुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बनना जरूरी है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग एक नवंबर से पहले उपचुनाव इसलिए कराना चाहता है, क्योंकि इसके बाद सूबे में दुर्गापूजा को लेकर उत्सव का माहौल शुरू हो जाएगा। दूसरा, अभी चुनाव आयोग को तैयारियों के लिए सितंबर का समय मिल जाएगा। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा दो मई को हुई थी। तृणमूल ने जबरदस्त बहुमत के साथ तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर वापसी की थी।

तीसरे मोर्चे की कवायद

नई दिल्ली : तीसरे मोर्चे का ताना-बाना बुनने में पूरी सक्रियता के साथ जुटे इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने गुरुवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की। एएनआइ

वैक्सीन ही नहीं, डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो लगवाएं मोदी : ममता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर गुरुवार को तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर लगाई है, अब उन्हें डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी तस्वीर लगानी चाहिए।

ममता ने विस सचिवालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने (मोदी) कोविड टीके के सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो अनिवार्य कर दी है। अब डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर को लगाएं। जमीन से लेकर आसमान तक सभी जगह अपना नाम रख रहे हैं। हर चीज की एक प्रतिष्ठा होती है। उसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के तहत होने वाली सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की परीक्षा में बंगाल हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल पर भी भाजपा और केंद्र पर हमला बोला। आरोप लगाया कि मोदी सरकार यूपीएससी जैसी संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। गौरतलब है कि सीएपीएफ की बीते आठ अगस्त को हुई परीक्षा में बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर सवाल किया गया था।

इस दौरान ममता ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव बाद बंगाल में हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सीआरपीएफ ने हिंसा की थी। शीतलकुची में सीआरपीएफ के जवानों ने गोली चलाई थी, जिसमें कई निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे। चुनाव बाद हिंसा पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर ममता ने कहा कि आयोग में भाजपा के आदमी हैं।

कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट को ब्लाक करने की निंदा की

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट कथित तौर पर ब्लाक करने की निंदा की। इसके साथ ही सवाल किया कि क्या इसका संबंध भाजपा की राजनीति और नीतियों का विरोध करने से है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ-ब्रायन ने ट्वीट किया कि ट्विटर और ट्विटर इंडिया, ये क्या चल रहा है? हम कांग्रेस और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट को ब्लाक करने की कड़ी निंदा करते हैं।

कानपुर देहात में भाजपा विधायक प्रतिभा शुक्ला बनवाएंगी परशुराम मंदिर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : जिस कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण एक मुद्दा बनना शुरू हुआ, उसी क्षेत्र यानी कानपुर देहात में विपक्ष के इस मुद्दे की काट का प्रयास भाजपा खेमे से शुरू हुआ है। सपा ने हर जिले में परशुराम की प्रतिमा लगवाना शुरू किया है। अब उसी राह पर चलते हुए कानपुर देहात के अकबरपुर रनियां से भाजपा विधायक प्रतिभा शुक्ला ने भी परशुराम मंदिर बनवाने की घोषणा की है।

मंदिर निर्माण के लिए गठित भगवान श्री परशुराम न्यास की अध्यक्ष प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद व न्यास के संरक्षक अनिल शुक्ला वारसी ने गुरुवार को बताया कि कानपुर-आगरा हाईवे पर स्थित उमरन गांव में न्यास को सात बीघा जमीन दान में मिली है। वहां भगवान परशुराम का मंदिर बनवाकर 25 फीट की प्रतिमा लगवाने जा रहे हैं। मंदिर परिसर में परशुराम अनुसंधान केंद्र और वैदिक पाठशाला भी होगी। अनिल शुक्ला ने दावा किया ब्राह्मण भाजपा के साथ था, है और रहेगा। यह मंदिर ब्राह्मणों को एकजुट करके राजनीतिक रूप से मजबूत बनाएगा।

प्रत्येक बूथ पर दो महिलाएं तैनात करेगी सपा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : समाजवादी पार्टी प्रत्येक बूथ पर दो महिला कार्यकर्ता अनिवार्य रूप से तैनात करेगी। अभी तक महिला कार्यकर्ताओं की बूथ पर तैनाती का कोई तय फार्मूला नहीं था। महिला कार्यकर्ताओं की जहां जैसी उपलब्धता थी, उसी के अनुरूप इनकी तैनाती हो जाती थी। गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में हुई समाजवादी महिला सभा की बैठक में तय किया गया कि अब प्रत्येक बूथ पर दो महिला कार्यकर्ताओं की तैनाती जरूर होगी। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र व जिले में समाजवादी महिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बैठक में कहा कि सपा में ही महिलाओं का सम्मान सुरक्षित है। अखिलेश यादव की सरकार में महिला सुरक्षा एवं प्रतिनिधित्व की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हुए थे। 1090 वूमेन हेल्पलाइन से सपा सरकार में महिला उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आई थी।

बंगाल ही नहीं उप्र, असम, त्रिपुरा व गुजरात में भी 16 को तृणमूल मनाएगी 'खेला होबे' दिवस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 21 जुलाई को शहीद दिवस के बाद अब 16 अगस्त को 'खेला होबे' दिवस बंगाल के साथ ही भाजपा शासित गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा व असम सहित अन्य राज्यों में भी मनाने की तैयारी कर रही है।

गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस का 'खेला होबे' नारा खूब चर्चित हुआ था। इसके साथ ही पार्टी को चुनाव में जीत भी मिली थी। इसके बाद पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि हर साल 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि बंगाल का खेला होबे का नारा था, अब यह देश के हर राज्य में लगेगा। यह नारा अब केवल बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे देश का नारा बन गया है। तृणमूल की ओर से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 16 अगस्त को फुटबाल मैच का आयोजन किया जाएगा।

भाजपा निकालेगी शहीद सम्मान यात्रा : दूसरी ओर, भाजपा 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने का विरोध कर रही है। भाजपा विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इस बाबत राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर 16 अगस्त की तारीख को बदलने की मांग की है। भाजपा का कहना है कि जिन्ना ने 16 अगस्त, 1946 को डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी, जिसके बाद बंगाल से लेकर कई राज्यों में भीषण दंगे हुए थे और कत्लेआम हुआ था। बंगाल भाजपा ने 16 अगस्त से दो दिन तक पूरे बंगाल में कथित तृणमूल के हमले में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद सम्मान यात्रा निकालने की घोषणा की है।

आरटीआइ कार्यकर्तासाकेत गोखले टीएमसी में शामिल

कोलकाता, राज्य ब्यूरो : जाने-माने आरटीआइ कार्यकर्ता और मोदी सरकार के आलोचक रहे साकेत गोखले ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का दामन थाम लिया। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं यशवंत सिन्हा, डेरेक ओ-ब्रायन एवं सौगत राय की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। महाराष्ट्र से आने वाले गोखले अक्सर आरटीआइ के जरिये नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं।

आजादी @75
जानिए जन-गण का मन

आगामी 15 अगस्त को भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पूरा देश उत्साहित है। आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां चरम पर हैं। अभी हम कोविड काल से जूझ ही रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक रूप से चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। महामारी से लड़ते-लड़ते हमने पर्याप्त संसाधन जुटा लिए हैं। सितंबर, 2020 में आई कोविड-19 की पहली लहर के प्रतिकूल असर से अभी अर्थव्यवस्था ने उबरने का संकेत ही दिया है। कई अध्ययन भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने का पूर्वानुमान जता रहे हैं।

देश के ऐसे माहौल में **लोकल सर्कल्स** ने लोगों के मन की थाह ली है कि तमाम मुद्दों और मसलों में हम 2022 में कहां खड़े होंगे जब भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर चुका होगा। 2017 से कर रहे इस आशय के सर्वे में इस बार इस संस्था ने 280 जिलों के 75 हजार लोगों की राय ली। इनमें 68% पुरुष, 32% महिलाएं शामिल रहीं।

अगले एक साल में कैसा रहेगा...

महामारी के असर से आर्थिक रिकवरी

33% पूरी तरह रिकवर होंगे और महामारी से पहले की जीडीपी स्तर को हासिल करेंगे
5% और स्थिति खराब होगी
2% कह नहीं सकते
3% हम किसी भी कीमत पर रिकवरी नहीं कर पाएंगे
15% सीमित रिकवरी होगी
31% पूरी नहीं लेकिन उल्लेखनीय रिकवरी होगी
11% पूरी तरह रिकवर होंगे, लेकिन महामारी के पूर्व स्तर को नहीं पाएंगे

वैश्विक फलक पर भारत की छवि

3% कह नहीं सकते
58% सुधरेगी
20% स्थिर रहेगी
19% घटेगी

महामारी की तीसरी लहर की तैयारी के प्रति आश्वस्ति

26% पूरी तरह आश्वस्त
4% कह नहीं सकते
32% कुछ आश्वस्त
13% बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं
25% बहुत थोड़ा आश्वस्त

उद्यमिता और रोजगार सृजन द्वारा जनसांख्यिकी लाभ

सामाजिक स्थिरता की तस्वीर

26% सुधरेगी
2% कह नहीं सकते
38% यथावत रहेगी
34% खराब होगी

घूसखोरी और भ्रष्टाचार में बदलाव

भारत की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि

20% सभी का विकास और समृद्धि
1% कह नहीं सकते
37% अधिकांश का विकास और समृद्धि
2% किसी का विकास और समृद्धि नहीं
40% कुछ का विकास और समृद्धि

सर्वेक्षण न योजना...फिर कैसे बचेंगे पहाड़

आपदा ▸ पहाड़ दरकने के कारण जानने के लिए नहीं करवाया सर्वेक्षण

तीन साल बीतने पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नियुक्त हुए उपाध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, शिमला

हिमाचल प्रदेश में कुछ वर्षों से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। किन्नौर जिला में पिछले 18 दिन में दो बार पहाड़ दरकने से कई लोग जान गंवा चुके हैं। हैरत यह है कि प्रदेश की सरकारों ने सर्वेक्षण ही नहीं करवाया कि पहाड़ों के दरकने और चट्टानें गिरने के पीछे कारण क्या हैं? दुखद यह है कि किसी भी सरकार के पास पहाड़ों को दरकने से रोकने के लिए कोई योजना नहीं दिखी।

हां, पूर्व आपदा प्रबंधन के नाम पर हर साल सरकारी विभागों की माक ड्रिल करवाकर प्रशासनिक औपचारिकता पूरी होती है। अगले वर्ष फिर प्रशासनिक अमले को चौकस करने का इंतजार किया जाता है। हकीकत में कभी चट्टानें गिरने की समस्या का स्थायी समाधान करने का प्रयास नहीं हुआ। आपदा प्रबंधन की प्राथमिकता का अंदाजा इससे होता है कि मौजूदा सरकार के तीन साल बीत जाने के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है।

केंद्र सरकार से हर वर्ष राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत राज्य सरकार को 90:10 के अनुपात में बजट मिलता है। इसे सरकार अपने वार्षिक बजट में भी दिखाती है। एसडीआरएफ के तहत हिमाचल को वर्ष 2020-21 के लिए 454 करोड़ रुपये का बजट आया था।

राष्ट्रीय आपदा राहत बल केवल शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करता है। हिमाचल में एसडीआरएफ बजट को भारत सरकार की ओर से 33 घोषित आपदाओं में से 25 आपदाओं पर खर्च किया जाता है, जिसमें सर्वेक्षण करना कहीं शामिल नहीं है। भूकंप, बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन, अचानक बाढ़, ग्लेशियर खिसकना सहित अन्य तरह की आपदाएं घोषित हैं, जिससे निपटने के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, यंत्र खरीद करना शामिल है। यदि लोक निर्माण विभाग की ओर से बुलडोजर खरीदने का प्रस्ताव आता है तो एक-दो बुलडोजर खरीदे जा सकते हैं। इसी तरह से अग्निशमन विभाग की ओर से वाहनों की खरीद शामिल है।

संभव नहीं पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण: सर्वेक्षण के नाम पर उद्योग विभाग का भूगर्भीय विंग यानी जियोलाजिकल विंग केवल क्षेत्र विशेष का सर्वे करता है। चाहे स्वारघाट का क्षेत्र हो, हणोगी माता का क्षेत्र, मंडी शहर के साथ लगता क्षेत्र या गुम्मा में चट्टानी नमक खान, क्षेत्र में ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहां पहाड़ों में भूस्खलन गतिविधियां होती रहती हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण संभव नहीं है।

किन्नौर जिले के निगुलसरी में प्राकृतिक आपदा के कारण गहरी खाई में मलबे में दबे शवों को बाहर निकालते एनडीआरएफ, आइटीबीपी, डोगरा रेजीमेंट के जवान। जागरण

मेरे पापा की बॉडी मिल गई, सिर नहीं मिला

समर नेगी, रिकांगपियो : वीरवार को इंटरनेट मीडिया पर दिखाई दिया लोकेंद्र सिंह वैदिक का यह स्टेटस लोगों को रुलाता रहा। निरमंड के पोशना इलाके में नालागई गांव के रहने वाले 59 वर्षीय हुकम राम लोकेंद्र के पिता थे। हरिद्वार से आ रही बस में सवार थे। वीरवार को जब उनकी सिरविहीन देह मिली, लोकेंद्र की आस का पहाड़ भी भरभरा कर गिर गया... बस एक चीख और खामोशी। संबंधियों और बचाव दल के मजबूत कंधों ने लोकेंद्र के आंसू पोंछे लेकिन घाव कहीं अधिक गहरा था। ये और ऐसे ही दृश्य दिख रहे हैं निगुलसरी के पास चील जंगल में जहां बुधवार को पहाड़ कई जिंदगियों पर टूटा था। हुकम राम समाजसेवी थे।

किन्नौर हादसा : दूसरे दिन निकाले चार और शव, बस मिली

जागरण संवाददाता, शिमला

▸ स्वजन से मिली जानकारी पर 12 लापता लोगों की सूची तैयार

▸ दोबारा चट्टानें खिसकने के कारण बचाव कार्य शाम सात बजे रोका

हिमाचल के किन्नौर जिले के निगुलसरी में दूसरे दिन बचाव कार्य भले ही गुरुवार सुबह पांच बजे से पहले शुरू कर दिया था, लेकिन शाम तक चार लोगों के शव ही निकाले जा सके। परिवहन निगम की बस, जिसके सतलुज नदी में समाने की आशंका थी, वह बचाव दल को मिल गई है, लेकिन इसमें सवार लोगों का पता नहीं चल पाया। प्रशासन ने स्वजन से मिली जानकारी के तहत 12 लापता लोगों की सूची तैयार की है।

प्रशासन ने गुरुवार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के जवानों की संख्या बढ़ा दी। अब एनडीआरएफ 56 जवान बचाव कार्य में जुटेंगे। पुलिस के 30, आइटीबीपी के 52 जवान भी राहत कार्य में जुटे हैं। गुरुवार को किन्नौर जिले के निवासी भूपेंद्र सिंह, नेपाल के लक्ष्मण थापा नेपाल व कुल्लू जिले के निरमंड के हुकम राम के शव निकाले गए। वहीं, चौथे शव की पहचान नहीं हो पाई।

किन्नौर के पुलिस अधीक्षक एसआर राणा ने बताया कि पहाड़ी से दोबारा चट्टानें खिसकने के कारण बचाव कार्य को शाम सात बजे बंद कर दिया है। सुबह तीन बजे से बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। रात नौ बजे से लेकर सुबह नौ बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।

बता दें कि बुधवार दोपहर को करीब 12 बजे निगुलसरी में पहाड़ दरकने से परिवहन निगम की बस, टिप्पर और पांच वाहन मलबे में दब गए थे। घटना के बाद 10 शव बुधवार को ही निकाल लिए थे, जबकि 13 घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया था।

मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के लिए की मदद की घोषणा : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को किन्नौर जिले के निगुलसरी पहुंचे और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान दो-तीन दिन तक चलता रहेगा, ताकि मलबे के नीचे कोई रह न जाए। वहीं, इस तरह के हादसों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही ठोस कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जान गंवाने वाले लोगों के स्वजन को चार-चार लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपये देगी।

घटनास्थल पर गाड़ियों के अवशेष। जागरण

नए कश्मीर का महबूबा को जवाब, लहराने के लिए कम पड़े तिरंगे

विवेक सिंह, जम्मू

▸ भाजपा ने उपराज्यपाल को लिखा, जिलों में तिरंगे उपलब्ध करवाए कश्मीर प्रशासन

▸ आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रशासन से लेकर सेना करेगी भव्य कार्यक्रम

एक वक्त था जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर अनुच्छेद-370 हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मगर अनुच्छेद-370 हटने के दो साल पूरे होने और स्वतंत्रता दिवस से पहले ही कश्मीर के लोगों ने महबूबा को जवाब दे दिया है। क्योंकि कश्मीर में हर जगह तिरंगे शान से लहरा रहे हैं। वहीं, नौबत यह है कि कश्मीर में तिरंगों की कमी हो गई। इसका मुद्दा भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने उठाया है। वहीं, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश प्रशासन से लेकर सेना भी अपने कार्यक्रम करेगी।

भाजपा ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे कश्मीर में भव्य कार्यक्रम की तैयारी की है। लोग भी आयोजन करने को लेकर खुद आगे रहे हैं। पंचायतों से लेकर वार्डों तक आजादी का जश्न मनाया जाएगा। हालांकि, सभी जगहों में भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को लहराने के लिए 500 तिरंगे दिए हैं। इनमें हर जिला इकाई को 30-30 तिरंगे दिए गए हैं। सरकारी विभागों में समारोह के लिए तिरंगे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग तो खुद ही तिरंगे बनवा रहे हैं।

वहीं, तिरंगों की कमी का मुद्दा भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने उठाया है। ठाकुर ने गुरुवार को उपराज्यपाल को ट्वीट कर जोर दिया है कि जिलों में लहराने के लिए जल्द तिरंगे उपलब्ध करवाए जाएं। ठाकुर ने प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उठाया है। ठाकुर का कहना है कि कश्मीर के देशभक्त लोग आतंकवादियों की धमकियों से डरने वाले नही हैं। जिलों में स्कूलों के पास अब तक लहराने के लिए तिरंगे नहीं हैं। इसके साथ कुछ सरकारी कर्मचारियों ने भी तिरंगे लेने के लिए संपर्क किया है। हमारे पास सीमित तिरंगे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गत दिनों प्रशासन को निर्देश दिए थे कि पंचायत स्तर तक लोगों को तिरंगे फहराने में सहयोग दिया जाए।

कार्यक्रम को यादगार बनाने की तैयारी: भाजपा के साथ अखिल विद्यार्थी परिषद ने भी कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने की तैयारी की है। विद्यार्थी परिषद के सचिव मुकेश मन्हास का कहना है कि हमने कश्मीर के 1000 गांवों में तिरंगे लहराने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कश्मीर में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 3305 जगहों पर 3361 तिरंगा फहराने का कार्यक्रम करने की तैयारी है।

भाजपा ने एक हजार अतिरिक्त तिरंगे मंगवाए: जम्मू-कश्मीर में तिरंगों की कमी को देखते हुए प्रदेश भाजपा ने लोगों में बांटने के लिए जम्मू से एक हजार अतिरिक्त तिरंगे कश्मीर मंगवाए हैं। कश्मीर में डेरा डाले बैठे संगठन महामंत्री अशोक कौल का कहना है कि कश्मीर में तिरंगों की कमी को देखते हुए जम्मू से तिरंगे शुक्रवार को श्रीनगर पहुंच जाएंगे। इन तिरंगों को लोगों में बांटा जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पहले ही कश्मीर में तिरंगा पहुंचा दिए थे। कश्मीर में तिरंगों की बढ़ती मांग को एक अच्छा संकेत करार देते हुए कौल ने बताया कि क्षेत्र में देशभक्त लोगों का हौसला बुलंद है। यह शांति न चाहने वाले चाहने वाली ताकतों का कमजोर होने का संकेत भी है।

इसरो को चंद्रयान-2 से भी नहीं मिले थे वांछित परिणाम

नई दिल्ली, प्रेट्र : भू-निगरानी उपग्रह ईओएस-03 को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करने में जीएसएलवी राकेट की विफलता से दो साल पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण के दौरान भी वांछित परिणाम नहीं मिलने पर बड़ा झटका लगा था।

इसरो की महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 परियोजना का उद्देश्य चंद्रमा पर एक लैंडर को उतारना था, लेकिन यह परियोजना भी वांछित परिणाम नहीं दे पाई थी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना के साथ चंद्रयान-2 को 22 जुलाई, 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन सात सितंबर को चंद्रयान-2 मिशन को उस समय झटका लगा था जब चंद्रमा की सतह से महज दो किलोमीटर पहले लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था।

ईओएस-03 मिशन की विफलता में कोई बड़ा मुद्दा नहीं : विशेषज्ञ

इसरो के पूर्व अध्यक्ष माधवन नायर ने गुरुवार को ईओएस-03 मिशन की विफलता को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि क्रायोजेनिक चरण में विफलता की आशंका अधिक होती है। इसी तरह की विफलता 2010 में एक प्रक्षेपण के दौरान हुई थी, लेकिन सुधारात्मक उपाय किए गए थे और उसके बाद इसरो ने छह से अधिक जीएसएलवी प्रक्षेपण किए थे।

कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

इस मिशन की विफलता से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा है। इससे न सिर्फ राकेट और सेटेलाइट पर खर्च हुए कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है बल्कि 10 साल तक इससे अर्जित हो सकने वाले राजस्व की भी हानि हुई है। जाने-माने अंतरिक्ष विज्ञानी जी. माधवन नायर ने मिशन की असफलता पर हैरानी जताई है, लेकिन साथ ही कहा कि इसरो वापसी करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, इसरो ने पिछले कुछ वर्षों में क्रायोजेनिक तकनीक में महारत हासिल कर ली है और इस मामले में भारत का पुराना रिकार्ड यूरोपीय देशों और रूस की तुलना में उतना खराब नहीं है।

152 पुलिस अधिकारियों को गृहमंत्री मेडल

▸ पुरस्कार पाने वालों में 28 महिलाएं, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सतीश चंद्र शर्मा (मरणोपरांत) का नाम भी शामिल

स्वर्गीय इंस्पेक्टर सतीश चंद शर्मा।

इंस्पेक्टर विरेंद्र सिंह।

एसीपी संदीप लांबा।

इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह। एम हर्ष वर्धन। इंस्पेक्टर अम्लेशवर राय। डोमिनिका पूर्ति।

नई दिल्ली, प्रेट्र: आपराधिक मामलों की जांच में उत्कृष्टता व उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए देश के 152 पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2021 के केंद्रीय गृहमंत्री पदक से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। इनमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सतीश चंद्र शर्मा (मरणोपरांत) का नाम भी शामिल है। पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। पिछले साल यह पुरस्कार 121 पुलिस अधिकारियों को प्रदान किया गया था।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 'उत्कृष्ट जांच के लिए केंद्रीय गृहमंत्री मेडल-2021' पाने वालों में 28 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में सीबीआइ के 15, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र पुलिस के 11-11, उत्तर प्रदेश के 10, केरल व राजस्थान के नौ-नौ, तमिलनाडु के आठ, बिहार के सात, गुजरात, कर्नाटक व दिल्ली के छह-छह पुलिस अधिकारी शामिल हैं। तेलंगाना के पांच, असम, हरियाणा, ओडिशा व बंगाल के चार-चार, जबकि शेष अन्य राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को भी इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा।

पुलवामा आतंकी हमले की जांच करने वाले एनआइए अधिकारी को भी पुरस्कार :समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के पांच अधिकारियों को भी गृहमंत्री पदक प्रदान किया जाएगा। इनमें डीआइजी अनुराग कुमार शामिल हैं, जिन्होंने आतंकी संगठन आइएसआइएस मामले की जांच में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने जांच के दौरान पाया था कि आरोपितों ने भारत में आइएसआइएस से प्रभावित 'जुनूद-उल-खिलाफा-फिल-हिंद' नामक संगठन बना लिया था। फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जांच करने वाले एसपी राकेश बलवाल को भी इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा।

सीबीआइ के विजय शुक्ला व एनसीबी के समीर वानखेड़े भी सूची में : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के एडिशनल एसपी विजय कुमार शुक्ला भी पदक पाने वालों में शामिल हैं, जिन्होंने बदायूं खुदकुशी मामले की जांच की थी। फिलहाल वह धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर डी. वानखेड़े को भी गृहमंत्री पदक प्रदान किया जाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने ड्रग्स के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है।

कुपवाड़ा में एलओसी के पास 15 ग्रेनेड सहित हथियार बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

स्वतंत्रता दिवस नजदीक आते ही सरहद पार से कश्मीर में बड़ी वारदात की साजिशों को मुस्तैद सुरक्षाबल नाकाम कर रहे हैं। गुरुवार को उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे करनाह (कुपवाड़ा) सेक्टर में सुरक्षाबलों ने नशीले पदार्थ और विस्फोटकों की खेप को बरामद किया। विस्फोटकों में 15 ग्रेनेड भी शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, पुलिस को अपने खुफिया तंत्र से पता चला था कि गुलाम कश्मीर में बैठे आतंकी सरगनाओं ने नशीले पदार्थों के साथ हथियारों का जखीरा जिला कुपवाड़ा में एलओसी से सटे इलाके में ओवरग्राउंड वर्करों के पास भेजा है। यह जखीरा एलओसी पर एक जगह विशेष पर छिपाया है। अगले एक-दो दिन में इसे ओवरग्राउंड वर्कर वादी के भीतरी इलाकों में पहुंचाने वाले हैं। पुलिस ने सेना के जवानों के साथ तलाशी अभियान चलाया। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जवानों ने करनाह सेक्टर में हाजीतरा गांव में तलाशी लेते हुए उस जगह का पता लगाया जहां नशीले पदार्थ और हथियार छिपाए थे। सारा सामान हाजीतरा में सरकारी स्कूल की इमारत से कुछ दूरी पर छिपाया गया था। जवानों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इसमें 15 ग्रेनेड, पांच पिस्तौल, तीन डेटोनेटर, पिस्तौल के 150 कारतूस और एक पैकेट नशीला पदार्थ ब्राउन शूगर जैसा शामिल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

बीएसएफ के काफिले पर हमला, इमारत में छिपे आतंकी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर दक्षिण कश्मीर के मलपोरा (काजीगुंड) में बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद शुरू हुई मुठभेड़ में दो सुरक्षाकर्मियों और दो नागरिकों समेत चार लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं, जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी अपनी जान बचाने के लिए एक बड़ी इमारत में छिप गए हैं। इमारत को सुरक्षाबलों ने चारों तरफ से घेरकर रखा है। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार और सेना की विक्टर फोर्स लगातार निगरानी कर रहे हैं।

नीरज के सम्मान में लगाया सुनहरे रंग का लेटर बाक्स

मनीष श्रीवास्तव, अंबाला

▸ डाक विभाग ने की अनोखी पहल, खंडरा में भी लगेगी पत्र-पेटिका

▸ राज्य के 78 खिलाड़ियों को मिलेगी डाक विभाग में नौकरी : रंजू प्रसाद

टोक्यो ओलिंपिक के भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले पानीपत निवासी नीरज चोपड़ा के सम्मान में डाक विभाग ने अनोखी पहल की है। इसके तहत पानीपत में मुख्य डाकघर के सामने सुनहरे रंग का लेटर बाक्स लगाया गया है।

चीफ पोस्ट मास्टर आफ जनरल रंजू प्रसाद ने बताया कि अभी पानीपत के मुख्य डाकघर में यह सुनहरे रंग का लेटर बाक्स लगाया गया है। जल्द ही नीरज के खंडरा गांव में भी इसे लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि डाक विभाग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने वाले हरियाणा के 78 खिलाड़ियों को नौकरी देने जा रहा है। डायरेक्टर से स्वीकृति भी मिल चुकी है।

ओलिंपिक विजेता के सम्मान में निकाला डाक टिकट : नीरज चोपड़ा के सम्मान में डाक विभाग ने पांच रुपये का वन स्टाम्प (डाक टिकट) भी जारी किया है। इस टिकट को बधाई संदेश वाले लिफाफे पर चस्पा करके चिट्ठियां भेजी जा सकती हैं।

पानीपत मुख्य डाक घर के बाहर ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में लगा सुनहरे रंग का लेटर बाक्स। सौजन्य से डाक विभाग

ओलिंपिक में पदक के लिए खेलों को प्रोत्साहित करें राज्य : मनोहर

राब्यू, चंडीगढ़ : टोक्यो ओलिंपिक में अपने राज्य के खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन से गदगद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दूसरे राज्यों से खेलों को प्रोत्साहित करने की अपील की है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) की वार्षिक बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये जुड़े मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की पदक तालिका शीर्ष पर लाने के लिए राज्य सरकारें खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। खेल नीतियों में खेल व खिलाड़ियों के अनुरूप बदलाव करनी चाहिए। वह बोले, हरियाणा की आबादी पूरे देश की आबादी का मात्र दो फीसद है। ओलिंपिक में राज्य के खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 25 फीसद रही और 57 फीसद पदक यहां के खिलाड़ियों ने जुटाए।

उत्तर प्रदेश और बिहार में गहरा रहा बाढ़ का संकट

जागरण टीम, नई दिल्ली

▸ उत्तर प्रदेश के 23 जिलों के 1243 गांव आपदा से प्रभावित, 5.46 लाख लोगों पर असर, 361 में बाढ़ से त्रासद हालात

उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ का संकट गहरा रहा है। उप्र के 23 जिलों के 1243 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। इनमें से 72 गांवों में कटान हो रही है। बाढ़ से 104 गांवों का संपर्क मार्ग कट गया है। जलभराव के कारण 539 गांवों में आबादी, 167 में खेती और 361 में जनजीवन और कृषि दोनों प्रभावित हैं। इन गांवों के 5,46,049 लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। उधर, बिहार में नए इलाकों में भी पानी फैलने लगा है। उत्तर बिहार की नदियों के नेपाल स्थिति जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के चलते दो दिन बाद भी निजात की उम्मीद नहीं है। दक्षिण बिहार की नदियां भी उफन रही हैं। गंगा के साथ सोन और पुनपुन के बढ़ते जलस्तर के कारण पटना के आसपास के निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन सतर्क है। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के पीरपैंती थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर गुरुवार को बाढ़ के पानी व तालाब में डूबने से तीन लोगों की मौत हो गई।

बिहार में नए इलाकों में फैला पानी : बिहार में बक्सर, पटना, मुंगेर से लेकर भागलपुर के कहलगांव तक गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना के दीघाघाट में गंगा का पानी प्रति घंटे एक सेमी बढ़ रहा है। गांधी घाट की भी यही स्थिति है। यहां जलस्तर रिकार्ड तोड़ने के करीब है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन भी खतरनाक बनी हुई है। समस्तीपुर में गंगा, गंडक और बाया नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। नेपाल से निकलने वाली तमाम नदियों का पानी तेजी से बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में यह नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में घुसपैठ कर डाटाबेस से छेड़छाड़, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर : भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में घुसपैठ कर सहारनपुर के एक युवक ने मध्य प्रदेश के अपने साथी के साथ डाटाबेस में छेड़छाड़ की। आरोपितों ने वेबसाइट के जरिये धोखाधड़ी कर दस हजार वोटर आइडी कार्ड बना डाले। जांच एजेंसियों के इनपुट पर सहारनपुर पुलिस ने गांव माच्छरहेड़ी निवासी आरोपित विपुल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया। दिल्ली की जांच एजेंसी दो तीन दिन बाद आरोपित को बी-वारंट पर दिल्ली लेकर जाएगी। सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव माच्छरहेड़ी निवासी विपुल सैनी को पुलिस व क्राइम ब्रांच ने साइबर सेल के साथ मिलकर बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। विपुल सैनी पर आरोप है कि उसने अपने साथी अरमान मलिक निवासी हरदा मध्य प्रदेश के साथ मिलकर आयोग की वेबसाइट में घुसपैठ कर डाटाबेस में छेड़छाड़ की।

देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 3.87 लाख हुए

बढ़ी चिंता ▶ महामारी से 24 घंटों में गई 490 और लोगों की जान

जेएनएन, नई दिल्ली

देश में कोरोना संक्रमण के 41,195 नए मामले सामने आए हैं। इससे कुल संक्रमितों की संख्या 3,20,77,706 हो गई है। वहीं लगातार पांच दिनों तक कमी दर्ज करने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर 3,87,987 हो गए। जबकि 490 ताजा मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,29,669 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मामले, कुल मामलों का 1.21 फीसद हैं।

राज्यों को उपलब्ध कराईं 54.04 करोड़ डोज : केंद्र: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 54.04 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। 1,09,83,510 अतिरिक्त डोज देने की तैयारी है। अभी भी राज्यों के पास 2,55,54,533 डोज उपलब्ध हैं।

बेंगलुरु में 75वें स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के लिए रिहर्सल के मौके पर बीएसएफ के जवानों का कोरोना टेस्ट के लिए स्वैब सैंपल लेते स्वास्थ्यकर्मी। प्रेट्र

सुबह आठ बजे तक की स्थिति	
नए मामले	41,195
कुल मामले	3,20,77,706
सक्रिय मामले	3,87,987
मौतें (24 घंटे में)	490
कुल मौतें	4,29,669
ठीक होने की दर	97.45 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	1.94 फीसद
सा.पाजिटिविटी दर 2.23	फीसद
जांचें (बुधवार)	21,24,953

खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि अक्षम लोगों को उनके घर जाकर टीका लगाएं

▶ प्रथम पृष्ठ का शेष

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिव्यांगों के लिए टीकाकरण शिविर में पहुंचने की उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मनोरोग केंद्रों में जाकर टीकाकरण किया जाना चाहिए। अक्षम लोगों को उनके घर पर जाकर प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाना चाहिए। अदालत ने बंगाल सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह अदालत को राज्य में प्रति दिन किए जाने वाले टीकाकरण की संख्या और बुनियादी सुविधाओं के बारे में सूचित करे।

स्वतंत्रता के सारथी — महामारी से आजादी

संक्रमितों की सेवा के लिए टाल दी शादी

बठिंडा की डा. हरजोत ने स्वजन के दबाव के बावजूद कोरोना मरीजों की देखभाल को दी प्राथमिकता

गुरप्रेम लहरी • बठिंडा

कोरोना काल में कई फ्रंटलाइन वर्करों ने अपनी जान जोखिम में डाल कर मरीजों की सेवा की। कुछ को तो सेवा के दौरान जान भी गंवानी पड़ी। डाक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को ही अपनी प्राथमिकता में रखा। अपने परिवार तक की परवाह नहीं की और कई-कई दिन उनसे दूर रहे। बठिंडा की डा. हरजोत कौर का भी जज्बा और समर्पण भाव प्रशंसनीय है। डा. हरजोत ने अपनी शादी की तैयारी छोड़ कोरोना मरीजों की देखभाल को अहमियत दी। स्वजन शादी के लिए जोर देते रहे, लेकिन उन्होंने महामारी से आजादी की जंग को तरजीह दी।

पहली लहर में रहीं मरीजों के बीच: कोरोना की पहली लहर में डा. हरजोत की ड्यूटी शहर के मेरिटोरियस स्कूल में बनाए गए कोरोना सेंटर में लगी, लेकिन बाद में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उन्हें संक्रमितों की सेवा के लिए भेजा गया। इस समय वह सरकारी अस्पताल में सैंपलिंग में ड्यूटी निभा रही हैं। पहली लहर में वह लगातार मरीजों के बीच रहीं। कोरोना केयर सेंटर में रहकर वहां दाखिल मरीजों की देखभाल की।

अक्टूबर में होनी थी शादी: बठिंडा के विशाल नगर की रहने वाली डा. हरजोत कौर की शादी बीते साल अक्टूबर में मुक्तसर के युवक के साथ तय हुई थी। डा. हरजोत कोरोना केयर सेंटर में ड्यूटी होने के कारण अत्यधिक व्यस्त थीं। परिवार के सदस्य उनसे कहते रहे कि वह कहीं दूसरी जगह तबादला करवा लें, लेकिन डा. हरजोत ने मना कर दिया। कहा कि वह वहीं पर तैनात रहेंगी, जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई है। कोरोना मरीजों का इलाज व देखभाल ही उनकी प्राथमिकता है। वह अपने फर्ज से भाग नहीं सकतीं। पहली लहर जब धीमी हुई तो उन्होंने शादी करने का फैसला किया। अब सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपलिंग में सेवाएं दे रही हैं।

मरीज का सैंपल लेतीं डा. हरजोत • फाइल फोटो

खाना पहुंचाने में भी मदद

डा. हरजोत ने केवल अस्पताल में ही कोरोना मरीजों की सेवा नहीं की। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल समाजसेवी संस्थाओं को भी पूरा सहयोग दिया। मेरिटोरियस स्कूल में नौजवान वेलफेयर सोसायटी मरीजों को खाना मुहैया करवाती रही। इसमें डा. हरजोत ने उनकी पूरी मदद की। उनके पिता इंद्रजीत सिंह कहते हैं, हमें गर्व है कि हरजोत ने अपनी निजी जिंदगी से ज्यादा मरीजों की सेवा को प्राथमिकता दी।

ड्यूटी के दौरान डा. हरजोत

न्यूज गैलरी

विशेष उड़ानों की सीमा 30 से बढ़ाकर 60 की गई

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने भारत और ब्रिटेन के बीच संचालित होने वाली विशेष उड़ानों की सीमा 16 अगस्त से प्रति सप्ताह 30 से बढ़ाकर 60 कर दी है। मंत्रालय का यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर-राज्य परिषद सचिवालय के सचिव संजीव गुप्ता द्वारा ट्विटर पर शिकायत किए जाने के पांच दिन बाद आया है। गुप्ता ने शिकायत की थी कि 26 अगस्त को 'ब्रिटिश एयरवेज', 'एयर इंडिया' और 'विस्तारा' की दिल्ली-लंदन उड़ानों की 'इकोनामी-क्लास' की एक टिकट की कीमत 1.2 लाख रुपये से 3.95 लाख रुपये की आ रही थी। (प्रेट्र)

वायरस उत्पत्ति की एनआइए जांच की मांग खारिज

नई दिल्ली : चीन से कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति और प्रसार की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से जांच कराने मांग को लेकर दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। पूर्व स्वास्थ्य और सेवा महानिदेशक डा. जगदीश प्रसाद ने यह याचिका दायर की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने कहा कि याचिका अनुमान पर आधारित है। (जासं)

कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी दिलाने की कोशिश जारी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में डब्ल्यूएचओ की मुख्य विज्ञानी डा. सौम्या स्वामीनाथन से मुलाकात कर कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी के मामले पर चर्चा की। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक डा. सौम्या स्वामीनाथन से मुलाकात की और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए वैश्विक स्वास्थ्य निकाय की मंजूरी पर चर्चा की।

मंडाविया ने एक ट्वीट कर बताया कि उन्होंने डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक डा. सौम्या स्वामीनाथन के साथ बैठक की। इस बैठक में हम लोगों ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर सार्थक चर्चा की। बैठक में डा. सौम्या ने कोरोना की रोकथाम के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

पिछले महीने राज्यसभा को बताया गया था कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची (ईयूएल) में शामिल कराने के लिए नौ जुलाई तक सभी आवश्यक दस्तावेज विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को सौंपे जा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लिखित उत्तर में कहा कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 9 जुलाई 2021 तक ईयूएल के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज डब्ल्यूएचओ को जमा कर दिए गए हैं। समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईयूएल सबमिशन पर निर्णय लेने में छह सप्ताह तक का समय लेता है।

आयुष्मान भारत के तहत दो करोड़ लोगों ने अस्पताल में कराया इलाज

नई दिल्ली, एएनआइ : कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब परिवारों के स्वास्थ्य खर्च का बोझ साझा करते हुए आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र ने अभी तक देश भर में करीब 24,683 करोड़ रुपये के 1.99 करोड़ अस्पताल में चल रहे इलाज को अधिकृत किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकार (एनएचए) के आंकड़ों के अनुसार, आज की तारीख तक योजना के तहत लगभग 16.20 करोड़ योग्य पात्रों की पुष्टि की जा चुकी है और उन्हें आयुष्मान कार्ड मुहैया कराया गया है।

एनएचए ने कहा, 'निर्धारित दर के साथ कोविड चिकित्सा एवं डाइग्नोस्टिक जांच के साथ 1,669 प्रक्रिया को मिलाकर 918 हेल्थ बेनीफिट पैकेज (एचबीपी) हैं। अभी तक देश भर में लगभग 23,000 सरकारी और निजी अस्पतालों का एक नेटवर्क एबी पीएम-जेएवाई के साथ सूचीबद्ध है।' हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट में कहा था कि 13 करोड़ से ज्यादा परिवारों को योजना से लाभ मिल सकता है। उन्होंने ट्वीट किया था, 'कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखरेख के लिए उठाए गए कदम के तहत, 18 वर्ष तक के किशोरों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। इसके प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर द्वारा किया जाएगा।'

'टीका प्रमाणपत्र पर देशों में आपसी समझ विकसित हो'

▶ विदेश यात्रा संबंधी कई बातें तथ्यों पर नहीं, अटकलों पर आधारित

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को सुझाव दिया कि विदेश यात्रा को लेकर किसी खास टीके पर जोर देने की बताए देशों के बीच कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र को लेकर कुछ समझ विकसित होनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक चुनौती होगी क्योंकि कुछ देश इस बात पर जोर देंगे कि उनके यहां आने को उनका टीका जरूरी है। जयशंकर ने यह भी उम्मीद जताई कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिलने का संकेत सितंबर में मिल सकता है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) के सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने जोर दिया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत के साथ दुनिया खड़ी रही और खास तौर पर आक्सीजन आपूर्ति एवं दवा की आपूर्ति के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि उन देशों को महामारी की पहली लहर के दौरान भारत ने मदद की थी।

वैश्विक टीका पासपोर्ट और भारतीयों को विदेश यात्रा के दौरान पेश आ रही समस्याओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यात्रा बाधा संबंधी कई बातें तथ्यों पर नहीं, अटकलों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने यहां प्रवेश करने के लिए टीका लगाने पर जोर नहीं देता, वह विमान पर बैठने से पहले आरटी पीसीआर नेगेटिव होने पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सामान्य तौर पर अभी यह (विदेश यात्रा) टीकाकरण आधारित होने की बजाय जांच आधारित होना चाहिए। कोवैक्सीन को लेकर यूरोप में यात्रा करने में कुछ परेशानियों के संबंध में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह स्थिति बदलेगी जब डब्ल्यूएचओ इसे मंजूरी दे देगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर डब्ल्यूएचओ को इस पर विचार करने में दो महीने से कुछ अधिक समय लगता है। कोवैक्सीन ने नौ जुलाई को आवेदन किया है और उन्हें उम्मीद है कि संभवतः सितंबर में कुछ संकेत मिलेगा।

तालमेल की कोशिश : जयशंकर। फाइल फोटो

वैक्सीन लेने से इन्कार करने पर वायुसेना कार्पोरल बर्खास्त

अहमदाबाद, प्रेट्र : वायुसेना ने अपने एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इस कर्मचारी ने कोविड-19 रोधी वैक्सीन लगवाने से इन्कार कर दिया था। वायुसेना में टीकाकरण को सेवा शर्त बनाया गया है।

अतिरिक्त सालिसिटर जनरल देवांग व्यास ने जामनगर गुजरात में वायुसेना कार्पोरल योगेंद्र कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर बुधवार को जस्टिस एजे देसाई और जस्टिस एपी ठाकर की खंडपीठ के सामने दलील देते हुए कहा कि नौ कर्मियों ने टीकाकरण कराने से मना किया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनमें से एक द्वारा जवाब नहीं देने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

कोविड-19 रोधी टीकाकरण के प्रति अनिच्छा जाहिर करने पर नोटिस को चुनौती देने वाली कुमार की याचिका पर हाई कोर्ट ने वायुसेना से नए सिरे से विचार करने को कहा। अंतरिम राहत देते हुए अदालत ने कुमार की याचिका का निपटारा कर दिया। कुमार ने 10 मई को जारी कारण बताओ नोटिस को रद करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। वायुसेना ने नोटिस जारी कर उसे यह बताने के लिए कहा था कि वैक्सीन नहीं लगवाने पर उसको सेवा से क्यों न बर्खास्त कर दिया जाए।

राष्ट्रीय फलक

राजस्थान में मर्यादा भूले मंत्री, बोले-अधिकारियों को लात मारो

जागरण संवाददाता, जयपुर

अपने विवादास्पद बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अब पानी के अवैध कनेक्शन हटाने वाले अधिकारियों को लात मारने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को भला-बूरा कहा और धमकी भी दी।

दरअसल, दो दिन पहले खाचरियावास से मिलने उनके विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइंस की कुछ महिलाएं पहुंची थीं। महिलाओं ने पानी की समस्या बताते हुए कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने उनके पानी के कनेक्शन काट दिए हैं। इस पर खाचरियावास भड़क गए और उन्होंने महिलाओं से कहा,जो अधिकारी पानी का कनेक्शन काटने आए उसको लात मारो, बाकी मैं देख लूंगा । उनके इस बयान से संबंधित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पानी के अवैध कनेक्शन काटने का अभियान चला रखा है । इसके तहत राज्यभर में कनेक्शन काटे जा रहे हैं । लोगों से वैध रूप से पानी के कनेक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है । विधानसभा में जलदाय मंत्री डा. बीडी कल्ला ने पानी के अवैध कनेक्शन काटने की बात कही थी। इसके बाद अधिकारी हरकत में आए। अब जब जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में पानी के कनेक्शन काटे गए तो खाचरियावास भड़क गए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी खाचरियावास विवादास्पद बयान देते रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय उन्होंने कई विवादास्पद बयान दिए थे।

एक बार तो यह तक कह दिया था कि पायलट जब नेकर (अंतःवस्त्र) पहनते थे तो मैं विश्वविद्यालय छात्रसंघ का अध्यक्ष था। उस समय उनके बयान की काफी आलोचना हुई थी।

भाजपा ने बताया शर्मनाक: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने परिवहन मंत्री के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा अब जब अधिकारी पानी के अवैध कनेक्शन काट रहे हैं तो उन्हें धमकी दे रहे हैं ।

प्रताप सिंह खाचरियावास पानी के अवैध कनेक्शन काटे जाने से हुए नाराज

नाम नहीं पुकारा तो भड़के विधायक, बोले-तमीज नहीं

जागरण संवाददाता, बरेली

सजे मंच पर जगह तो मिली मगर, संचालक ने नाम नहीं पुकारा तो भाजपा विधायक को नागवार गुजर गया। गुस्सा इस कदर आया कि माइक छीनकर कह दिया, इंडिगो वालों को तमीज नहीं है। फरीदपुर विधायक डा. श्यामबिहारी लाल के तेवर देख इंडिगो वाले सहमकर पीछे हट गए मगर, उद्घाटन में नाम की चाह तल्खी की चर्चा बन गई।

बिगड़े बोल : डा. श्यामबिहारी लाल

गुरुवार दोपहर को बरेली से मुबंई तक फ्लाइट का उद्घाटन करने के लिए एयरपोर्ट पर कार्यक्रम हुआ। मंच पर प्रदेश के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, फरीदपुर विधायक डा. श्यामबिहारी लाल बैठे हुए थे। दिल्ली और लखनऊ से मंत्रालय के जनप्रतिनिधि, अधिकारी आनलाइन जुड़े थे। इंडिगो की टीम आनलाइन संचालन कर रही थी। संचालक ने मंत्री का आभार जताया। कार्यक्रम में अनुपस्थित बिथरी चैनपुर विधायक राजेश मिश्रा पप्पू, देरी से आए शहर विधायक डा. अरुण कुमार का नाम लेकर स्वागत किया। कार्यक्रम समाप्ति की ओर था। विधायक झटके से मंच से उठे और एयरपोर्ट अथारिटी के निदेशक राजीव कुलश्रेष्ठ से माइक छीनकर बोले- इंडिगो वालों को तमीज नहीं, बुलाकर नाम तक नहीं लिया जा रहा है।

बरेली से मुंबई की फ्लाइट शुरू: गुरुवार से बरेली से मुंबई तक की उड़ान शुरू हो गई। दोपहर करीब 12 बजे इंडिगो की एयरबस एयरपोर्ट पर उतरी। दिल्ली से आनलाइन जुड़े नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एयरपोर्ट पर मौजूद मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उद्घाटन किया। कहा कि जल्द ही लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज एयरपोर्ट को बरेली से जोड़ा जाएगा। नंद गोपाल गुप्ता ने कहा, कानपुर से भी अगले महीने बेंगलुरू और मुंबई की फ्लाइट मिलने लगेगी। बरेली-दिल्ली के लिए सातों दिन फ्लाइट मिलेगी।

प्रधानमंत्री से जोड़ा भाई का रिश्ता, भेजी राखी

अभिषेक मालवीय, सुलतानपुर

रेशम की डोर के साथ भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए उप्र के सुलतानपुर की बबिता यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी के साथ चिट्ठी भी भेजी है। यह भाव मन में तब आया जब बीते पांच अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आयोजित हुए अन्न महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया। तभी से उनका हौसला बढ़ा और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन के लिए गुरुवार को रजिस्टर्ड डाक से उन्होंने पीएम को राखी भेज दी। लक्ष्मणपुर गांव निवासिनी बबिता यादव कहती है कि मोदीजी ने गरीबों-पिछड़ों के सामाजिक उत्थान के लिए जो योजनाएं लागू की हैं उससे आर्थिक उत्थान भी होगा। बबिता यादव का संयुक्त परिवार मात्र 15 बिस्वा की खेती पर निर्भर है। पति मनरेगा मजदूरी करते हैं। वह खुद पारिवारिक कार्यों के साथ पशुपालन करती हैं। चार गायें पाल रखी हैं, जिससे दूध का व्यवसाय करती हैं। वह कहती हैं कि अन्न महोत्सव के बाद उनका व परिवार को मान-सम्मान बढ़ा।

पत्र में लिखी 'मन की बात'

लिखने-पढ़ने में हस्ताक्षर तक सीमित बबिता यादव ने पीएम मोदी को जो पत्र लिखवा कर भेजा है उसमें उनके मन की बातें हैं। संबोधन व अभिवादन के बाद लिखा है कि जबसे मेरी आपसे बात हुई है, एक अलग सा उत्साह है। आपके बढ़ाए हौसले ने जीवनशैली में बदलाव किया है। आपको भाई मान राखी भेज रही हूं, इसे स्वीकार करें। अपनी छोटी बहन पर आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखिएगा।

विज की कोठी पर हमले की साजिश, तलवारें बरामद

जागरण संवाददाता, अंबाला

कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर हमले की साजिश का पता चला है। पुलिस ने 67 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट ले गई, लेकिन पेश करने से पहले कागजी कार्यवाही पूरी कर उन्हें छोड़ दिया।

राज्य के गृह मंत्री अनिल विज बुधवार रात चंद्रपुरी में अपने निजी सहायक (पीए) अजय कुमार का हालचाल पूछ कर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। डंडे, झंडे आदि लेकर खड़े इन लोगों ने मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भीड़ में से किसी ने पीसीआर पर पत्थर फेंका, जिससे शीशा टूट गया। पड़ाव थाना पुलिस ने रमिंद्र सिंह, विक्की, हरदीप सिंह, प्रीत, मेजर, आदित्य, अमन के खिलाफ केस दर्ज किया और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इन लोगों ने आधी रात को ही अंबाला-दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया। सुबह होते ये लोग शास्त्री कालोनी स्थित विज के आवास के नजदीक पहुंचे और हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस को सूचना थी कि गृह मंत्री की कोठी पर हमले की साजिश है। लिहाजा विज को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। फिर भी वे सदर बाजार चौक पर चाय पीने आए। गुरुवार सुबह जाम लगा रहे किसानों के पास से तलवारें और डंडे मिले हैं। पुलिस को पहले से ही आशंका थी कि मंत्री विज पर भी हमला किया जा सकता है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद पहले शंभू टोल पर और फिर अंबाला शहर पुलिस लाइन में आंदोलनकारी एकत्रित हो गए। इनकी मांग थी कि मुकदमा रद कर आंदोलनकारी को उनके घर छोड़ा जाए। भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत के पहुंचने की अटकलें रहीं, लेकिन वह नहीं आए।

गर्भ में पल रहे बच्चे को रक्त चढ़ाकर बचाया

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

उपलब्धि

▶ मां के गर्भनाल में सूई से छेद कर अजन्मे बच्चे को की गई रक्त की आपूर्ति

▶ बच्चे के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटकर तीन पर आ गई थी

चिकित्सा जगत में कोलकाता ने एक और मिसाल कायम की है। मां के पेट में पल रहे बच्चे को रक्त चढ़ाकर उसकी जान बचाई गई है। अपोलो हास्पिटल के डाक्टरों की टीम ने इस बेहद दुर्लभ व जटिल आपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

24 हफ्ते की गर्भवती बर्द्धमान की रीमा चाकलादार नियमित चेकअप के दौरान सोनोग्राफी कराने अस्पताल आई थीं। जांच में पता चला कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का रक्त पानी हो गया है और पेट, सीने में जम गया है। चिकित्सकीय भाषा में इस बीमारी को 'फिटल हाईड्राप्स' के नाम से जाना जाता है। अजन्मे बच्चे की जान बचाने के लिए उसे तुरंत रक्त चढ़ाने की जरूरत थी।

इतने जटिल मामले के लिए विशेष मेडिकल टीम गठित की गई, जिसमें डा. सीताराम मूर्ति पाल, डा. कांचन मुखोपाध्याय, डा. सुमना हक और डाक्टर मल्लीनाथ मुखोपाध्याय शामिल थे। इनकी देखरेख में मां के गर्भनाल में सूई से छेद करके अजन्मे बच्चे को रक्त की आपूर्ति की गई। अभी करीब 200 मिलीलीटर रक्त चढ़ाया गया है।

आगे और भी रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। रक्त चढ़ाने के लिए भी अलग से मेडिकल टीम गठित की गई थी, जिसमें डा. सुदीप्त शेखर दास, डा. जयंत कुमार गुप्त और डा. श्यामाशीष बंद्योपाध्याय शामिल थे।

फिटल हाईड्राप्स की यह है वजह: अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. कांचन मुखोपाध्याय ने बताया कि पेट में भ्रूण के रूप में पल रहे बच्चे की मां का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव और पिता का बी पाजिटिव है। ऐसे मामलों में पहली बार गर्भधारण करने पर आम तौर पर कोई समस्या नहीं होती। रीमा की पहली संतान पाजिटिव ब्लड ग्रुप वाली है, जिसकी उम्र अभी नौ साल है। दूसरी संतान के भी पाजिटिव ब्लड ग्रुप वाली होने पर इस तरह की गंभीर समस्या हो सकती है, जैसा कि रीमा के मामले में देखने को मिला है। बच्चे के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटकर तीन पर आ गई थी, जबकि यह सामान्य तौर पर 12 के आसपास होनी चाहिए। रीमा के बच्चे का ब्लड ग्रुप पाजिटिव है। पहले बच्चे के जन्म के बाद उसके शरीर में कुछ पाजिटिव ब्लड सेल आ गए थे।

हालांकि, शरीर में उससे लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो गई थी, लेकिन दूसरी बार भी पाजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा गर्भ में आया तो उसकी प्रतिरोधी क्षमता ने उस ब्लड सेल को मारना शुरू कर दिया। इस वजह से बच्चे का खून पानी में तब्दील होने लगा। डा. श्यामाशीष बंद्योपाध्याय ने कहा कि विदेश में फिटल हाईड्राप्स के खतरे को टालने के लिए टीकाकरण किया जाता है। प्रत्येक महिला को प्रथम गर्भधारण के समय ही इस बाबत विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। ताकि जच्चा-बच्चों को परेशानी नहीं हो।

'सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों के लिए, सेवानिवृत्त के लिए नहीं'

▶ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों के लिए है न कि परोपकार और उदारता के रूप में सेवानिवृत्त लोगों के लिए। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें एक सेवानिवृत्त लोकसेवक को इस तरह के परिसर को अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि एक सेवानिवृत्त लोक सेवक को अनिश्चितकाल के लिए ऐसे परिसर को अपने पास रखने की अनुमति देने का निर्देश बिना किसी नीति के राज्य की उदारता का वितरण है।

केंद्र की अपील मंजूर करते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने हाई कोर्ट का आदेश रद कर दिया और कश्मीरी प्रवासी व खुफिया ब्यूरो (आइबी) के सेवानिवृत्त अधिकारी को 31 अक्टूबर, 2021 या उससे पहले परिसर को खाली कर कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने केंद्र को 15 नवंबर, 2021 तक उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जो सेवानिवृत्ति के बाद हाई कोर्टों के आदेशों के आधार पर सरकारी आवास रह रहे हैं। इस मामले में आइबी अधिकारी को फरीदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां उन्हें एक सरकारी आवास आवंटित किया गया था। अधिकारी 31 अक्टूबर, 2006 को सेवानिवृत्त हुए थे। शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह हाई कोर्ट की खंडपीठ के जुलाई, 2011 के उस आदेश के खिलाफ अपील पर यह फैसला सुनाया जिसने अपने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी थी। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि सेवानिवृत्त अधिकारी का अपने राज्य में लौटना संभव नहीं है।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री 45 फीसद बढ़ी

नई दिल्ली : देश में में यात्री वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में 45 फीसद बढ़कर 2,64,442 यूनिट हो गई, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 1,82,779 यूनिट थी। यात्री वाहनों में कार, यूटिलिटी व्हीकल्स और वैन शामिल हैं। सियाम के अनुसार दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में दो फीसद घटकर 12,53,937 यूनिट रह गई, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 12,81,354 यूनिट थी। (प्रेट्र)

दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। उद्योग जगत को नई टेक्नोलाजी, कौशल विकास और अनुसंधान पर पर्याप्त खर्च करना चाहिए।
अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलोग्राम	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
54,843.98	16,325.15	₹ 45,560	₹ 61,313	₹ 74.25	$ 71.56
▲ 318.05	▲ 82.15	▲ ₹ 422	▲ ₹ 113	▼ ₹ 0.19	

'सभी कारोबारी क्षेत्रों में दिखने लगा सुधार'

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : एफएमसीजी से लेकर होटल तक का कारोबार करने वाली अग्रणी घरेलू कंपनी आइटीसी लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि सभी कारोबारी श्रेणियों में स्पष्ट तौर पर सुधार दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जहां बाधा बनी हुई हैं।

कंपनी के चेयरमैन एवं एमडी संजीव पुरी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के बीच आगे बढ़ रही है। वहीं, आधुनिक व्यापार और पारंपरिक कारोबार में भी भरपाई देखी जा सकती है। सभी श्रेणियों में स्पष्ट तौर पर सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य और स्वच्छता उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हुई थी। हालांकि इनमें अब थोड़ी नरमी आई है, जो उम्मीदों के अनुरूप ही है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के कारण निकट भविष्य में अनिश्चितता है। पुरी ने कहा कि कंपनी की भविष्य में करीब 15,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है। उन्होंने होटल व्यापार को लेकर कहा कि यह क्षेत्र महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कंपनी इसके लिए नए सिरे से रणनीति बना रही है।

इकोनामी की रिकवरी को लेकर सरकार प्रतिबद्ध : वित्त मंत्री

सभी राज्यों को इस वर्ष समय पर जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूत होती दिख रही है और कोरोना काल में सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए, उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। उद्योग संगठन सीआइआइ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों के साथ संवाद में वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष शुरुआती पांच महीनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) में 37 फीसद की बढ़ोतरी हुई। जुलाई के आखिर में देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 620 अरब डालर के रिकार्ड स्तर को पार कर गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर-अक्टूबर से लेकर अब तक कर्ज के रूप में पांच लाख करोड़ रुपये इकोनामी में डाले गए हैं। पिछले कुछ समय के दौरान निर्यात भी बढ़ रहा है। लोगों का बाजार में भरोसा बढ़ रहा है और

निर्मला सीतारमण ● जागरण आर्काइव

शेयर बाजारों में निवेश के लिए हर महीने तीन लाख नए डीमैट खाते खुल रहे हैं।

सीतारमण ने बताया कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई मोर्चे पर काम किया जा रहा है। टैक्स की वसूली बढ़ रही है। इस वजह से सभी राज्यों को इस वर्ष समय पर जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान हो जाएगा। इससे राज्यों को खर्च करने में आसानी होगी। राजकोषीय घाटे को बजट में तय लक्ष्य के मुताबिक रखा जाएगा। संसद के चालू सत्र में फैक्टरिंग बिल, इंश्योरेंस बिल, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटाने के लिए बिल पारित कराए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश में तेजी है और इस साल एयर इंडिया, बीपीसीएल, कानकोर जैसी कंपनियों के विनिवेश का काम पूरा हो जाएगा। वहीं सार्वजनिक कंपनियों की संपदा के मौद्रीकरण के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इससे उद्यमियों को सरकारी कंपनियों की बेकार पड़ी जमीन मिलेगी। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से निवेश बढ़ाने के लिए भी कहा।

रिन्युएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देखना चाहती है वित्त मंत्री: सीतारमण ने कहा कि वह रिन्युएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर देखना चाहती है। ताकि अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन का त्याग हो सके और भारत में पैनल से लेकर सोलर बैट्री तक का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि भारत में चिप मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता को विकसित करने की जरूरत है।

चीन की नकल कर नहीं बन सकते ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब : अमिताभ कांत

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि चीन की नकल कर देश कभी भी दुनिया का अगला मैन्यूफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता है। भारत को उन क्षेत्रों की ओर नहीं देखना चाहिए, जिनमें चीन का पहले से ही वर्चस्व है। सीआइआइ के कार्यक्रम में कांत का कहना था कि दुनिया का नेतृत्व करने के लिए देश को विकास के उभरते मौकों को पकड़ना होगा। उद्योग जगत को ग्रीन हाइड्रोजन, उच्च गुणवत्ता वाली बैटरी और एडवांस्ड सोलर पैनल के क्षेत्र में स्पर्धात्मक बनना होगा। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं कि पांच वर्षों में इसका दाम एक रुपये प्रति यूनिट तक आ सकता है। अमेरिका व यूरोप करीब 500 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन व ग्रीन अमोनिया का आयात करेंगे। ऐसे में 2030 तक इनके 200 गीगावाट निर्यात का लक्ष्य रखना चाहिए।

'एफटीए के लिए स्पर्धा को तैयार रहना होगा'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसी भी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने के लिए हमें भी उदार दिल दिखाना होगा। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि हम उनके उत्पादों के लिए छूट नहीं दे और उनके साथ एफटीए करार कर लें। इसलिए हमें किफायती होने के साथ अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि हम हर चीज में किफायती और गुणवत्ता वाले नहीं हो सकते।

यूरोपीय संघ के साथ 12-13 वर्ष पहले एफटीए वार्ता की शुरुआत हुई थी और उस संघ ने अपने सदस्य देशों की शराब के लिए भारतीय बाजार को खोलने की मांग की थी। लेकिन उस पर भारतीय शराब निर्माताओं ने विरोध जाहिर किया था। हाल ही में ब्रिटेन के साथ एफटीए की चर्चा चली तब भी शराब निर्माताओं ने ब्रिटेन की सस्ती शराब आने से भारतीय शराब उत्पादन पर प्रतिकूल

पीयूष गोयल ● जागरण आर्काइव

असर पड़ने की आशंका जाहिर की थी। भारत इन दिनों यूएई के साथ एफटीए वार्ता कर रहा है और ब्रिटेन एवं अमेरिका के साथ भी एफटीए की पहल की गई है। सीआइआइ के कार्यक्रम में गोयल ने उद्यमियों से यह भी कहा कि उन्हें घरेलू उत्पादों की खरीदारी को तरजीह देना चाहिए, भले ही वह थोड़ी महंगी ही क्यों न हो। उद्यमियों को जापान और कोरिया से इस मामले में सीखने के लिए कहा जो घरेलू उत्पाद खरीदने को अपनी शान मानते हैं। गोयल ने कारपोरेट जगत से कहा कि वे भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करेंगे तभी एमएसएमई का भला होगा।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने पहुंचाया स्पर्धा को नुकसान : सीसीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर स्पर्धा को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को सही ठहराया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजारों को नौ अगस्त को इसकी जानकारी दी। आयोग ने कहा कि ग्रासिम ने अपनी कैटेगरी में बाजार की शीर्ष कंपनी होने का बेजा लाभ उठाया, यह साबित हो गया है। सीसीआइ के अनुसार ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने अपने ग्राहकों से भेदभावपूर्ण कीमत वसूलकर, बाजार तक पहुंच ना देकर और उन पर पूरक दायित्व थोपकर एक खास स्टेपल फाइबर की आपूर्ति में बाजार में अपने वर्चस्व का बेजा लाभ उठाया है। आयोग ने छह अगस्त के एक आदेश में कंपनी को ऐसे कामों में से दूर होने और उन्हें बंद करने का निर्देश दिया, जिनसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन हुआ है।ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजारों को बताया कि उसके पास ऊपरी अदालत में अपील के लिए पर्याप्त आधार हैं।

सभी भारतीय को चार वर्षों में इंटरनेट से जोड़ेंगे : चंद्रशेखर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : इलेक्ट्रानिक्स व आइटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि वर्ष 2025 तक सभी भारतीय को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह काम मुख्य रूप से ब्राडबैंड इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कारोबार में आसानी के लिए साइबर कानून को आसान बनाया जा रहा है और क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) जैसी उच्च तकनीक पर फोकस किया जा रहा है।

उद्योग संगठन सीआइआइ के कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने बताया कि अगले तीन से पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये टर्नओवर की 500-600 कंपनियां होंगी, जबकि अभी इनकी संख्या मात्र 25 है। उन्होंने निजी क्षेत्रों से इनोवेशन पर फोकस करने का आग्रह करते हुए कहा कि भरोसेमंद और किफायती टेक्नोलाजी कंपनी ही सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकती है।

> आइटी राज्यमंत्री ने कहा कि कारोबार में आसानी के लिए साइबर कानून को सहज बनाया जा रहा है

चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में डाटा की निजता मौलिक अधिकार है और सरकार डाटा सुरक्षा बिल ला रही है। यह फिलहाल संसदीय स्थायी समिति के पास है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले 25 वर्षों में डिजिटल टेक्नोलाजी की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री तकनीक की ताकत की बदौलत प्रशासन को बदल रहे हैं ताकि देशवासी और सरकार व विभिन्न विभागों के बीच अंतर को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों का कभी सरकार से संपर्क नहीं हुआ था, वहां भी कोरोना काल में तकनीक की बदौलत ही लोगों के खाते में सीधे वित्तीय मदद पहुंचाई जा सकी।

चीनी निर्यात 51 लाख टन पर पहुंचा

नई दिल्ली, प्रेट्र : चालू मार्केटिंग वर्ष में चीनी मिलों ने अब तक 51.1 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। आल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन (एआइएसटीए) ने एक बयान में गुरुवार को कहा कि इस वर्ष सितंबर में खत्म हो रहे मार्केटिंग वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा चीनी निर्यात इंडोनेशिया को किया गया है। चीनी मार्केटिंग वर्ष अक्टूबर से शुरू होकर अगले वर्ष सितंबर तक रहता है। चीनी निर्यात का यह आंकड़ा मार्केटिंग वर्ष 2020-21 में पहली अगस्त तक का है। एसोसिएशन के अनुसार करीब 2,02,521 टन चीनी इस वक्त लोडिंग की प्रक्रिया में है।

एआइएसटीए ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष जनवरी में चीनी मिलों को 60 लाख टन चीनी निर्यात की इजाजत दी थी। मिलों ने ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत आठ लाख टन अतिरिक्त चीनी निर्यात की इजाजत ली थी। ओजीएल के तहत निर्यातकों को किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाती है।

जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, खुदरा महंगाई भी कम हुई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जून के औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष जून के मुकाबले 13.6 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जून के दौरान मैन्यूफैक्चरिंग में भी पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 13 फीसद की बढ़ोतरी रही, जो मांग की बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। हालांकि यह बढ़ोतरी बीते वर्ष रही भारी गिरावट के चलते निम्न आधार की वजह से भी है। पिछले वर्ष जून के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 16.6 फीसद की गिरावट हुई थी। वहीं, इस वर्ष जुलाई की खुदरा महंगाई दर गिरावट के साथ 5.59 फीसद रह गई, जो जून में 6.26 फीसद थी। जुलाई में खाने-पीने की चीजों के खुदरा दाम में भी कमी आई। जुलाई में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 3.96 फीसद रही जो जून में 5.15 फीसद थी।

5.59 फीसद रही जुलाई की खुदरा महंगाई दर

13.6 फीसद बढ़ा जून में औद्योगिक उत्पादन

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जून में खनन उत्पादन में पिछले वर्ष इसी माह के मुकाबले 23.1 फीसद, बिजली में 8.3, प्राइमरी गुड्स में 12, इंटरमीडिएट गुड्स में 22.6, कंस्ट्रक्शन गुड्स में 19.1 और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 30 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कैपिटल गुड्स के उत्पादन में इस वर्ष जून में हुआ 25.7% का इजाफा यह संकेत दे रहा है कि कंपनियां मैन्यूफैक्चरिंग में ताजा निवेश कर रही हैं। जून में कंज्यूमर नान ड्यूरेबल गुड्स के उत्पादन में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 4.5% की गिरावट रही।

इस वर्ष जुलाई में सब्जी, अनाज व चीनी के दाम में कमी आने से खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर में नरमी का रुख रहा। सब्जी के खुदरा दाम में पिछले वर्ष जुलाई के मुकाबले 7.75%, अनाज में 1.75 और चीनी में 0.52% की गिरावट रही। वहीं, जुलाई में खाद्य तेल व वनस्पति के खुदरा दाम में पिछले वर्ष जुलाई के मुकाबले 32.53%, अंडे के दाम में 20.82, मांस-मछली में 8.33, फल में 8.9 व दाल की खुदरा कीमतों में 9.04% की बढ़ोतरी रही।

बड़ी कंपनियों में खरीदारी से बाजार नए रिकार्ड की ओर

मुंबई, प्रेट्र: आइटी व बैंकिंग क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों में निवेशकों की खास दिलचस्पी से घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को तेज उछाल दर्ज किया गया। डालर के मुकाबले रुपये की मजबूती ने भी निवेशकों का मनोबल ऊंचा किया। दिन के कारोबार के आखिर में बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 318.05 अंकों यानी 0.58 फीसद के उछाल के साथ 54,843.98 के नए रिकार्ड पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में सेंसेक्स 54,874.10 की शीर्ष ऊंचाई तक चला गया था। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला निफ्टी भी 82.15 अंक यानी 0.26 फीसद सुधरकर 16,325.15 के नए रिकार्ड पर जाकर बंद हुआ।

गुरुवार को सेंसेक्स पैक में सबसे अधिक 6.22 फीसद का उछाल पावरग्रिड के शेयरों में दर्ज किया गया। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टाइटन, एलएंडटी, एनटीपीसी व

सेंसेक्स पैक में सबसे अधिक 6.22 फीसद का उछाल पावरग्रिड के शेयरों में दर्ज किया गया ● फाइल फोटो

आइसीआइसीआइ बैंक के शेयरों में भी मजबूती देखी गई। हालांकि डा. रेड्डीज, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा एसबीआइ के शेयरों में निवेशकों ने मुनाफावसूली की। बीएसई के यूटिलिटीज, पावर, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स व आइटी में 3.11 फीसद का उछाल दर्ज किया गया। बीएसई के मिडकैप व स्मालकैप इंडेक्स 1.97 फीसद तक उछले।

न्यूज गैलरी

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर कोकीन के साथ गिरफ्तार

अहमदाबाद : अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल हवाई अड्डे पर गुजरात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने चार किलो कोकीन के साथ एक अफ्रीकी नागरिक डेरेक पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया। दोहा से मंगाई गई यह कोकीन दिल्ली, अहमदाबाद समेत देश के दूसरे शहरों तक पहुंचाई जानी थी। (राब्यू)

शरद पवार की आवाज में फोन करने वाला गिरफ्तार

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय मंत्रालय को फोन कर वहां के अधिकारी को राकांपा प्रमुख शरद पवार बताने वाले व्यक्ति और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने स्थानांतरण के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी को फोन किया था और राकांपा प्रमुख की आवाज की नकल उतारी थी। उसने आवाज बदलने वाले स्पूफ-काल एप का इस्तेमाल किया था। (प्रेट्र)

उप्र में शराब की आनलाइन बिक्री की अनुमति से इन्कार

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शराब की आनलाइन बिक्री से होम डिलिवरी की अनुमति संबंधी मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने यहा यह आदेश अधिवक्ता गोपालकृष्ण पांडेय की याचिका पर दिया है। अदालत ने कहा कि यह उप्र सरकार का नीतिगत मसला है। (जासं)

खौलते तेल में हाथ डलवा ली ससुरालियों की परीक्षा

अहमदाबाद : पत्नी मायके से लापता हो गई तो कच्छ (गुजरात) निवासी रना कोली ने ससुरालियों पर पत्नी को भगाने का आरोप लगाते हुए खौलते तेल में हाथ डालकर परीक्षा देने को मजबूर कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। (राब्यू)

घोंघा तस्कर के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में दुर्लभ सी कुकूंबर (एक प्रकार का घोंघा) की तस्करी पर मनी लांड्रिंग के आरोप में मामला दर्ज किया है। इसका औषधीय इस्तेमाल होता है। (प्रेट्र)

पत्नी अपने प्रेमी से शादी कर सके इसलिए पति ने दिया तलाक

नईदुनिया, इंदौर

- कुटुम्ब न्यायालय में पहुंचा इंदौर का अनोखा मामला
- आठ साल पहले हुई थी शादी, पांच साल की बेटी रहेगी मां के साथ

आठ साल के वैवाहिक जीवन के बाद जब पति को पता चला कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है तो उसकी प्रेमी से शादी करवाने के लिए पति ने उसे तलाक दे दिया। महिला का अविवाहित प्रेमी भी शादी करने के साथ ही उसकी पांच साल की बेटी को साथ रखने को तैयार हो गया। आपसी सहमति से तलाक लेने पहुंचे दंपती को कुटुम्ब न्यायालय ने पहले तो समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो तलाक के कागज पर मुहर लगा दी।

मामला इंदौर में रहने वाली 28 वर्षीय महिला और उसके पति का है। दोनों की शादी वर्ष 2012 में हुई थी। करीब तीन साल पहले पति को पता चला कि पत्नी किसी और से प्रेम करती है। पति ने पत्नी के उस रिश्ते को समझकर उसे प्रेमी के साथ ही शादी करने के लिए कहा। महिला के मायके और ससुराल वालों ने उसे काफी समझाया। उसकी पांच साल की बच्ची की परवरिश का हवाला दिया। ससुरालवालों ने यह तक कहा कि महिला चाहे तो अलग रह ले, लेकिन महिला ने तलाक लेकर प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करने की बात कही। साथ रहने की कोई संभावना न देखते हुए पति-पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया। कुटुम्ब न्यायालय में दंपती ने एडवोकेट मनोज बिनीवाले के माध्यम से तलाक लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। पत्नी ने स्वीकार किया कि वह किसी और से प्रेम करती है। पति ने भी बताया कि वह तलाक देने को तैयार है। कोर्ट ने पति-पत्नी की बात सुनने के बाद तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली। बिनीवाले के मुताबिक पति-पत्नी ने आपस में यह भी तय किया कि पांच साल की बेटी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ रहेगी।

पोर्न वीडियो मामले में अभिनेत्री गहना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

मुंबई, प्रेट्र : सत्र अदालत ने गुरुवार को पोर्न वीडियो मामले में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। कारोबारी राज कुंद्रा भी मामले के आरोपितों में शुमार है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल ने पिछले सप्ताह अभिनेत्री को गिरफ्तारी से राहत प्रदान करने से इन्कार कर दिया था। जज ने कहा था, 'मौजूदा प्राथमिकी में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। आरोपों और परिस्थितियों के मद्देनजर अंतरिम राहत नहीं प्रदान की जा सकती।' मुंबई पुलिस ने पोर्न फिल्म बनाने और एप के जरिये प्रसारित करने के मामले में कई मुकदमे दर्ज किए हैं। इस मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा व सहयोगी रयान थोर्पे को गत महीने गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने हाल ही में मामले की अन्य आरोपित शर्लिन चोपड़ा की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। राजकुंद्रा की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।

कानपुर के घर में मिले 36 वर्ष पुराने खून के दाग

जागरण संवाददाता, कानपुर : सिख विरोधी दंगे की जांच में जुटी एसआइटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) ने कानपुर में किदवईनगर की तरह दबौली के भी एक मकान में 36 वर्ष बाद मृतकों के खून के दाग ढूंढ़ निकाले। इस घर में पिता-पुत्र की हत्या के बाद दंगाइयों ने डकैती डाली थी। एसआइटी जब मौके पर पहुंची तो यहां दीवारें तो नई दिखीं, लेकिन फर्श पुराना ही नजर आया। इसके बाद बेंजाडीन टेस्ट में खून के दाग स्पष्ट नजर आ गए।

एसआइटी ने बताया कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दबौली एल ब्लाक स्थित घर में भी सरदार तेज सिंह और उनके बेटे सतपाल सिंह की हत्या की गई थी। परिवार के बाकी सदस्यों को दूसरे घरों में छिपकर जान बचानी पड़ी थी। दंगाइयों ने पूरे घर में लूटपाट करके आग लगा दी थी। सुबूतों के अभाव में उस दौरान पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। दो वर्ष पूर्व एसआइटी ने 19 मामलों की जांच शुरू की थी।

असम में ड्रग तस्करी रुकने से खत्म होगा अलगाववाद

कड़ा रुख

नीलू रंजन, नई दिल्ली

असम में ड्रग तस्करी के खिलाफ जारी अभियान से पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय अलगाववादी संगठनों की कमर टूट सकती है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय अलगाववादी संगठनों की फंडिंग का मुख्य स्रोत ड्रग, हथियार और मानव तस्करी के माध्यम से होती है। असम और मिजोरम की सीमा पर खूनी झड़प के पीछे असली वजह असम के इस अभियान को भी माना जा रहा है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने इसके खुलकर संकेत भी दिए थे।

सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले कई दशकों में असम ड्रग तस्करी के म्यांमार, लाओस और थाइलैंड के गोल्डन ट्राइंगल के रास्ते से भारत में भेजे जाने वाले ड्रग का मुख्य पड़ाव बन गया है। म्यांमार से मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के रास्ते ड्रग असम पहुंचाए जाते हैं और यहां से पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ भारत के अन्य इलाकों में इन्हें पहुंचाया जाता है। सीमा से सटे म्यांमार के इलाके में विभिन्न अलगाववादी गुटों के सक्रिय कैंप है, जो तस्करों के लिए मददगार साबित होते हैं। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां आने वाले कुल ड्रग की 25 फीसद खपत पूर्वोत्तर राज्यों में होती है और 75 फीसद भारत के दूसरे भागों में पहुंचाया जाता है। अभियान की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल आठ अगस्त तक 1449 मामलों में 2418 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि 2018 में 455 मामलों में 694 ड्रग तस्कर, 2019 में 826 मामलों में 1226 ड्रग तस्कर और 2020 में 980 मामले में 1652 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किये गये थे।

मानसिक रूप से कमजोर महिला की गवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने किया भरोसा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से कमजोर एक महिला की गवाही पर भरोसा करते हुए दुष्कर्म मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। पीड़िता ने अपने साथ हुई दुष्कर्म की घटना को निचली अदालत में प्रश्नोत्तर रूप में बताया था।

यह घटना सितंबर 2015 में उत्तराखंड में हुई थी। 70 फीसद अशक्त महिला ने निचली अदालत में प्रश्नोत्तर रूप में गवाही दी थी। उसे शपथ नहीं दिलाई जा सकती थी, क्योंकि वह इसे समझने में असमर्थ थी। निचली अदालत ने अक्टूबर 2016 में आरोपित को दोषी ठहराते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जिरह के दौरान महिला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों की सही पहचान की थी।

हाई कोर्ट ने अभियुक्त की अपील मार्च 2019 में खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। अभियुक्त ने उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। पीठ ने कहा कि सुबूत में कुछ विरोधाभास हैं। हालांकि, हमारा मानना है कि महिला की गवाही विश्वसनीय है और वह आइपीसी की धारा 376 (2) (आइ) के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार हो सकती है। न्याय मित्र के रूप में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे एक वकील ने पीठ से कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने और चिकित्सा जांच में देरी के कारण आरोपों की पुष्टि के लिए कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास था।

आसाराम के बेटे नारायण साई को फरलो देने के आदेश पर रोक

झटका

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्म मामले में सजा पा चुके नारायण साई को दो हफ्ते की फरलो प्रदान करने संबंधी गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। नारायण स्वघोषित संत आसाराम बापू का बेटा है। राजस्थान की जेल में बंद आसाराम को भी दुष्कर्म के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने नारायण को नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

सात साल जेल में बिता चुके कैदी को साल में एक बार की फरलो: पीठ ने कहा कि बांबे फरलो व पैरोल नियमों के अनुसार सात साल जेल में बिता चुके कैदी को हर साल एक बार फरलो दी जा सकती है। पीठ ने पूछा कि दिसंबर में जब नारायण को दो हफ्ते की फरलो दी गई थी तब राज्य सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया था?

दोष तय करने के लिए शिनाख्त परेड को ही अकेला आधार न बनाया जाए

नई दिल्ली, प्रेट्र : किसी अपराध मामले में शिनाख्त परेड को ही दोष निर्धारण के लिए अकेला मानदंड नहीं मानना चाहिए। किसी आरोपित को दोषी मानने के लिए अन्य तथ्यों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भी गौर करना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कही है।

इस टिप्पणी के साथ शीर्ष न्यायालय ने डकैती मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को बरी कर दिया। बरी किए गए शख्स दो बार की शिनाख्त परेड में अपराध में शामिल होने के लिए पहचाने गए थे। जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा, इस मामले में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के रुख से उन्हें धक्का लगा है। दोनों ही स्तरों पर शिनाख्त परेड के उद्देश्य को नहीं समझा गया। यह दोषी तक पहुंचने का एक जरिया मात्र है, जैसे कि अन्य सुबूत होते हैं।

अगर बाकी के सुबूत शिनाख्त परेड के परिणाम की पुष्टि नहीं करते हैं तो उस पर गौर करके फैसले पर पहुंचने की जरूरत होती है। इस मामले में सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद पीठ इस निष्कर्ष पहुंची कि डकैती मामले में दोनों लोगों को गलत ढंग से दोषी ठहराया गया। मामले में बरामदगी के बारे में भी अभियोजक ने पर्याप्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी।

ज्ञानवापी मामला : वक्फ बोर्ड ने वापस ली याचिका

जासं, वाराणसी : ज्ञानवापी मामले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में दाखिल निगरानी याचिका को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने वापस ले लिया है। गुरुवार को विशेष न्यायालय में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फ और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ताओं ने बताया कि सिविल जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रिट याचिका दायर की जा चुकी है। ऐसे में यहां दायर निगरानी याचिका वापस ले रहे हैं।

कार्य के प्रति समर्पण है तो परिणाम भी सकारात्मक होगा

सक्षम पीढ़ी तैयार करने वाली शिक्षा नीति

धर्मेंद्र प्रधान

नई शिक्षा नीति भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर पहुंचाने में हमारे नेतृत्व के संकल्प और दृष्टिकोण को दर्शाती है

आठ जुलाई को मैंने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। यह चुनौतीपूर्ण और रोमांचक है। यह अनुभूति केवल इस मंत्रालय के शानदार इतिहास को देखते हुए ही नहीं, अपितु यहां चल रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन के कारण भी है। यह नीति 34 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आई, जो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि एनईपी, 2020 एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका देश के शैक्षणिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इससे आंतरिक बदलाव होगा और संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत के भविष्य को नई दिशा मिलेगी और विश्व में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप चाहें तो कह सकते हैं कि गुणवत्ता, समानता, पहुंच और सामर्थ्य के सिद्धांतों पर तैयार की गई यह नीति हमारी सरकार के लिए एक मार्गदर्शक फलसफा है, एक मूल पाठ है, जो करोड़ों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का एक साधन है।

एनईपी 2020 की पहली विशेषता यह है कि इस नीतिगत उपाय के माध्यम से समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर देकर हम प्री स्कूल से ही एक बच्चे के लिए अधिक सक्षम परिवेश सुनिश्चित करते हैं। एनईपी में सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ा गया है। नई 5+3+3+4 स्कूली शिक्षा प्रणाली के जरिये एक बच्चे को औपचारिक स्कूलों के लिए तैयार किया जाना है। अब तक प्ले स्कूल का विचार मुख्य रूप से शहरों के मध्यम या उच्च वर्ग तक ही सीमित था, क्योंकि वे निजी स्कूलों का खर्च वहन कर सकते थे।

दूसरी विशेषता पहली से ही जुड़ी हुई है कि कौशल और स्कूली शिक्षा (अकादमिक), पाठ्यक्रम संबंधी और पाठ्यक्रम के अलावा मानविकी और विज्ञान के बीच के वर्गीकरण को तोड़कर बहु-विषयकता, वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया गया है। इसमें रचनात्मक संयोजन करने की पूरी संभावना है। उदाहरण के लिए पेंटिंग के साथ गणित विषय का संयोजन।

एक छात्र के जीवन में आने वाले कई प्रकार के तनाव से निपटने के लिए शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर मार्कशीट के बजाय एक समग्र प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। उसमें योग्यता के साथ बच्चे के कौशल, दक्षता, पात्रता और अन्य प्रतिभाओं का आकलन किया जाएगा। हाईस्कूल के प्रत्येक बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। यह छठी कक्षा से शुरू होगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र के लिए कभी भी पाठ्यक्रम को छोड़ने के लिए उपयुक्त प्रमाणन के साथ पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने और छोड़ने के कई विकल्प होंगे।

अवधेश राजपूत

स्कूली शिक्षा के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जो स्वतंत्र रूप से काम करेगा, लेकिन यह सिद्धांतों, मानकों और दिशानिर्देशों की व्यवस्था-नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी एनडीईएआर के माध्यम से आपस में जुड़ा होगा। इससे संपूर्ण डिजिटल शिक्षा ईकोसिस्टम सक्रिय होगा और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पना किए गए इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधारों के लिए आवश्यक है।

एनडीईएआर समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 में भी सहायता करेगी, जिसे अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए इस माह की शुरुआत में 2.94 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय की घोषणा की गई थी। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जो सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के 11.6 लाख स्कूलों, 15.6 करोड़ से अधिक छात्रों और 57 लाख शिक्षकों के लिए है। सभी बाल केंद्रित वित्तीय सहायता डीबीटी के जरिये सीधे छात्रों को प्रदान की जाएगी।

उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) होगा, जो विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) से अर्जित सभी शैक्षणिक क्रेडिट के डिजिटल स्टोरेज की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि इन्हें अंतिम डिग्री में शामिल किया जा सके। इसमें व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण शामिल हैं। विशेष रूप से यह छात्रों के किसी विदेशी संस्थान में एक सेमेस्टर पूरा करने के लिए एनईपी के तहत परिकल्पित विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ने की व्यवस्था में सहायक होगा। विधिक और चिकित्सा संस्थानों को छोड़कर पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों का एक ही नियामक होगा, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (एचईसीआइ) कहा जाता है। यह 'हल्का लेकिन सख्त' नियामक ढांचा सुनिश्चित करेगा।

एनईपी मूक-बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम की सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा (आइएसएल) में तैयार करने के मानकीकरण सहित शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के लिए तीन भाषा नीति की भाषाई दक्षता के माध्यम से ज्ञान अर्थव्यवस्था तैयार करती है। यूनेस्को ने आइएसएल आधारित सामग्री पर विशेष ध्यान देते हुए प्रौद्योगिकी-सक्षम समावेशी शिक्षण सामग्री के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इन सभी पहलों को एक साथ जोड़ने के लिए लैंगिक समावेशन कोष की स्थापना, वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए विशेष शिक्षा जोन के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया जाएगा और राज्यों को बाल भवन या डे बोर्डिंग यानी दिन के लिए बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि एनईपी 2020 विद्यार्थियों की उच्चतम क्षमता और कौशल को बढ़ाएगी। यह नीति विश्व स्तर की शिक्षा प्रणालियों के इतिहास में सबसे अधिक परामर्श प्रक्रियाओं के बाद लाई गई है और भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर पहुंचाने में हमारे नेतृत्व के संकल्प और दृष्टिकोण को दर्शाती है। जैसा कि हम अमृत महोत्सव या भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं, वैसे ही यह नई नीति आज के 5 से 15 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को तैयार करेगी, जो भारत की स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर 30 से 40 वर्ष आयु के होंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा कार्यबल तैयार करने की इस प्रक्रिया में शामिल होने का एक अवसर दिया गया है, जो वैज्ञानिक विचार, आलोचनात्मक सोच और मानवतावाद पर आधारित एक वैश्विक समुदाय का प्रणेता होगा।

(लेखक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं)

response@jagran.com

बेसुरा रुदन

जिस विपक्ष ने अपने हुड़दंग से संसद नहीं चलने दी, वह अब इस बात का रोना रो रहा है कि सरकार ने, स्पीकर ने सदन क्यों नहीं चलने दिए? यह न केवल हास्यास्पद है, बल्कि विचित्र भी। विपक्ष खुद को पीड़ित बताने के लिए ऐसे आरोप भी लगा रहा है कि उसके नेताओं के साथ उच्च सदन में बुरा बर्ताव हुआ। विपक्ष के दुर्भाग्य से इस कथित बुरे बर्ताव का जो वीडियो सामने आया, वह कुछ और ही कहानी कह रहा है। उसमें मार्शल और सांसदों के बीच धक्कामुक्की होती दिख रही है। उसमें यह भी दिख रहा कि कुछ महिला सांसद एक मार्शल को खींच रही हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने यह सफाई दी कि पूरा घटनाक्रम दिखाया जाए। पता नहीं पूरा घटनाक्रम किसी कैमरे में कैद हुआ है या नहीं, लेकिन यह तो सबने देखा है कि कुछ विपक्षी सांसद राज्यसभा सभापति के आसन के समक्ष मेज पर चढ़े हुए थे और बाकी तालियां बजा रहे थे। विडंबना यह है कि ऐसी ओछी-अमर्यादित हरकत का भी विपक्ष बचाव कर रहा है। वास्तव में इसी रवैये के कारण उसके आरोपों पर यकीन करना कठिन हो रहा है। क्या ये वही विपक्ष नहीं, जिसने संसद में मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़े, आसन के समक्ष जाकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराईं?

जो विपक्ष संसदीय नियम-कानूनों की दुहाई दे रहा है, वह वही है, जिसने पहले दिन ही यह जाहिर कर दिया था कि संसद नहीं चलने देनी है और इसी कारण उसने प्रधानमंत्री को यह भी अवसर नहीं दिया कि वह अपने नए मंत्रियों को सदन से परिचित करा सकें। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष यही रट लगाए है कि उसके सारे कृत्य जायज हैं और सारी गलती सत्तापक्ष की है। विपक्ष ने संसद का सत्र न चल पाने और उसके तय समय से पहले खत्म हो जाने के विरोध में सड़क पर मार्च भी निकाला, लेकिन इसे चोरी और सीनाजोरी के अलावा और कुछ कहना कठिन है। विपक्ष में इतनी ईमानदारी होनी ही चाहिए कि यह कह सके कि उसने संसद का मानसून सत्र नहीं चलने दिया। यदि वह यह साबित करने की कोशिश करेगा कि उसकी कोशिश के बावजूद संसद नहीं चलाई गई तो वह हंसी का पात्र ही बनेगा। विपक्ष को यह आभास हो जाए तो बेहतर कि उसने सरकार को घेरने के फेर में खुद को कठघरे में खड़ा करने का काम किया। निःसंदेह संसद चलाते वक्त सत्तापक्ष को विपक्ष की असहमति का सम्मान करना होता है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं होता कि वह अपने संसदीय दायित्व उसे सौंपकर उसके आदेशों का पालन करने लगे। मनमानी किसी की हो, वह चलनी नहीं चाहिए।

मुखरित होती पीड़ा

हरियाणा के आंदोलनकारियों की यह पीड़ा है कि तीनों कृषि सुधार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव पंजाब के आंदोलनकारी नेता अपने स्वार्थ के कारण नहीं मान रहे हैं। यह सत्य है और हरियाणा के किसानों की पीड़ा उचित ही है। उनकी इस बात से असहमत होने का कोई कारण नहीं कि किसी कानून में संशोधन भी प्रकारांतर से नया कानून ही होता है। हरियाणा के किसानों के क्षोभ का एक प्रमुख कारण यह भी है कि आंदोलन में खालिस्तान समर्थक प्रभावी हैं। इसीलिए हरियाणा के किसान नेता स्पष्ट कहते हैं कि हम किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करने नहीं आए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित कराने के लिए कानून बनवाना हमारा उद्देश्य है। विचारणीय है कि हरियाणा के किसान संगठन यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि तीन कृषि सुधार कानूनों को रद करने के बजाय हम उनमें आवश्यक संशोधन करने के पक्षधर हैं।

> कृषि सुधार कानून विरोधी आंदोलन के नेताओं के दुराग्रह के विरोध में हरियाणा के किसान संगठन क्षोभ व्यक्त करने लगे हैं

वे यह भी आरोप लगाते हैं कि अब तक केंद्र सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता हुई और हर बार सरकार ने संशोधन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन पंजाब के आंदोलनकारी नेताओं के कानून रद करने के दुराग्रह के कारण वार्ता निष्फल रही है। वास्तव में हरियाणा के किसान नेताओं को यह समझ में आने लगा है कि इस आंदोलन से नुकसान केवल हरियाणा का और उसके किसानों का हो रहा है। पंजाब अन्य प्रदेशों के नेता अपने स्वार्थ के कारण आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। हरियाणा के किसान संगठन अपनी बात मंच से भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मंच पर पंजाब के किसान संगठनों का कब्जा है, जो अपनी मर्जी से किसी भी नेता को मोर्चे से निलंबित करते रहते हैं। यह भी रेखांकित करने वाली बात है कि आंदोलनकारियों की तरफ से बनाए गए दोनों प्रमुख स्थल हरियाणा में ही हैं। इस कारण दिल्ली मार्ग पर यातायात बाधित रहता है। इससे हरियाणा के किसानों, उद्यमियों, व्यापारियों को हानि हो रही है। हरियाणा के किसान संगठनों को यह बात समझ में आ गई है। वैसे समझ में तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन मुखर नहीं हुए थे। अब मुखर हुए हैं तो निश्चित रूप से परिणाम भी सकारात्मक आएंगे।

खतरे की घंटी को सुनने की जरूरत

डा. सुरजीत सिंह

जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को देखते हुए आर्थिक स्वार्थों को छोड़कर विश्वकल्याण के बारे में सोचना होगा

इंटरगवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) की नई रिपोर्ट मानव जगत के लिए एक चेतावनी है कि अब भी समय है, जब धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए एकजुट हुआ जा सकता है। आज यह हमारी जरूरत नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता भी है। पिछले कुछ महीनों में धरती के अलग-अलग हिस्सों में लोगों ने प्रकृति के जिस रौद्र रूप को देखा, वह अप्रत्याशित नहीं है, बल्कि मानव के अनियोजित विकास के प्रति प्रकृति की नाराजगी है। यह मानव जाति के लिए एक खतरे की घंटी के समान है। रिपोर्ट बताती है कि अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके जिम्मेदार मानव निर्मित कारक ही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमी घटनाओं में वृद्धि के साथ-साथ वर्षा के बदलते पैटर्न ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आज हम एक खतरनाक मोड़ पर हैं। पिछले दो दशकों में आने वाले चक्रवातों की आवृत्ति ही नहीं बढ़ी है, बल्कि उनकी सघनता एवं गहनता भी बहुत बढ़ गई है। सामान्यतः अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते थे, परंतु 2001-2019 तक अरब सागर में 52 प्रतिशत अधिक चक्रवात आए हैं। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों में आठ प्रतिशत की कमी आई है। चक्रवातों के आने की आवृत्ति में भी 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे हवा में अधिक नमी हो जाने के कारण बारिश की मात्रा एवं आवृत्ति भी बढ़ गई है।

विकास की अंधी दौड़ में मानव ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। उद्योगीकरण, शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के कारण अधिक कार्बन उत्सर्जन से 20वीं सदी में पृथ्वी का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसमें 0.6 डिग्री सेल्सियस पिछले तीन दशकों में बढ़ा है। आइपीसीसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 से 2040 के बीच औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा। उल्लेखनीय है कि विश्व की कुल कार्बन डाईआक्साइड का 28 प्रतिशत चीन, 15 प्रतिशत अमेरिका, सात प्रतिशत भारत और पांच प्रतिशत रूस उत्सर्जन करते हैं। कार्बन उत्सर्जन की दर को यदि नहीं रोका गया तो पृथ्वी का तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से जलवायु परिवर्तन पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ सकते हैं, जिन्हें रोकना मानव के बस में नहीं रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक क्षेत्र में तापमान बाकी दुनिया से दो से तीन गुना ज्यादा बढ़ रहा है। आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ लगातार पिघल रही है। शीतोष्ण या भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की तुलना में ठंडे क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहे हैं। पिछले 60 वर्षों में अलास्का लगभग तीन डिग्री फारेनहाइट गर्म हो गया है। साइबेरिया में लैपटेव सागर लगभग बर्फ मुक्त हो चुका है। समुद्र की बर्फ पिघलने के बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सूर्य का ताप जब इस बर्फ से टकराकर वापस लौटता है तो पृथ्वी के औसत तापमान के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। बर्फ पिघलने की स्थिति में समुद्र सीधे सूर्य के ताप को सोखने लगते हैं, जिससे उनका तापमान बढ़ने लगता है। इससे आने वाले वर्षों में चक्रवातों एवं सुनामी की आवृत्ति में और वृद्धि हो जाएगी।

प्रत्येक व्यक्ति पर है धरती को बचाने का दारोमदार। फाइल

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने की स्थिति में बर्फ-मुक्त ग्रीष्मकाल 20 गुना अधिक होने के आसार हैं। 2050 तक दक्षिण-पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में 32.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के 40 से 50 दिनों का अतिरिक्त अनुभव होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विश्व भर में पेयजल संकट, दावानल, सूखा एवं अकाल, गर्म हवाएं, बेमौसम भारी बारिश आदि में बढ़ोतरी हो जाएगी। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। तटीय इलाकों के डूबने से इस सदी के अंत तक दुनिया के 20 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण आशंकित सूखे से सभ्यताएं भी बदल सकती हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक भारत को 1.2 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर का नुकसान हो सकता है। इसके और भी घातक परिणाम होंगे।

जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को देखते हुए हमें अपने आर्थिक स्वार्थों को छोड़कर जनकल्याण एवं विश्वकल्याण के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को इस दिशा में एक साथ कार्य करने की जरूरत है। दुनिया को मिलकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर अधिक ध्यान देना होगा। जितना धन हम जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों से निपटने में लगाते हैं, यदि वही धन ग्लोबल वार्मिंग को रोकने पर व्यय किया जाए तो उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। कम कार्बन उत्सर्जन की तरफ जाने से ग्रीन अर्थव्यवस्थाओं का विकास होगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर अधिक निवेश होगा। साथ ही प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलने से रोजगार भी बढ़ेगा। तकनीकी एवं सामाजिक मुद्दों में समन्वय आज की एक बड़ी आवश्यकता है। सतत विकास में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने से न सिर्फ देशों के बीच, बल्कि राज्य एवं स्थानीय स्तर पर भी लोगों की समझ बढ़ेगी। इसे एक अलग विषय के रूप में मानने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। जीवाश्म ईंधन को जलाना, वनों की कटाई, उद्योगीकरण, प्रदूषण, कार्बन एवं मीथेन उत्सर्जित करने वाले उपकरणों आदि से आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए भी जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ पर्यावरण क्रांति को आज का मंत्र बनाने की जरूरत है।

आज भले ही हम जलवायु परिवर्तन के छोटे प्रभावों से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन यदि समय रहते इस विषय में गंभीरता से नहीं सोचा गया तो हम सभ्यता को विनाश के मुहाने तक ले जाएंगे, जहां सिर्फ महामारियों और विनाश का ही मंजर होगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

नाग देवता

हमारी संस्कृति में आदि काल से ही नाग को आध्यात्मिक आस्था और विश्वास के एक क्रियाशील प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। युगों से भारत में नाग देवता की महिमा का गायन होता रहा है। विविधताओं के साथ देश के सभी भागों में नाग को प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। अनेकानेक कथाओं में नाग के पौराणिक अस्तित्व होने से सहज मान्यताओं का क्रम अनवरत चलता रहा। वस्तुतः जीवन-दर्शन में नाग का संकेत परंपरागत व्यवहारों से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य सा हो गया। देवाधिदेव महादेव शंकर अपने गले में जिसे धारण करते हों, वह स्वतः पावन एवं पूजित हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव के पवित्र माह सावन में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा का विधान है। भगवान शेषनारायण के बारह स्वरूपों की भी स्तुति वंदना नागपंचमी को होती है। इस विशेष दिवस पर जो भी मानव शुद्ध मन से उनका सत्कार करता है, उसे उनसे कभी भय या क्षति की भावना शेष नहीं रहती। इससे मन की कई आशंकाएं मिट जाती हैं।

विश्व समुदाय को आश्चर्य है कि भारत में नागों की पूजा होती है, क्योंकि वे इसके अधिभौतिक दर्शन को नहीं जानते, केवल भौतिक पहचान तक सीमित हैं। नाग देवता माता लक्ष्मी के सेवक हैं। अमूल्य नागमणि एवं दैव निधियों के प्रहरी हैं। महात्माओं ने नाग के किसी भी रूप में शत्रुभाव का निषेध किया है। धर्म वचन है कि उसे शत्रु मानने से अशुभ और मित्र मानने से शुभ होता है। इच्छाधारी नाग का वर्णन ग्रंथों में भी आया है, जो आत्मिक क्रियाओं के निरूपण को व्यक्त करते हैं। सत्यमार्गी प्राणियों के लिए सहायक नागदेव शिव के श्रृंगार हैं। काल के द्योतक नागदेव महाकाल के आभूषण हैं, जो सत्य और शिव के संबंध को प्रकट करता है। विष को कंठ में धारण करने वाले नीलकंठ ने विषधर वासुकि को अपनी कंठमाला बनाकर बड़ा संदेश दिया है कि रामभक्त को विष व्याप्त नहीं हो सकेगा।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

कमजोर होते पहाड़

सुरेंद्र कुमार

> बार-बार विस्फोट करने से पहाड़ों की संरचना कमजोर हो रही है। फलस्वरूप वे आज स्वतः ही खिसक रहे हैं

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगुलसरी में हुए भयानक भूस्खलन यानी पहाड़ों के खिसकने की घटना चिंताजनक है। अभी लोग 25 जुलाई के भयावह भूस्खलन के जख्मों से भी ठीक से नहीं उभरे थे कि उससे भी खौफनाक आपदा बरप गई। करीब एक पखवाड़े के दौरान हिमाचल प्रदेश में दो बार प्राकृतिक आपदाओं का आना किसी बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है। इसने प्रदेश के साथ-साथ समस्त देशवासियों को एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विकास की हमारी दिशा गलत तो नहीं है। यहां तक कि घाटी में सैर-सपाटे के लिए आए पर्यटकों में भी खलबली मची हुई है। वैसे तो राज्य में पहले भी पहाड़ दरकते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी आवृत्ति बढ़ गई है। यदि इस वर्ष की बात की जाए तो प्रदेश में अब तक 31 दुखद भूस्खलन की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। जो गत वर्ष घटित भूस्खलन की 16 घटनाओं से कहीं अधिक हैं।

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि किन्नौर में भूस्खलन की बढ़ रही घटनाओं की मुख्य वजह वहां जल संसाधन का अंधाधुंध दोहन है। जिसने पहाड़ों को खोखला कर दिया है। फलस्वरूप हल्की सी वर्षा भी भारी नुकसान कर दे रही है। ज्ञात हो कि किन्नौर में सतलुज नदी पर ही लगभग 22 पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जा चुका है। इसके लिए जिले में प्रकृति से भारी खिलवाड़ हुआ है। सतलुज नदी किन्नौर की जीवनदायिनी है। इसके बगैर जिले में जीवनयापन नामुमकिन है, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में मानव इतना खो गया है कि उसने वैदिक काल से बह रही सतलुज नदी को भी लगभग 150 किलोमीटर भूमिगत सुरंग में बहने को मजबूर कर दिया है। इससे नदी का दम दिन-रात घुट रहा है। इस स्वजल धारा का अपना एक जीवन है जिसे मानव अपने स्वार्थ के खातिर नष्ट करने पर तुला है। नतीजतन कभी बटसेरी तो कभी निगुलसरी जैसे भयंकर हादसे हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हिमाचल ने विशेष रूप से किन्नौर ने विकास के नाम पर बहुत कुछ खोया है।

दरअसल किसी भी जल विद्युत परियोजना को तैयार करने के लिए पहाड़ों पर सैकड़ों बार विस्फोट करने पड़ते हैं। किन्नौर में 22 जल विद्युत परियोजनाएं तैयार की गई हैं। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि इस आधुनिक खुशहाली के लिए किन्नौर के पहाड़ों पर कितनी बार विस्फोट किए गए होंगे। बार-बार विस्फोट करने से पहाड़ों की संरचना कमजोर होती है। फलस्वरूप वे आज स्वतः ही दरक रहे हैं। जाहिर है यदि हम पहाड़ों को नष्ट करने से अब भी बाज नहीं आए तो भावी पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। अब देखना है कि सरकारें इन दिल दहलाने वाली घटनाओं से कितना सबक लेती हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

भारत को मिले स्थायी सदस्यता

'सुरक्षा परिषद में नए भारत की मौजूदगी' शीर्षक से लिखित आलेख में ऋतुराज सिन्हा ने लिखा है कि जब देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तब विश्व के सबसे ताकतवर मंच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का अवसर मिलना हमारे स्वतंत्रता दिवस के गौरव को और बढ़ा देता है। हालांकि वैश्विक परंपरा के अनुसार अभी भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से ही शिरकत कर रहा है। भारत दो साल तक इसमें रहेगा। इस दौरान भारत को दो बार परिषद की अध्यक्षता का मौका मिलेगा। मोदी सरकार को इस अवसर का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान यदि भारत के किसी फैसले से विश्व में शांति स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिलती है तो यह भारत और मानवता के हित में होगा। इससे हमारी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की दावेदारी और मजबूत होगी। वैसे भी आज भारत जैसा एक लोकतांत्रिक, उदार, सहिष्णु और बहुलतावादी देश सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है तो यह यह विश्व का दुर्भाग्य ही है। भारत का सोच दूसरे देशों से हमेशा अलग रहा है। दुनिया के अन्य देश जहां स्वार्थ से प्रेरित होकर फैसले लेते हैं वहीं भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम (पूरे विश्व को अपना परिवार मानना) की भावना को ध्यान में रखकर कोई काम करता है। यही कारण है कि भारत सरकार के फैसलों से दुनिया के किसी देश को कोई हानि नहीं होती है। कोरोना काल में दुनिया ने भारत के इस रूप को बड़े नजदीक से देखा है। आज यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि भारत शुरुआत से ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होता तो वर्तमान में विश्व समुदाय आतंकवाद, वर्चस्ववाद, अशांति, जलवायु परिवर्तन आदि कई समस्याओं का सामना नहीं कर रहा होता। अब और देर न करते हुए सभी प्रमुख देशों को भारत को इसका स्थायी सदस्य बनाने के लिए आगे आना चाहिए।

विवेक श्रीवास्तव, पटना

मेलबाक्स

दुविधा में प्रदर्शनकारी किसान

बेशक हरियाणा के किसान सीधे सादे हैं, लेकिन यह बात उनकी समझ में आ ही गई कि आंदोलन पर पंजाब के किसानों का एकाधिकार हो गया है। हरियाणा के किसानों को तो मंच से बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को भी अपमानित कर मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया था। दरअसल पंजाब के आंदोलनकारी नेताओं को हरियाणा के किसानों से कोई मोह नहीं है। उन्हें तो धरने के लिए समर्थन चाहिए था। इसीलिए उन्होंने हरियाणा के किसानों को अपने साथ जोड़ने का जुगाड़ किया। बरसों से हरियाणा के किसान सतलुज यमुना लिंक नहर में पानी आने की बाट जोह रहे हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर का जो हिस्सा पंजाब में बना था उसे इन पंजाब के किसानों ने ही पाट दिया था। जब चूल्हा तंदूर जलता है तो आसपास के पड़ोसी भी रोटी सेंकने आ जाते है। ऐसे में उप्र के किसान नेता भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने आ पहुंचे। किसान आंदोलन उद्देश्य से भटक रहा है। किसान नेता अपनी जिद छोड़ें और वार्ता की मेज पर बैठें, ताकि समस्या का समाधान हो सके।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

खिलाड़ियों को मिले सुविधा

टोक्यो ओलंपिक-2020 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों पर राज्यों, खेल संघों, केंद्र सरकार, नियोक्ता संगठनों और अन्य विविध वाणिज्यिक संस्थानों ने जो धनवर्षा की है उस पर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। देश भर में खेल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की आवश्यकता है। खेल जगत के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता है। खेलों का सुधार करने एवं उन्नत तकनीकी से सुसज्जित ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी केंद्र-राज्य सरकारों का दायित्व है। कारपोरेट घराने आगे आकर खेल सुविधाओं में निरंतर वृद्धि करके उभरती प्रतिभाओं के लिए संसाधन जुटा सकती हैं जिनका उपयोग करके खिलाड़ी देश का नाम रोशन करने में योगदान दे सकते हैं। आगामी प्रतिस्पर्धाओं के लिए राज्य सरकारें खेल प्रतिभाओं को तराशने के वास्ते दीर्घकालीन योजनाओं का क्रियान्वयन करें, तभी हम वैश्विक स्तर की पदक तालिका गिनती बढ़ाकर भारत का नाम ऊंचा कर पाने में संभव होंगे।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

... 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 ... हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1.7 करोड़ है देश में ई-स्पोर्ट्स के दर्शकों की संख्या। इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2025 तक इसमें पांच गुना बढ़ोतरी होने की उम्मीद है जिससे यह आंकड़ा साढ़े आठ करोड़ को पार कर सकता है।

अमृत महोत्सव

महिलाओं के लिए समान अधिकारों का आह्वान

अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिलने और देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बतौर पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश स्वाधीन भारत में सभी मतों के अनुयायियों के साथ ही महिलाओं के भी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन कुछ उदाहरण ये दर्शाते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया है। लिहाजा इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। ऐसे में आशा की जानी चाहिए कि आजादी के अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि में आस्था और पंथ से परे नागरिक अधिकारों के समान कानून हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के सूत्रधार बनेंगे

गीता भट्ट
निदेशिका, नान कालेजिएट वूमेंस एजुकेशन बोर्ड, दिल्ली विश्वविद्यालय

सभी मतों और वर्गों की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे सरकार। प्रतीकात्मक

केरल की एक वरिष्ठ नन सिस्टर लूसी ने अपनी साथी नन के साथ एक बिशप द्वारा किए दुष्कर्म के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया। इसके बाद सिस्टर लूसी को वेटिकन की अनुमति से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और पुस्तक प्रकाशित करने जैसे कारण बताकर, चर्च की अवज्ञा करने के लिए न केवल बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षिका के रूप में प्राप्त वेतन से भी वंचित कर दिया गया। देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की बेला पर न केवल एक नन, बल्कि एक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश भी एक भारतीय महिला के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। इस राष्ट्र की सामूहिक चेतना को अंतरावलोकन कर समाज में समान अधिकारों को बहाल करने का आह्वान करना होगा, जो हमारी विरासत के साथ संविधान में भी निहित है।

एक बहुलवादी समाज के रूप में भारत हमेशा समावेशी रहा है, जहां सभी विविधता में सह-अस्तित्व का सम्मान करते हैं। हालांकि बदलते सामाजिक परिवेश में समाज के कई समुदाय स्वयं दमनकारी, रूढ़िवादी प्रथाओं और रीति-रिवाजों पर मंथन कर उन्हें त्यागने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक ऐसी सामाजिक संरचना विकसित हो जो समान मौलिक व नागरिक अधिकारों में विश्वास करती हो। महिलाओं और समाज सुधारकों ने बार बार आगाह किया है कि धार्मिक प्रथाओं की आड़ में, कई रीति-रिवाज लैंगिक भेदभाव करते हैं और महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखतें हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों की 1911 की जनगणना रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय हिंदू कानूनी रूप से बहुविवाह कर सकते थे, लेकिन व्यवहार में यह असामान्य था। हिंदू समुदायों में वैदिक विरासत और रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक संबंधों की पवित्रता जीवनोपरांत भी मानी जाती है। वैवाहिक जीवन में तलाक एक असंभव विकल्प था। बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं ने विवाह में अलग होने का वैध अधिकार दिए जाने की मांग वर्ष 1930 में ही उठाई थी।

भारत की संसद ने वर्ष 1950 के बाद हिंदू कोड बिल के द्वारा हिंदू महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए। इस संदर्भ में 19वीं और 20वीं सदी में प्रतिक्रियावादी ताकतों को दरकिनार करते हुए सामाजिक परिवर्तनों ने भारतीय समाज को रूढ़िवाद से मुक्त किया। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत किए गए संवैधानिक प्रविधान सभी भारतीय नागरिकों को समानता के अधिकार, भेदभाव और शोषण से संरक्षण प्रदान करते हैं। विडंबना यह है कि हमारा संविधान अभी भी सिस्टर लूसी जैसी महिलाओं के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। भारतीय संदर्भ में एक पंथनिरपेक्ष राज्य सर्वधर्म समभाव का पालन करता है, परंतु सभी समुदायों की महिलाओं को समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में शासन की सीमाएं हैं।

समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर कानूनों का सीमांकन वास्तव में एक राष्ट्र के पंथनिरपेक्ष होने पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान सभा में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा भी यह प्रश्न उठाया गया है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे एचसी मुखर्जी जो ईसाई मत के अनुयायी थे, उन्होंने अल्पसंख्यक होने के आधार पर विधानमंडल में सीटों के आरक्षण प्रस्ताव का विरोध किया। संविधान सभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले तजामुल हुसैन ने कहा था कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए हैं और अब 'अल्पसंख्यक' शब्द को हमारे शब्दकोश से हटा देना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान सभा में समान नागरिक अधिकारों पर विचार करते हुए कहा था कि वर्ष 1937 तक उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत जैसे हिस्सों में उत्तराधिकार के मामले में एक ही कानून हिंदुओं और मुसलमानों को शासित करता था। बाबा साहब ने सदन को यह भी बताया था कि केरल के उत्तरी मालाबार में मातृ सत्तात्मक मरुमक्कथायम कानून हिंदुओं के साथ-साथ मुसलमानों पर भी लागू होता था। परंतु रूढ़िवादी सोच और आस्था की ढाल के पीछे छिपकर सभी समुदायों को समान सामाजिक व नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया और समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया।

यद्यपि वर्तमान सरकार ने तलाक कानूनों में असमानता को दूर करने के लिए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक लाकर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की ओर कदम उठाया है, लेकिन बहुविवाह और हलाला जैसे रीति-रिवाज अभी भी लैंगिक न्याय पर हावी हैं। बहुविवाह की स्थिति में, हिंदू से विवाहित महिला के लिए कानून उसके अधिकारों की रक्षा करता है, परंतु मुस्लिम से विवाह करने पर वही कानून लाचार है। पारसी समुदाय की महिलाओं ने भी 1936 के पारसी विवाह और तलाक अधिनियम पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अधिनियम के अनुसार पारसियों के वैवाहिक मुद्दों को विशेष पारसी अदालतों द्वारा निपटाया जाता है जहां न्यायाधीश के साथ पारसी समुदाय से प्रतिनिधि सदस्य भी होते हैं जो न्यायाधीश को सुझाव देते हैं। इसी संदर्भ में पारसी महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और संहिताबद्ध कानूनों के अधीन पारिवारिक अदालतों के तंत्र को लागू करने की अपील की है।

राष्ट्रीय अस्मिता व एकता को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में दिए सार्वभौमिक सिद्धांत, जिनकी परिकल्पना बाबा साहेब आंबेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं द्वारा की गई थी, उन्हें जीवंत करना आवश्यक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि में आस्था और पंथ से परे मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों के समान कानून राष्ट्रीय अस्मिता के सूत्रधार बनेंगे।

प्रगति की ओर बढ़ती यात्रा का उत्सव

श्रीनिवास
राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

भारत सनातन संस्कृति को धारण करने वाला एक प्राचीन राष्ट्र है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास क्रम में भारत पर भी लंबे समय तक विदेशी सत्ता का अधिपत्य रहा। वर्ष 1947 में भारत को स्वाधीनता मिली। आज देश उस स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण करने की ओर बढ़ रहा है। यह आत्मगौरव का विषय है कि हमने लड़ाई लड़कर स्वाधीनता को प्राप्त किया और अब 75वीं वर्षगांठ के उत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। इस उत्सव को अमृतोत्सव की संज्ञा दी गई है।

देश की वर्तमान पीढ़ी एक ऐसे कालखंड की साक्षी बन रही है, जब हमारे सामूहिक आत्म संशय का स्थान राष्ट्रीय आत्मविश्वास ने ले लिया है, जब पश्चिम के पैमानों को दरकिनार कर हम अपनी मौलिकता में अपने अस्तित्व की सार्थकता देखने लगे हैं। यह सभी एक जागते हुए देश की निशानी है। शत्रु सीमा में घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक करना, पूरे दमखम से अनुच्छेद 370 को हटाना, सीएए कानून के माध्यम से प्रताड़ितों को आश्रय देना, राम मंदिर निर्माण से राष्ट्रीय चेतना को वास्तविक अभिव्यक्ति देना, गलवन घाटी में चीन के दांत खट्टे करना आदि ऐसे घटनाक्रम रहे जिन्होंने देश को आत्मविश्वास दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश का एकजुट रहना और अब ओलिंपिक में तिरंगा बुलंद करने वाले देश के युवाओं का स्वागत करना भी यह बताता है कि भारत अपनी विकास यात्रा में स्वर्णिम सोपान के द्वार खटखटा रहा है।

स्वाधीनता के गौरव के साथ हमें अपनी नियति की रिक्तता का भी भान होना चाहिए। हमने सिर्फ भूगोल ही नहीं, अपने आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक व लोक के स्वराज को भी खोया है। यह हमारी मर्मांतक पीड़ा है। ऐसा नहीं कि पिछले सात दशक की हमारी यात्रा उत्साह, आविष्कार और सफलता के लक्ष्य से दूर रही। निश्चित तौर पर भारत ने अपनी सात दशक से अधिक की यात्रा में आश्चर्यचकित करने वाले कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश आज सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है।

भारत उद्योग के क्षेत्र में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है। सभी प्रकार के उद्योग आज भारत में स्थापित हो रहे हैं। आत्मनिर्भरता के आह्वान के साथ देश फार्मा के क्षेत्र में नए आयाम को छूने की ओर अग्रसर है।

भारत ने गत वर्षों में अपनी आंतरिक व बाह्य सुरक्षा को भी मजबूत किया है। हम आज विश्व की सबसे मजबूत सेना तंत्र वाले देशों में शुमार हैं। आने वाले दिनों में कृषि से जुड़े उत्पादन को भी अपनी शक्ति बढ़ाने में देश सफल होगा। अपने परंपरागत ज्ञान व जैव विविधता के साथ भारत भविष्य में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भी अग्रसर होने की तैयारी में जुटा है।

अपने गौरवशाली अतीत के साथ अपने सुनहरे भविष्य के स्वप्न देख रहे भारत के सामने वर्तमान की चुनौतियां भी हैं। अतः जो पाया है उसी में न खोकर जो पाना शेष है उसके लिए पुरुषार्थ करना ही हमें 'संकल्प से सिद्धि' की ओर लेकर जाएगा। इसलिए आने वाले समय में भारत के युवाओं को भारत की वास्तविक पहचान, हिंदुत्व जीवन पद्धति, भारत के गौरवशाली इतिहास, सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर एक सकारात्मक बहस खड़ी करते हुए सही दिशा में बढ़ना पड़ेगा। आज के युवाओं को उन सभी हुतात्माओं के जीवन से प्रेरणा लेनी पड़ेगी जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में हर युवा को अपनी मेधा और नए विचारों से परंपराओं की नींव पर भविष्य का महान भारत खड़ा करना ही होगा। हमारी मूल अस्मिता को बचाने के लिए हमारी पूर्व की पीढ़ियों ने अकल्पनीय बलिदान दिए हैं। आज स्वाधीनता के 75वें वर्ष में हमें यह मन-मस्तिष्क में बैठाना होगा कि हम बलिदान की परंपरा के वारिस हैं।

खरी-खरी

अगले जनम मोहे श्रवण कुमार ही दीजो

मुकेश राठौर

यह देश राम, कृष्ण, भीष्म, नचिकेता और श्रवण कुमार का है। सदियां बीतीं मगर आज भी इन पितृभक्तों की गाथाएं जनमानस की जुबान पर है। हर मां-बाप अपेक्षा करते हैं कि उन्हें भी इन आज्ञाकारी पुत्रों जैसे पुत्र मिले।

बहरहाल गृहग्राम की कोपरेटिव सोसाइटी में क्लर्की पर जमे विद्याधर बाबू अपने इकलौते बेटे का भविष्य संवारने के नेक इरादे से गांव छोड़ शहर चले आए। बेटे के भविष्य के आगे उन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया। सब कहते हैं शहर में भविष्य है। यही सोचकर लाखों लोग भविष्य तलाशते गांव से शहर आते हैं, लेकिन एक भविष्य को ढूंढने में अतीत और वर्तमान दोनों को गंवा बैठते हैं।

उन्होंने बेटे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिला दिलाया। बेटा पढ़-लिखकर उसी शहर में मोटे पैकेज वाली नौकरी में लग गया। शादी की बात आई तो बड़े घर की उच्च शिक्षित बहू भी मिल गई। वह भी जाब वाली। पढ़ा-लिखा लड़का, पैकेज वाली जाब और शहर में सेटल छोटा परिवार।

बेटे के विवाहोपरांत मां-बाप की अपेक्षाएं बढ़ गईं। हालांकि विद्याधर बाबू के बेटा-बहू उनकी हर अपेक्षा पर खरे उतरने हेतु प्रयासरत थे, मगर जब अपेक्षाएं हावी हो तो उपेक्षा का डर सताने लगता है। उपेक्षाओं का क्या है साहब, मोबाइल आने के बाद जुबान, कानों पर और हाथ, आंखों पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाए तो गलत न होगा। यही हो रहा था। विद्याधर बाबू को लगता बहू आने के बाद बेटा बदल गया है। जैसा कि अमूमन हर मां-बाप को लगता है। बेटे को बदलना ही है। वह बेटे से पति जो हो जाता है। श्रीमती विद्याधर को लगता कि उनके तो भाग्य ही फूट गए। जैसा अमूमन बहू आने के बाद होता है। विद्याधर बाबू अच्छे बेटों के उदाहरण देकर कहते, हे ईश्वर, अगले जनम मोहे श्रवण कुमार ही दीजो।

बड़े भारी मन से विद्याधर बाबू ने 20 साल बाद गांव लौटने का मन बनाया। मन ऐसा उचाट हुआ कि बेटे-बहू ने लाख मनाया, मगर वे न माने। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। जब बेटा ही हाथ में न रहा तो शहर में रहकर क्या करते? अंततः उनकी गांव वापसी हो गई। उसी घर में जहां उनके बूढ़े मां-बाप अकेले रहते थे।

ट्वीट-ट्वीट

भारत में ट्विटर ने कांग्रेस और उसके कुछ नेताओं के आधिकारिक हैंडल ब्लाक कर दिए हैं। इस बीच तालिबानी हैंडल रोजाना अपने सैन्य कब्जे और लोगों को मौत के घाट उतारने की अपडेट दिए जा रहे हैं।
स्टैनले जानी@johnstanly

राहुल गांधी पर ट्विटर की कार्रवाई के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम कांग्रेसियों ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर राहुल गांधी की तस्वीर लगा ली है। कांग्रेसियों के मुताबिक इस कवायद का असर देश के दूरदराज के गांवों तक पहुंचेगा और इससे राहुल गांधी के पक्ष में जबरदस्त लहर पैदा होगी।
अभिषेक उपाध्याय@upadhyayabhii

क्रिकेट को ओलिंपिक में शामिल कराने को लेकर आइसीसी के प्रयास निश्चित रूप से स्वागतयोग्य हैं। इसकी आवश्यकता लंबे समय से महसूस हो रही थी। हमें यह समझना होगा कि दुनियाभर में लगभग दो अरब लोग क्रिकेट को बहुत चाव से देखते हैं। भले ही यह कुछ ही देशों में मुख्य रूप से खेला जाता हो, लेकिन इन कुछ देशों की आबादी बहुत अधिक है और इसके दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा है।
विक्रम चंद्रा@vikramchandra

किसी भी ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जिसकी अपने राष्ट्र के प्रति कोई निष्ठा न हो।
प्रणव महाजन@pranavmahajan

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या क्रिकेट को ओलिंपिक में शामिल किया जाना चाहिए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या ट्विटर के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

लड़ते अनपढ़ लोग हैं जो हों तर्कविहीन,
संसद में क्यूं दिख रहा उल्टा-सीधा सीन?
उल्टा-सीधा सीन चल रही खींचातानी,
माननीय चढ़ मेज कर रहे हैं मनमानी।
हम भारत के लोग वोट देते हैं बढ़चढ़,
पर संसद में लोग लड़ें ज्यों लड़ते अनपढ़!
- ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

नई नियुक्ति नियमावली पर छिड़ी रार

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड में सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए घोषित नई नियमावली पर नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा खुलकर इसके विरोध में आ चुकी है तो आजसू सहित कई अन्य संगठन भी इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। कांग्रेस भी एक सुर में नहीं बोल रही है। नई नीति में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां पाने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के झारखंड से ही हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा पास करने की शर्त रखी गई है। इस बाध्यता के साथ ही नियमावली में कुछ भाषाओं को नहीं जोड़ने को लेकर यह रार शुरू हुई है। वैसे नियुक्ति संबंधी पूर्व की नियमावली भी राजनीतिक विवादों के घेरे में ही थी।

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने राज्य के 24 में से 13 जिलों को अधिसूचित जिला करार देते हुए वहां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का निर्णय किया था। स्थानीय की परिभाषा यह तय की गई कि वर्ष 1985 से पूर्व राज्य में निवास करने वाला इस श्रेणी में आएगा। राज्य के 11 जिले गैर-अधिसूचित थे। अब राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन करते हुए नई नीति बनाई है। इसमें सभी 24 जिलों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा 12 स्थानीय भाषाओं की बाध्यता भी है, जिसे लागू किया गया है। इसमें कई ऐसी भाषाएं शामिल नहीं की गई हैं जो राज्य के विभिन्न इलाकों में प्रचलित है।

पक्ष और विपक्ष से यह मांग उठ रही है कि भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका को भी स्थानीय भाषाओं में शुमार किया जाए। राज्य सरकार के एक मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भी बाकायदा इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस में दो स्वर हैं। एक धड़ा छूटी हुई भाषाओं को जोड़ने की मांग कर रहा है तो दूसरा खेमा सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह इसे ऐतिहासिक बता रहा है। उधर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इसे हिंदी पर ही हमला बता दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई नियुक्ति नियमावली का विरोध करते हुए न्यायालय में जाने तक की बात कही है। रघुवर दास का आरोप है कि गठबंधन सरकार ने असंवैधानिक नीति बनाई है। यह राज्य की जातिगत और भाषागत संरचना को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश है। भाजपा ने बांग्ला और ओड़िया भाषा को शामिल करने का स्वागत किया है, लेकिन कुछ भाषाओं की उपेक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। रघुवर दास का दावा है कि उनकी सरकार ने 2016 में पहली से 10वीं तक की परीक्षा पास करने वालों के लिए नौकरी का प्रविधान किया था। भाजपा सरकार ने जेपीएससी और एसएससी की परीक्षा में संताली, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया व अन्य भाषाओं को शामिल किया था।

युवाओं को रोजगार देने के लिए संजीदगी से आगे बढ़ रही प्रदेश सरकार। फाइल

वर्तमान सरकार ने नियुक्तियों को उलझाने की मंशा से नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इसके विपरीत झामुमो रघुवर दास को घेर रही है। झामुमो का दावा है कि रघुवर दास ने कभी भी झारखंड के स्थानीय लोगों के हित की बात नहीं की। नई नीति में आदिवासियों, मूलवासियों, पिछड़ों, दलितों के ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के प्रविधान किए गए हैं। स्थानीय भाषाओं को नई नियमावली में शामिल किया गया है। यह भाजपा को रास नहीं आ रहा है और वह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। झारखंड की नौकरियों पर पहला हक उन्हीं का है जो यहां के स्थानीय लोग हैं। कांग्रेस का एक धड़ा भी इसमें सुर मिला रहा है, लेकिन कुछ विधायक दबी-जुबान इसे ठीक नहीं ठहरा रहे हैं। स्नातक स्तर की नौकरियों के लिए सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए राज्य से ही हाईस्कूल और इंटर पास होने की अनिवार्यता सभी के गले नहीं उतर रही है। आशंका है इससे सामान्य वर्ग भर्तियों की प्रक्रिया में अलग-थलग पड़ सकता है, जो राज्य की बड़ी आबादी का अहम हिस्सा हैं। यह नैसर्गिक न्याय के विपरीत होगा। निर्दलीय विधायक सरयू राय भी नई नीति पर सवाल खड़े कर चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद आई नई नियुक्ति नियमावली को लेकर शुरू हुए राजनीतिक विवाद से राज्य में सरकारी पदों पर भर्ती का सिलसिला थम सकता है, जो चिंता की मूल वजह है।

उल्लेखनीय है कि गठबंधन सरकार ने इस वर्ष को नौकरियों का साल घोषित कर रखा है। हेमंत सोरेन ने हर साल पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। सरकार इस दिशा में काफी संजीदगी से बढ़ रही है और राज्य के विभिन्न विभागों में खाली करीब सवा लाख पदों को भरने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसी स्थिति में नई नियुक्ति नियमावली को लेकर शुरू हुए विवाद का जितनी जल्दी पटाक्षेप हो जाए बेहतर होगा। राजनीतिक स्तर पर इसे सुधारने की मांग सत्तापक्ष-विपक्ष दोनों स्तर पर हो रही है। अगर इसका सर्वमान्य हल नहीं निकाला गया तो राजनीतिक विवाद बढ़ेगा, जो नौकरी की आस लगाए युवाओं और प्रदेश दोनों के हित में नहीं होगा।

मंथन

ई-स्पोर्ट्स को मिले प्रोत्साहन

भारत में ई-स्पोर्ट्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच छोटे शहरों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि अगले साल चीन में आयोजित एशियाई खेलों में पदक हासिल कर सकें

रजनीश मिश्रा
वरिष्ठ पत्रकार

जापान में हुए ओलिंपिक खेलों में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद निगाहें अगले साल चीन में होने वाले एशियाई खेलों पर होंगी। एशियाड में पहली बार पदक स्पर्धाओं में शामिल ई-स्पोर्ट्स में भारत का डंका बजाने का मौका देश के छोटे शहरों की युवा प्रतिभाओं को भी मिल सकता है।

ई-स्पोर्ट्स समेत पूरे आनलाइन गेमिंग क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे भारत के स्टार खिलाड़ी तीर्थ मेहता ने 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई खेलों में पदक जीत कर सनसनी मचा दी थी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दबदबे वाले इस खेल को तब डेमो यानी प्रदर्शन श्रेणी में रखा गया था। तीर्थ ने ई-स्पोर्ट्स की हार्थस्टोन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था।

अगले साल चीन के हांगझू में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम का चयन ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन आफ इंडिया करेगी। इसके निदेशक लोकेश सूजी का कहना है कि टीम चयन से पूर्व आयोजित की जा रही शुरुआती प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूर्वोत्तर के शहरों से भी गजब की युवा प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। मुख्यतः कंप्यूटर और कन्सोल पर खेले जाने वाले इन खेलों में पारंपरिक रूप से बड़े शहरों का दबदबा रहा है, परंतु छोटे स्थानों से प्रतिभाओं के मिलने से उन्हें बहुत हैरत नहीं है। तीर्थ मेहता भी गुजरात के भुज से हैं।

भारत में ई-स्पोर्ट्स ने हाल के वर्षों में तेजी से जगह बनाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले छह साल में ई-स्पोर्ट्स के गेमिंग स्टूडियो की संख्या में पांच गुनी वृद्धि हुई है। अब देश में इसके 14 प्रसारण प्लेटफार्म भी हैं और यह संख्या बढ़ कर 20 हो जाने का अनुमान है। बड़ी युवा आबादी के कारण देश में ई-स्पोर्ट्स के दर्शकों की संख्या भी बहुत है। अभी यह करीब 1.7 करोड़ है और वर्ष 2025 तक इसके पांच गुना बढ़ कर साढ़े आठ करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। खिलाड़ियों की संख्या भी 15 लाख हो जाएगी जिसमें एक बड़ा हिस्सा छोटे शहरों का होगा।

देश में ई-स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगले चार साल में 46 फीसद सालाना की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। तीर्थ मेहता का मानना है कि सुविधाओं में बढ़ोतरी और इस अपेक्षाकृत नए खेल के प्रति सामान्य मानसिकता में बदलाव से छोटे शहरों की प्रतिभाओं को भी उभरने का पूरा मौका मिल सकता है। देशभर से छुपी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए खेल मंत्रालय और भारतीय ओलिंपिक संघ को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

हालांकि भारत में ई-स्पोर्ट्स प्रतिभाओं की भरमार है, पर चयन की औपचारिक संस्थाओं का विस्तार नहीं होने से उनकी तलाश एक कठिन काम है। इस क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियां हैं। लंदन आधारित पेशेवर सेवा प्रदाता 'अर्न्स्ट एंड यंग' और भारतीय व्यापार जगत की अग्रणी संस्था 'फिक्की' की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में आनलाइन गेमिंग क्षेत्र ने वर्ष 2019 के दौरान 40 प्रतिशत और 2020 में 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि की। विशेषज्ञों का मानना है कि बेतहाशा बढ़त के बावजूद देश में इसके समक्ष दो प्रमुख चुनौतियां भी हैं। पहला, गेमिंग संबंधी कानूनों को लेकर स्थिति का पूरी तरह स्पष्ट नहीं होना और दूसरा इसी वजह से कई स्थानों पर इस पर कई तरह के प्रतिबंध आदि का लगना। मात्र तीन साल में ही 'यूनिकार्न स्टेटस' यानी एक अरब डालर के बाजार मूल्य के नजदीक पहुंच चुकी एक बड़ी भारतीय गेमिंग कंपनी एमपीएल के नीति और कानून विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डीजे मैनाक का कहना है कि गेमिंग सेक्टर को प्रतिबंधों नहीं, बल्कि कारगर नियमन की जरूरत है। इसके बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है। कर राजस्व और रोजगार के कई नए अवसर पैदा हो रहे हैं। तेजी से उभर रहे ई-स्पोर्ट्स क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं के आगे बढ़ने के रास्ते भी खुल रहे हैं। भारत ई-स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विश्व फलक पर एक बड़ी ताकत बन सकता है। देश में युवाओं की बड़ी आबादी है और छोटे शहरों के युवा भी उचित मार्गदर्शन मिलने पर बड़ी स्पर्धाओं में अपना हुनर दिखा सकते हैं।

कंप्यूटर और मोबाइल क्रांति ने ई-स्पोर्ट्स के विकास में व्यापक योगदान दिया है। प्रतीकात्मक

नियमन आवश्यक : भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट में स्पाट फिक्सिंग और अन्य तरह के कदाचार के मामले जब सामने आए तो खेल पर ही प्रतिबंध नहीं लगा दिया गया। अगर कुछ समस्याएं हैं भी तो उनको उचित नियमन के जरिये ठीक किया जा सकता है। गेमिंग के विज्ञापनों में लत लगने और वित्तीय जोखिम संबंधी अस्वीकरण अनिवार्य करना भी पूरी तरह सही नहीं है। भारत में लोग अपने कुल आनलाइन समय का मात्र छह प्रतिशत ही गेमिंग पर बिताते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो अधिक लत लगाने वाली और वित्तीय जोखिम वाली हैं, पर उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

ई-स्पोर्ट्स को एशियाई खेलों में पहली बार पदक श्रेणी में रखा गया है। गेमिंग के प्रति नकारात्मकता से इसमें भारत के प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है। अगर आप किसी लोकप्रिय चीज को सीधे सीधे प्रतिबंधित करेंगे तो उसके गैर कानूनी स्वरूप ले लेने की भी आशंका रहेगी। भारतीय कानून कौशल आधारित खेलों यानी गेम्स आफ स्किल्स को प्रतिबंधित नहीं करते। केवल गेम्स आफ चांस को ही प्रतिबंधित करते हैं, जिनके परिणाम पूरी तरह संयोग पर निर्भर करते हैं।

16 अगस्त से भक्तों के लिए खुल जाएगा पुरी जगन्नाथ मंदिर। महाप्रभु के दर्शन-पूजन में फल-फूल, भोग, धूप व दीप ले जाने पर है रोक।

उत्तराखंड

सिंचाई सुविधाओं का विकास

किसानों की आय दोगुना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने खास ध्यान केंद्रित किया हुआ है। इस दिशा में उत्तराखंड में कई कदम उठाए जा रहे हैं। फार्मर्स मशीनरी बैंक के माध्यम से किसानों को कृषि उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं तो उन्नत बीज, खाद का भी इंतजाम किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। निश्चित रूप ये कदम सराहनीय हैं, मगर खेतों में पैदावार बढ़ाने के मद्देनजर सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम करने के मोर्चे पर स्थिति बहुत बेहतर नहीं मानी जा सकती।

आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में कृषि का कुल क्षेत्रफल 6.90 लाख हेक्टेयर है। इसके सापेक्ष 3.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ 43 हजार हेक्टेयर और मैदानी क्षेत्र में 2.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है।

> विषम भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य उत्तराखंड में खेती की तस्वीर संवारने के लिए सरकार को सिंचाई के साधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है

ऐसा नहीं कि राज्य गठन के बाद सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं न बनी हों। सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से बड़े पैमाने पर नहरों आदि का निर्माण हुआ तो नलकूप भी स्थापित किए गए हैं। कागजों पर देखें तो राज्य में 31 हजार किलोमीटर से अधिक नहरों आदि का जाल बिछा हुआ है, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में तो पानी पहुंच रहा है, मगर पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों तक पानी पहुंचाना चुनौती बना है। साफ है कि कहीं न कहीं सिस्टम की नीति और नीयत में खोट है। पूर्व में कई मर्तबा ये शिकायतें आती रही हैं कि एक ही नहर अथवा गूल का कई-कई बार निर्माण दिखाकर बजट ठिकाने लगा दिया गया, जबकि ऐसी बातें भी आती रही हैं कि जिन स्रोतों से गूलें बनाई गई हैं, उनमें गर्मियों में पानी सूख जाता है। शिकायतों पर जांच भी होती है, लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते की भेंट चढ़ जाती हैं। सिस्टम की इन खामियों को दूर कर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है। जब खेतों में पानी पहुंचेगा तो फसलोत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी भी। इस मोर्चे पर प्रभावी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा।

वैसे भी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत सभी राज्यों की मदद कर रही है। प्रदेश सरकार को भी इस दिशा में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से केंद्र के समक्ष रखकर अधिकाधिक योजनाएं हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही योजनाएं ठीक से धरातल पर उतरें, इसके लिए मानीटरिंग की पुख्ता व्यवस्था के साथ ही जवाबदेही तय करनी जरूरी है।

झारखंड

प्रतिभाओं को प्रोत्साहन

झारखंड ने देश के खेल मानचित्र पर अलग स्थान बनाया है। हाकी, तीरंदाजी, क्रिकेट समेत कई खेल प्रतिस्पर्धा में राज्य के खिलाड़ियों ने अपना मुकाम बनाया है। झारखंड की धरती शुरू से ही खिलाड़ियों के लिए उर्वरा भूमि रही है। जयपाल सिंह मुंडा से लेकर निक्की, सलीमा तक कई ऐसे खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाबी पाई है। खेल संसाधनों का विकास और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का यह प्रतिफल है। ओलिंपिक में भाग लेकर लौटी राष्ट्रीय महिला हाकी टीम की दो सदस्यों को जिस प्रकार से राज्य सरकार ने हाथोंहाथ लिया है, वह सराहनीय है।

ओलिंपिक आरंभ होने के पूर्व राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को उत्साहित करने के निमित्त पुरस्कार की योजनाएं तैयार कीं। खिलाड़ियों के टोक्यो से लौटने के पूर्व ही उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से आनेवाली महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा साबित कर दिखाया है कि लगातार मेहनत कर लक्ष्य को पाया जा सकता है। बुधवार को राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा पीठ ठोके जाने से उनका उत्साहवर्धन हुआ है। अगर

टोक्यो ओलिंपिक का हिस्सा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फाइल

> खेल और खिलाड़ियों के प्रति सरकार के उत्साहजनक रवैये से झारखंड की खेल प्रतिभाओं में नई उम्मीद जगी है

खिलाड़ियों को इसी प्रकार संरक्षण मिलता रहा तो वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न खेलों के 22 आवासीय सेंटर चलाए जा रहे हैं। राज्य में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए 96 डे बोर्डिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है। परंपरागत खेल हाकी एवं तीरंदाजी का रांची और दुमका में सेंटर फार एक्सीलेंस संचालित किया जा रहा है। फुटबाल का बोकारो में सेंटर फार एक्सीलेंस है। झारखंड स्टेट स्पोटर्स प्रमोशन सोसायटी का संचालन किया जा रहा है। यहां नौ से 14 वर्ष के बच्चों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके रहने, खाने एवं पढ़ने का सारा खर्च सरकार और सीसीएल संयुक्त रूप से उठाते हैं। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के तहत सरकारी नौकरी देना शुरू किया है। पहले यहां के अच्छे खिलाड़ी रोजगार नहीं मिलने के कारण पलायन कर जाते थे। अब नियुक्ति मिलने से खिलाड़ी दूसरे राज्यों का रुख नहीं करेंगे। इसके अलावा उन खिलाड़ियों का भी खयाल रखना होगा जो आर्थिक अभाव में गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं।

/ हिमाचल प्रदेश /

डराने लगे पहाड़

जितने सुंदर पहाड़ दिखते हैं, उनकी मुसीबतें भी पहाड़ जैसी हैं। पहाड़ कई बार आपदाओं का कारण भी बने हैं। प्रदेश में भूस्खलन एवं पहाड़ का टूटना अब आम होने लगा है। मैदानी जिलों को छोड़ सभी जिलों में पहाड़ टूटने की घटनाएं हो रही हैं। इन हादसों में कई लोगों की जान भी जा रही है। मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी तो दी जा सकती है, लेकिन पहाड़ टूटने या भूस्खलन जैसी घटना की पूर्व में जानकारी दे पाना संभव नहीं है। देखने में पहाड़ मजबूत लगते हैं, लेकिन जिस तरह ये गिर रहे हैं, इससे लगता है कि ये कमजोर होने लगे हैं। इसका कारण प्राकृतिक भी हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे अनियोजित विकास भी एक कारण है।

यह सही है कि कांगड़ा जिला के बोह घाटी के रुलेहड़ गांव में अधिक पानी आने के कारण भूस्खलन हुआ, लेकिन सिरमौर में पिछले दिनों हुआ भूस्खलन या सोलन तथा अन्य जगह पर टूट रहे पहाड़ अनियोजित विकास का ही कारण लगते हैं। किन्नौर जिले में बुधवार को पहाड़ टूटने से एक

दरकते पहाड़ों से सबक लेने का समय। फाइल

> विकास जरूरी है, लेकिन पहाड़ों से छेड़छाड़ करने से पहले तकनीकी पक्ष अवश्य देखे जाने चाहिए

बस समेत करीब छह वाहन दब गए। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोगों को चोटें आई हैं। बचाव कार्य जारी है और कई लोग लापता हैं। चार साल पहले पठानकोट-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी जिले में भी पहाड़ टूटने से दो बसें दबने से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अब वहां पर आइआइटी के प्रशिक्षुओं ने अलार्म सिस्टम लगाया है, जिससे भूस्खलन होने की स्थिति में लोगों को अलार्म से जानकारी मिल जाती है। यह सही है कि विकास के लिए सड़कें अहम हैं। विकास की राह भी सड़कों से निकलती है, लेकिन सड़क निकालने से पहले वहां पर तकनीकी पक्षों को जानना बहुत जरूरी है। अगर पहाड़ को काट कर सड़क निकाली जा रही है तो यह ध्यान रखा जाए कि उसकी बनावट कैसी है, क्या पहाड़ काटने से उसके खिसकने की आशंका तो नहीं होगी? ऐसे तमाम बिंदुओं का अध्ययन किया जाना जरूरी है। अगर पहाड़ कच्चा है तो उसे खिसकने से रोकने के लिए पहले ही प्रबंध किए जाने चाहिए।

बंगाल

हिंसा मामले पर हाई कोर्ट से झटका

बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर उनके नेता एवं मंत्री लगातार नकारते रहे हैं। इसे भाजपा की साजिश करार देते रहे हैं। यहां तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की विशेष समिति ने जांच के बाद हिंसा पर जो रिपोर्ट दी उसे भी गलत बताया गया। परंतु हिंसा हुई है इसका एक और प्रमाण बुधवार को उस समय में सामने आया, जब हाई कोर्ट ने चुनाव नतीजे के बाद से हमले के डर से बेघर लोगों को सकुशल घर वापसी का निर्देश दिया। हाई कोर्ट का यह निर्देश ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने पुलिस को दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में बेघर परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा के साथ तुरंत घर लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट अगले 45 दिनों के भीतर अदालत में पेश करने को कहा गया है। इससे यह साफ हो गया कि बंगाल में चुनाव बाद हालात क्या थे? यह कहीं न कहीं ममता सरकार के उस दावे की पोल खोल दी है कि जिसमें कहा गया था कि चुनाव बाद कोई हिंसा ही नहीं हुई।

> कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में बेघर परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा के साथ उन्हें तुरंत घर लौटाने का आदेश दिया है

दरअसल तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में चुनाव से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों पर हमले शुरू हो गए थे। यहां तक कि डायमंड हार्बर के भाजपा प्रत्याशी तक को नहीं छोड़ा गया था। मतदान के बाद तो और हमले होने लगे। इससे आतंकित हो कर कई परिवार जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर हो गए। पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की तो आठ निवासियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जवाब में तृणमूल विधायक ग्यासुद्दीन मोल्ला ने भी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। मोल्ला ने आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्तियों के घर में हथियारबंद थे। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने बुधवार को डायमंड हार्बर जिला पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने और पीड़ित परिवारों को घर वापस भेजने का निर्देश दिया। यह पहला मामला नहीं है जब बेघर भाजपा कार्यकर्ताओं के घर वापसी के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। इससे पहले महानगर के इंटाली, हुगली, बीरभूम जिले में भी इसी तरह से तृणमूल के आतंक से घर छोड़ने वालों को सुरक्षित घर वापसी का निर्देश दिया था। अभी मुख्य मामले पर फैसला आना बाकी है। पांच जजों की पीठ में सुनवाई पूरी हो चुकी है और एनएचआरसी की विशेष समिति ने जो सिफारिश की है उस पर हाई कोर्ट का क्या आदेश होता यह देखने वाली बात होगी।

श्रद्धा का महासावन

सावन में सब पावन

श्रावण मास अपने आप में विशेष है। भोलेनाथ की उपासना के साथ-साथ यह प्रकृति के श्रृंगार का महीना है। सावन में चारो ओर फैली हरियाली और सावन की रिमझिम घटाएं मन को प्रफुल्लित करती हैं। आनंद और ऊर्जा के प्रवाह से भरे इस महीने में हर किसी का नाचने-गाने-झूमने का मन करता है। शिव का पूजन इस आनंद को अध्यात्म और उपासना की ओर ले जाता है। भगवान भोलेनाथ को यह पावन महीना अत्यंत प्रिय है। शास्त्र बताते हैं कि समुद्र मंथन सावन में ही हुआ था। समुद्र मंथन में तरह-तरह की निधियां निकली थीं। अमृत के साथ विष भी निकला था। लोक कल्याण के लिए शिवजी ने उस विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया। जहर की ज्वाला शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी के ऊपर जलाभिषेक किया। अभिषेक से विष की ज्वाला शांत हुई और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवताओं को इच्छित वरदान दिए। तब से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की परंपरा है। भगवान शंकर का नाम आशुतोष है। लोटाभर जल से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल, बिल्वपत्र चढ़ाने के साथ धतूरा, पंचामृत और अन्य पूजन सामग्रियों से पूजन करने का विधान है। शिव के जलाभिषेक में जल की शक्ति और संरक्षण का संदेश छिपा है। जल की महत्ता का बोध है। जल की तरह बेलपत्र भी शिव को प्रिय है। संदेश यह कि हरे-भरे पेड़-पौधों से नाता बना रहे। वृक्ष नष्ट न होने पाएं। शिव के पूजन के साथ पेड़ों की रक्षा और पौधारोपण का भी संकल्प लें।

गुलाब नंद ओझा
सरदार पंडा, बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

राज्यों को किरायेदारी माडल कानून तत्काल लागू करने की हिदायत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्र ने कहा, मकान मालिकों और किरायेदारों की मुश्किलें दूर करने में मुफीद साबित होगा यह कानून

किरायेदारी माडल कानून (माडल टेनेंसी एक्ट) के अनुरूप राज्यों को तत्काल अपने कानूनों में संशोधन करने की हिदायत दी गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को माडल टेनेंसी एक्ट भेज दिया है। शहरी विकास मंत्रालय का कहना है कि मकान मालिकों और किरायेदारों की मुश्किलों को दूर करने में यह कानून मुफीद साबित होगा। दोनों पक्षों के विवाद को निर्धारित समय में सुलझाने और उनके हितों को संरक्षित करने के लिए राज्यों को एक कानूनी तंत्र स्थापित करना होगा।

इस माडल कानून को लागू करने अथवा नहीं करने का पूरा अधिकार राज्यों की मर्जी पर निर्भर होगा। यह रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीखों से लागू नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में उन मकान मालिकों अथवा दुकान मालिकों को कोई बहुत राहत नहीं मिल सकेगी, जिनकी प्रापर्टी बहुत कम किराये पर उठी हुई है। इस संबंध में विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा।

शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव उन प्रापर्टी के लिए तैयार किया गया है, जिनके मालिक कानूनी विवादों से बचने के लिए उन्हें किराये पर नहीं उठा रहे हैं। राज्यों में इस नए माडल कानून के लागू होने से ऐसे मकान मालिक बेधड़क अपने मकान और दुकान किराये पर उठा सकेंगे। शहरी विकास मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के मुताबिक शहरी इलाकों में लगभग सवा करोड़ प्रापर्टी खाली पड़ी हैं। उनके मालिकों को लगता है कि उनकी प्रापर्टी किराये के बहाने हड़प न ली जाए।

माडल टेनेंसी एक्ट (एमटीए) को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सात जून, 2021 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां लागू करने के लिए भेजा गया था। नए माडल कानून में दोनों पक्षों के हिसाब से प्रविधान किए गए हैं। समझौते में पारदर्शिता के लिए सारी बातों को विस्तार से दिया जाएगा। इसमें मकान मालिक को घर का मुआयना, मरम्मत से जुड़े काम कराने या किसी दूसरे मकसद से आने के लिए 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना होगा। किराया समझौता (रेंट एग्रीमेंट) में दर्ज समयसीमा से पहले किरायेदार को तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि वह लगातार दो महीनों तक किराया देने में विफल रहा हो अथवा प्रापर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। कामर्शियल प्रापर्टी के लिए अधिक से अधिक छह महीने का सिक्यूरिटी डिपाजिट लिया जा सकेगा।

माडल एक्ट के मुताबिक, किराया समझौता खत्म होने के बाद भी मकान खाली नहीं करने वाले किरायेदार से चार गुना तक का मासिक किराया वसूला जा सकेगा। मकान के ढांचे के रखरखाव के लिए मकान मालिक के साथ किरायेदार को भी ध्यान देना होगा। मकान के ढांचे में सुधार करने अथवा मकान की मरम्मत कराने के बाद किराये में वृद्धि करने का अधिकार होगा। इसमें किरायेदार की मंजूरी जरूरी होगी। माडल एक्ट में विवादों के निपटारे के लिए प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। ऐसे मसलों के त्वरित समाधान के लिए किराया अदालतें और किराया न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के तर्रेम गांव को तीन दशक बाद मिली नक्सली खौफ से आजादी

तीन दशक बाद तर्रेम में खुले ग्रामीण सचिवालय में पहुंचने लगे आदिवासी। नईदुनिया

अनिल मिश्रा, जगदलपुर

- फोर्स का कैंप खुलने के बाद इलाके में विकास की शुरू हुई नई गाथा
- सड़क, बिजली, स्कूल, राशन दुकान की मिली सुविधा तो बढ़ा उत्साह

छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के तर्रेम गांव में तीन दशक के बाद नक्सली खौफ से आजादी मिली है। यह वही गांव है, जहां 1992 में नक्सलियों ने पहली बार बारूदी सुरंग का विस्फोट किया था। इसमें पुलिस वैन में सवार जिला बल के 12 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद पुलिस चौकी बंद हो गई। नक्सलियों ने बासागुड़ा से तर्रेम तक 15 किमी सड़क को काट दिया। इसके बाद तर्रेम नक्सली आतंक की अंधी सुरंग में खो गया। अब तीन दशक के बाद फोर्स की मदद से प्रशासन तर्रेम को उसका पुराना गौरव दिलाने की कोशिश कर रहा है। बासागुड़ा से तर्रेम तक दोबारा सड़क बन चुकी है। इस साल एक जनवरी को नया थाना व फोर्स का कैंप स्थापित किया गया है।

तर्रेम में इन दिनों बदलाव की बयार बह रही है। फोर्स के पहुंचने से गांव में बिजली पहुंच गई है। स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, बाजार सबकुछ दोबारा शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत के नवनिर्मित भवन में ग्रामीण सचिवालय शुरू होने पर आदिवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। तर्रेम के आसपास के गांवों में जहां पहले नक्सली स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काला झंडा फहराया करते थे, वहां अब राष्ट्रीय उत्सव की उमंग दिख रही है।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर बसे तर्रेम की पहचान एक जमाने में वनोपज के बड़े केंद्र के रूप में रही है। इसी इलाके के सुकमा जिले का गांव जगरगुंडा भी वनोपज का बड़ा बाजार रहा है। इन दोनों गांवों से महुआ, चिरौंजी, इमली, बांस आदि का बड़ा व्यापार होता था। तर्रेम के साप्ताहिक बाजार से हर हफ्ते दर्जनों ट्रक वनोपज आंध्र प्रदेश की मंडियों को भेजा जाता था। इस मार्ग से होकर दक्षिण भारत के बड़े शहरों के लिए बसें चला करती थीं, लेकिन नक्सलियों ने सब तहस-नहस कर दिया था।

बुरे थे हालात, अब बदल गई तस्वीर : बीजापुर के कलेक्टर रितेश अग्रवाल कहते हैं कि यहां आने के बाद जब तर्रेम का दौरा किया तो आश्रमशाला व स्कूल खंडहर थे। बिजली नहीं थी। राशन के लिए लोग 20-25 किमी दूर पैदल जाते थे। बच्चे 15 किमी दूर बासागुड़ा पढ़ने जाते थे। अब यह गांव समन्वित विकास केंद्र बन गया है। कुछ महीने पहले बिजली पहुंच चुकी है। सड़कों पर सोलर लैंप जगमगा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो गया है। गांव तक एंबुलेंस पहुंच रही है। तर्रेम को देख आसपास के गांवों से भी विकास की मांग उठने लगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इलाके के गांवों के लिए कई विकास कार्यों की घोषणा की है।

सड़क बनाने में कई जवानों ने दी शहादत

बस्तर के आइजी सुंदरराज पी ने बताया कि तर्रेम तक सड़क बनाने में कई जवानों ने शहादत दी है। सड़क बनी तो विकास के दूसरे काम भी हो गए। इलाके की तस्वीर बदल गई। तर्रेम के आगे अब सिलगेर व जगरगुंडा तक सड़क बनाई जा रही है। फोर्स तर्रेम से जगरगुंडा के बीच कुंदेड़, बेदरे आदि गांवों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही है। इसी इलाके के टेकलगुड़ा गांव में बीते तीन अप्रैल को नक्सलियों से मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे। फोर्स फिर भी इलाके की तस्वीर बदलने और लोगों को नक्सलियों के चंगुल से आजाद कराने में जुटी है।

आज से 22 तक चांदी के झूले में विराजेंगे रामलला

- सावन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक भाइयों सहित झूले पर रहेंगे विराजमान
- तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय करेंगे रामलला को समर्पित

21 किग्रा. चांदी से तैयार इसी झूले में झूलेंगे रामलला। एएनआइ

जागरण संवाददाता, अयोध्या

रामलला के लिए चांदी का झूला तैयार हो गया है और सावन शुक्ल पंचमी यानी 13 अगस्त को वैकल्पिक गर्भगृह में उनका झूला पड़ेगा, जिस पर रामलला सहित चारों भाइयों का विग्रह स्थापित कर झुलाया जाएगा। रामलला का झूलनोत्सव सावन की पूर्णिमा यानी 22 अगस्त तक चलेगा। हालांकि रामलला को पहले से ही प्रत्येक वर्ष सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक झूले पर झुलाया जाता रहा है, किंतु वह झूला लकड़ी का था। इस बार श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 21 किलो का चांदी का झूला तैयार कराया है।

493 वर्ष पूर्व भव्यता-दिव्यता का पर्याय राम मंदिर तोड़े जाने के बाद नौ नवंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के साथ ही राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। उसके बाद से न केवल भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है, बल्कि रामलला के दरबार में वे सारे उत्सव होने लगे हैं, जो वैष्णव आस्था के केंद्र पर होने चाहिए तथा जिनसे रामजन्मभूमि शताब्दियों तक वंचित रही है। इसी क्रम में शुक्रवार से रामलला को सावन की परंपरा के अनुरूप झूला झुलाने की तैयारी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय उत्साह से झूले को रामलला को समर्पित करने की तैयारी में हैं। रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्रदास के अनुसार रामलला सहित चारों भाइयों के विग्रह को झूले पर स्थापित किए जाने से पूर्व विशेष पूजन किया जाएगा। सनातन उपासना परंपरा व शास्त्रों के मर्मज्ञ जगद्गुरु रामानुजाचार्य डा. राघवाचार्य के अनुसार यह रामलला के गौरव की वापसी ही नहीं, बल्कि भारतीयता के गौरव की प्रतिष्ठा का क्षण है।

सीआइएससीई इस बार साल में दो बार लेगा बोर्ड परीक्षा

बदलाव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : काउंसिल फार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन (सीआइएससीई) शैक्षणिक सत्र 2021-22 में परीक्षाएं दो सेमेस्टर में आयोजित करेगा। एक सेमेस्टर में 50 प्रतिशत सिलेबस के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। पहले सेमेस्टर की परीक्षा नवंबर और दूसरे सेमेस्टर की मार्च या अप्रैल में होगी। दोनों सेमेस्टर का परीक्षा पैटर्न भी बदला गया है।

सीआइएससीई के अनुसार, पहला सेमेस्टर मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पेपर होगा, जबकि दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा इस पर निर्भर होगी कि उस समय कोरोना महामारी की देश में क्या स्थिति होगी। अगर स्थित सामान्य रही तो आफलाइन परीक्षा होगी, वरना आनलाइन। हर सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र आइसीएसई के लिए 80 अंक और आइएससी के लिए 70 अंक का होगा। नया सिलेबस और परीक्षा पैटर्न सीआइएससीईडाटओरजी पर उपलब्ध है। बोर्ड प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क भी कराएगा। स्थिति अनुकूल होने पर स्कूलों में प्रैक्टिकल होंगे, अन्यथा वर्चुअल मोड में होंगे। स्कूलों को प्रैक्टिकल के अंक अपलोड करने होंगे। स्कूल विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट व आंतरिक मूल्यांकन का रिकार्ड भी रखेंगे।

अब मध्य प्रदेश के जंगलों में भी गूंजेगी बब्बर शेरों की दहाड़

मनोज तिवारी, भोपाल

- गुजरात से मिली हरी झंडी, शेर-शेरनी के दो जोड़े लाए जाएंगे

> गुजरात के चिड़ियाघर से दो युवा शेर-शेरनी लाने की सहमति मिल गई है। भोपाल के वन विहार में उनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी।
> -आलोक कुमार, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में बब्बर शेर (एशियाटिक लायन) लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। वन्य प्राणी अदला-बदली कार्यक्रम के तहत दो शेर और दो शेरनी गुजरात से मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। इन्हें भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में रखा जाएगा। इन्हें खासतौर से वंशवृद्धि के लिए लाया जा रहा है। यदि इसमें सफल रहे, तो इनकी संतानों को खुले जंगल में विशेष बाड़ा बनाकर रखने पर विचार किया जाएगा। बाद में इन्हें जंगल में रखने और इनकी संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में शेरों का आना पर्यटकों के लिए एक और सौगात होगी।

करीब एक साल पहले भेजे गए शेर देने के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए गुजरात वन विभाग ने कुछ दिन पहले ही सहमति पत्र भेज दिया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) ने भी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि दुनिया में सिर्फ गुजरात के गिर अभयारण्य में पाए जाने वाले बब्बर शेर की अगवानी के लिए श्योपुर का कूनो पालपुर नेशनल पार्क 17 साल से तैयार है। बब्बर शेरों को महामारी से बचाने के लिए 1994 में कूनो पालपुर का चयन हुआ था और 2003 में यह तैयार भी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात सरकार को शेर देने के निर्देश दिए हैं, पर तमाम कोशिशों के बाद भी मप्र को शेर नहीं मिले हैं। ऐसे में गुजरात के जूनागढ़ स्थित शक्करबाग जूलाजिकल पार्क से शेर-शेरनी के दो जोड़े देने की सहमति वन विभाग के लिए उम्मीद भरी खबर है। विभाग पर्यटकों को दिखाने के लिए इन्हें वन विहार नेशनल पार्क में रखेगा और यहीं इनकी ब्रीडिंग कराई जाएगी। शेर और शावकों को बाड़ों में रखकर जंगल का वातावरण देने की कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश में अब तक केवल चिड़ियाघर में ही शेरों की ब्रीडिंग (प्रजनन) हुई है। इसमें सफलता पाने वाले इंदौर चिड़ियाघर प्रबंधन और देश के अन्य विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी।

डाक्टर और अधिकारी जाएंगे गुजरात : वन विभाग ने गुजरात से युवा (दो से ढाई साल उम्र) शेर-शेरनी मांगे हैं ताकि आसानी से वंशवृद्धि हो सके। वन विहार के डाक्टर और अधिकारियों का दल शक्करबाग चिड़ियाघर जाएगा और शेरों को पसंद करेगा। इस दौरान उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। स्वस्थ शेरों का ही चयन किया जाएगा।

50 कर्मचारियों और अधिकारियों को भारत ने अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त मजार-ए-शरीफ इलाके से सकुशल निकाल लिया है। भारत सरकार ने यात्रियों को लाने के लिए बुधवार को विशेष विमान भेजा था।

गजनी पर कब्जे के साथ काबुल के और करीब पहुंचा तालिबान

अफगान संकट ▸ आतंकियों के कब्जे में आने वाली यह दसवीं प्रांतीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी से महज 130 किलोमीटर दूर है यह शहर

गवर्नर और पुलिस प्रमुख पर तालिबान से डील करने का आरोप

काबुल, एपी : तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। गजनी प्रांत की राजधानी गजनी सिटी पर भी उसका कब्जा हो गया है। महज एक हफ्ते में आतंकियों के कब्जे में आने वाली यह दसवीं प्रांतीय राजधानी है। इसके साथ ही तालिबान राष्ट्रीय राजधानी काबुल के और करीब पहुंच गया है। काबुल से गजनी 130 किलोमीटर दूर है। कई अन्य शहरों पर भी कब्जे को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, अफगान सरकार ने तालिबान को सत्ता साझा करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने देश में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए यह प्रस्ताव दिया है।

गजनी के सांसद मुहम्मद आरिफ रहमानी ने बताया कि यह शहर आतंकियों के नियंत्रण में आ गया है। गजनी की प्रांतीय परिषद के सदस्य अमानुल्लाह कामरानी ने कहा, शहर के बाहर स्थित दो सैन्य ठिकानों पर अफगान बलों का अब भी नियंत्रण है। उन्होंने कहा, गजनी प्रांत के गवर्नर और पुलिस प्रमुख सरेंडर करने के बाद तालिबान से डील कर फरार हो गए। तालिबान की ओर से जारी वीडियो और फोटो से यह जाहिर होता है कि सौदे के तहत आतंकियों ने गवर्नर के काफिले को रोका नहीं। इधर, हेलमंद की राजधानी लश्कर गाह में अफगान बलों और तालिबान के बीच लड़ाई चल रही है। सुरक्षा बलों ने शहर को घेर रखा है। यहां 45 तालिबान आतंकियों को ढेर किया गया है। समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, कंधार शहर में भी लड़ाई तेज हो गई है। तालिबान ने दावा किया कि उसका कंधार की प्रांतीय जेल पर कब्जा हो चुका है।

- कई दूसरे शहरों पर भी नियंत्रण के लिए चल रही भीषण लड़ाई
- अफगान सरकार ने तालिबान को दिया सत्ता साझा करने का प्रस्ताव

अफगान सुरक्षा बलों से हुई लड़ाई के बाद गजनी शहर स्थित एक चौक पर लगा तालिबान का झंडा। एपी

अफगानिस्तान में तालिबान धीरे-धीरे तमाम प्रांतों पर कब्जा करता चला जा रहा है। इससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। गुरुवार को गजनी शहर के अंदर तालिबान आतंकी गश्त करते देखे गए। ये लोगों की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रहे हैं। एपी

इस कारण अहम है गजनी सिटी

गजनी सिटी पर आतंकियों का कब्जा रणनीतिक रूप से अफगान बलों के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि यह शहर काबुल-कंधार हाइवे पर स्थित है। यह सड़क काबुल को देश के दक्षिणी प्रांतों से जोड़ती है। इस महत्वपूर्ण मार्ग पर आतंकियों का कब्जा होने से सरकारी बलों के आवागमन के साथ ही रसद और सैन्य साजो-सामान की आपूर्ति बाधित हो सकती है।

चार लाख लोग हुए विस्थापित

समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतेरस के प्रवक्ता ने बताया कि अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस देश में इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक करीब चार लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से ज्यादातर गत मई के बाद विस्थापित हुए।

वर्चस्व के साथ बर्बरता भी बढ़ी

एएनआइ के मुताबिक, अफगानिस्तान में वर्चस्व बढ़ने के साथ ही तालिबान की बर्बरता भी बढ़ गई है। कंधार प्रांत में 33 लोगों की हत्या की खबर है। जिन लोगों को मारा गया, उनमें सिविल सोसाइटी के लोग, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता बताए गए हैं।

एक हजार अपराधी किए रिहा

एएनआइ के अनुसार, तालिबान का कई प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा हो गया है। इस आतंकी संगठन ने ऐसे छह शहरों की जेलों में बंद करीब एक हजार अपराधियों को रिहा कर दिया है। रिहा हुए अपराधियों में कई खूंखार आतंकी भी हैं। ये शहर पहले अफगान सरकार के नियंत्रण में थे।

तालिबान के कब्जे में भारतीय वायुसेना का हेलीकाप्टर नहीं

नई दिल्ली, आइएएनएस : विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि तालिबान ने जिस लड़ाकू हेलीकाप्टर पर कब्जा किया है, वह भारतीय वायुसेना का नहीं है। एक दिन पहले यह खबर आई थी कि कुंदुज एयरबेस पर तालिबान ने एक एमआइ-35 हेलीकाप्टर पर कब्जा कर लिया है। तब यह समझा गया था कि यह हेलीकाप्टर अफगानिस्तान को भारत से तोहफे के तौर पर मिले चार हेलीकाप्टरों में से एक है।

हेरात में पुलिस मुख्यालय पर तालिबान का कब्जा

काबुल, एएनआइ: तालिबान ने गुरुवार को हेरात में पुलिस मुख्यालय व देश के तीसरे सबसे बड़े शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। इस बीच, अल जजीरा ने बताया कि तालिबान ने कंधार शहर में प्रवेश कर लिया है। कुछ स्थानीय निवासियों ने मीडिया को बताया कि अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर में स्थिति गंभीर थी, क्योंकि शहर की सीमा के भीतर विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच भारी लड़ाई चल रही थी। तालिबान द्वारा की जा रही मारकाट से देश की स्थिति बुरी तरह बिगड़ रही है। आतंकवादी समूह शहरों और गांवों पर कब्जा कर लोगों को लूटकर मार रहे हैं।

तालिबान के प्रवक्ता की तरह बोल रहे इमरान खान

- कहा, गनी के रहते अफगान सरकार से बात नहीं करेगा तालिबान
- पाकिस्तान को कचरा साफ करने वाला देश समझता है अमेरिका

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान के प्रवक्ता की तरह बात कही है। उन्होंने विदेशी पत्रकारों से बातचीत में कहा, अफगानिस्तान में मौजूदा हालात में राजनीतिक समाधान की उम्मीद बेहद कठिन है। तालिबान अशरफ गनी के राष्ट्रपति रहते सरकार से बात नहीं करेगा। समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, विदेशी पत्रकारों से बातचीत के दौरान इमरान की बौखलाहट भी सामने आई। उन्होंने कहा कि पाक को अमेरिका युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में सिर्फ कचरा साफ करने में उपयोगी समझता है। अमेरिका ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया और पाकिस्तान के साथ अलग बर्ताव कर रहा है। यह बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से जो बाइडन ने अभी तक इमरान से फोन पर बात नहीं की है। इससे वह नाखुश हैं।

तालिबान को पनाह देना बंद करे पाकिस्तान: अमेरिकी रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से फोन पर बात की और कहा, तालिबान आतंकियों को पनाह देना बंद करें। अफगानिस्तान से लगती सीमा पर आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाहों को निशाना बनाएं।

तालिबान का समर्थन कर रहे पाक आतंकी संगठन : अफगानिस्तान में कब्जे को लेकर तालिबान के हमलों में पाक के आतंकी संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद समेत कई पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने तालिबान को आतंकियों की भर्ती में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है।

इमरान खान। फाइल/इंटरनेट मीडिया

पाक पर प्रतिबंध लगाने की उठी मांग

अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों ने तालिबान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इन लोगों का मानना है कि तालिबान के विनाशकारी हमलों के पीछे पाकिस्तान है। अफगान इंटरनेट मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर ट्विटर पर अभियान चला रखा है। इस मांग के समर्थन में बीते चार दिनों में हजारों ट्वीट किए गए हैं।

अफगानिस्तान से हिंदुओं व सिखों को जल्द निकाल सकता है भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत ने फिलहाल तो काबुल स्थित अपने दूतावास को बंद करने या वहां से कर्मचारियों को बुलाने का फैसला नहीं लिया है लेकिन जिस तेजी से तालिबान काबुल के नजदीक पहुंचने लगा है उसको देखते हुए सरकार की भावी योजना भी तैयार है। इसके तहत भारत अपने कर्मचारियों संग वहां बचे अल्पसंख्यकों (हिंदुओं व सिखों) को भी निकाल सकता है। इसका संकेत विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी दे रहे हैं। दरअसल, दुनिया के दूसरे देशों से भी इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि वो भी काबुल स्थित अपने दूतावास को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं।

एक दिन पहले ही अफगानिस्तान के एक बड़े शहर मजार-ए-शरीफ से भारत ने अपने 50 कर्मचारियों व अधिकारियों को सकुशल निकाला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का कहना है कि अफगानिस्तान के हालात काफी चिंताजनक है। हम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमें अभी भी उम्मीद है कि अफगानिस्तान में एक समग्र शांति वार्ता को लेकर सहमति बनेगी। इसके लिए दोहा में गुरुवार को बैठक हो रही है जिसमें भारत भी शामिल हो रहा है।

हमारी मुख्य चिंता वहां महिलाओं व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने को लेकर है। पिछले साल भी 380 अल्पसंख्यकों को निकाल कर भारत लाया गया था। हमारा मिशन अभी भी उनके संपर्क में है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता।

अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के बावजूद भारत अभी वहां अपने काबुल दूतावास को बंद करने नहीं जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को यह मशविरा जरूर दिया गया है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं चालू हैं तब तक उसके जरिए वहां से बाहर निकल लें।

अफगानिस्तान को सैन्य मदद पहुंचाना मुश्किल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

तालिबान जितनी तेजी से अफगानिस्तान में अपनी ताकत बढ़ाने में सफल हो रहा है उसे देखते हुए भारत के लिए अशरफ गनी सरकार के पास सैन्य मदद पहुंचाना आसान नहीं होगा। अफगानिस्तान सरकार के सुरक्षा कर्मी और सैन्य दल पिछले एक महीने के दौरान तालिबान की बढ़ती ताकत रोकने में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। कई शहरों में अफगानी सुरक्षाकर्मी तालिबान से सीधी लड़ाई से पहले ही अपने ठिकाने छोड़ कर भाग खड़े हुए हैं। ऐसे में वहां भेजी जाने वाले किसी भी तरह की सैन्य मदद पर तालिबान का कब्जा होने का खतरा है।

इस तरह की सूचना भी आ रही है कि उत्तरी अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबान ने सरकारी सुरक्षाकर्मियों से जो अमेरिकी वाहन लूटे थे उसी पर सवार हो कर वे दूसरे शहरों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े हैं।

बिगड़ते हालात

- मदद में भेजे गए हथियारों के तालिबान के हाथ लगने का खतरा
- बिना मुकाबला किए मैदान छोड़ कर भाग रहे अफगान सुरक्षा कर्मी

अरिंदम बागची। फाइल/ इंटरनेट मीडिया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब यह पूछा गया कि क्या भारत अफगानिस्तान को सैन्य मदद भेजेगा तो उनका जवाब था कि, इस तरह की मीडिया रिपोर्टों का वे जवाब नहीं देंगे। उन्होंने मीडिया में आई इस तरह की खबरों पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जिसमें भारत की तरफ से अफगानिस्तान को भेंट किए गए एमआइ-35 हेलीकाप्टरों के तालिबान के कब्जे में जाने की बात कही गई है।

बागची ने कहा कि हमने मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट देखी है लेकिन हमें इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान और भारत के बीच वर्ष 2011 में की गई रणनीतिक साझेदारी का भी हवाला दिया है लेकिन दूसरे कूटनीतिक सूत्रों ने दैनिक जागरण को बताया है कि जमीनी हकीकत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वहां के सरकारी सैन्यकर्मियों को अभी गोला-बारूद या दूसरे हथियारों की अभी जरूरत नहीं है। कई प्रांतों में वहां की स्थानीय सरकारें अपने स्तर पर तालिबान से बात कर रही हैं और उन्हें आसानी से नियंत्रण सौंपा जा रहा है। ऐसे में बाहरी सैन्य मदद की उन्हें दरकार नहीं है और साथ ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये हथियार या सैन्य मदद तालिबान के हाथ नहीं लगेंगे।

सनद रहे कि भारत ने पिछले बीस वर्षों में अफगानिस्तान में एक व्यवस्थित सैन्य ढांचा बनाने में कई तरह से मदद देने का काम किया है। वहां के सैन्यकर्मियों व सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देने के साथ भारत ने हेलीकाप्टर व दूसरे साजोसमान भी दिये हैं। हाल ही में नई दिल्ली में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई ने दैनिक जागरण से कहा था कि आने वाले दिनों में भारत से सैन्य हेलीकाप्टर व दूसरे उपकरणों की मदद मांगी जा सकती है। लेकिन अब लगता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी।

क्वाड की बैठक में ताइवान गलियारे पर चर्चा

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- अधिकारियों ने चीन को सबसे ज्यादा चुभने वाला मुद्दा उठाया
- मोदी, बाइडन, सुगा और मारीसन के बीच जल्द होगी बैठक

चीन के आक्रामक व्यवहार के खिलाफ चार देशों अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया और जापान के गठबंधन क्वाड की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ती जा रही है। गुरुवार को इस गठबंधन के तहत चारों देशों के विदेश मंत्रालयों के आला अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के केंद्र में चीन से जुड़े मुद्दे ही रहे। क्वाड की बैठकों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और वहां चीन के वर्चस्व को लेकर चर्चा पहले होती रही है, लेकिन इस बार ताइवान गलियारे का मुद्दा भी खास तौर पर उठा। ताइवान गलियारा वैसे तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र का ही एक हिस्सा है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में पहली बार इसका जिक्र कर चीन को संकेत दिया है कि क्वाड के देश ताइवान के मुद्दे को लेकर भी मुखर होंगे। चीन की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, वार्ता में कोरोना के प्रभाव, महामारी पर रोक लगाने को लेकर साझा दायित्व, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति व अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार को लेकर विमर्श हुआ है। क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं (पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, आस्ट्रेलिया के पीएम स्काट मारीसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा) की मार्च 2021 में हुई ऐतिहासिक बैठक में वैक्सीन को लेकर किए गए फैसले की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। इसके तहत बड़े पैमाने पर भारत में कोरोना वैक्सीन का निर्माण होना है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने ताइवान गलियारे में शांति व सुरक्षा के महत्व पर बात की है। चारों देशों के बीच निकट भविष्य में शीर्ष नेताओं की आमने-सामने की बैठक को लेकर बात हुई है। माना जाता है कि सितंबर, 2021 में संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरान यह बैठक हो सकती है।

वहीं, जापान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और सभी के लिए समान अवसर वाला क्षेत्र बनाने को लेकर बात हुई है। यह एक ऐसा मुद्दा बन गया है, जिसे अब यूरोप और आसियान के देश भी मानने लगे हैं। जापान ने यह भी बताया है कि सदस्य देशों के बीच क्वाड का विस्तार करने और समान विचारधारा वाले देशों को इसमें शामिल करने की बात हुई है। सभी देशों ने बयान में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ सहयोग बढ़ाने का खास तौर पर जिक्र किया है। कहा गया है कि आसियान की तरफ से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए जो दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया है, क्वाड उसका समर्थन करता है।

ग्लोबल वार्मिंग का असर

ग्लोबल वार्मिंग के चलते वैश्विक तापमान में काफी वृद्धि देखी जा रही है। अमेरिका सहित कई देशों में तापमान बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बहुत ही आम हो गई हैं। इटली के सार्डिनिया स्थित मैंडास के पास गुरुवार को भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयावह है कि इसे बुझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। एपी

अमेरिका में फिर तेजी से बढ़ रही कोरोना महामारी

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका में कोरोना महामारी फिर तेज गति से बढ़ने लगी है। इसके लिए कोरोना के डेल्टा वैरिएंट को कारण बताया जा रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सीडीसी) ने यह अंदेशा जताया है कि आगामी चार हफ्ते में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। इस अवधि में मरने वालों की संख्या भी काफी बढ़ सकती है।

सेंटर्स फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन की ओर से बुधवार को जारी किए गए अनुमान के मुताबिक, चार सितंबर तक देश में 3,300 से लेकर 12,600 कोरोना पीड़ितों की मौत होने का अंदेशा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चार हफ्ते की इस अवधि में साढ़े पांच लाख से लेकर 23 लाख 40 हजार नए मामले मिल सकते हैं। जबकि इस दौरान 8,600 से लेकर 33 हजार 300 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किए जाने का अनुमान है। महामारी की दो लहरों का सामना कर चुके अमेरिका में अब तक कुल करीब तीन करोड़ 70 लाख संक्रमित पाए गए हैं। छह लाख 30 हजार से ज्यादा मौत हुई है। तमाम प्रयासों के बावजूद अमेरिका महामारी को रोक नहीं पा रहा है।

- सीडीसी ने अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने का जताया अंदेशा

अमेरिका में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हर स्तर पर इससे निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैलिफोर्निया स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाती एक युवती। एएफपी

इन देशों में यह है हाल

पाकिस्तान : एएनआइ के अनुसार, इस देश में तीन माह बाद एक दिन में 102 पीड़ितों की मौत हुई और 4,934 नए केस पाए गए। यहां चौथी लहर है।

रूस : रायटर के मुताबिक, तीसरी लहर का सामना कर रहे इस देश में एक दिन में सर्वाधिक 808 पीड़ितों की मौत हुई और 22 हजार नए केस मिले।

चीन : एएनआइ के अनुसार, डेल्टा के चलते यहां फिर नए मामलों में उछाल आया है। 24 घंटे में 61 नए केस मिले, लेकिन कोई मौत नहीं हुई।

आस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में लाकडाउन के कारण हर तरफ सन्नाटा ही दिखाई पड़ता है। सिटी सेंटर क्षेत्र में मास्क लगाकर जाता युवक। रायटर

दक्षिण-पूर्व एशिया में नए मामलों में आ रही स्थिरता

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, गत एक माह में दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में कोरोना के नए मामलों में स्थिरता देखी जा रही है। भारत में संक्रमण स्थिर होने के चलते ऐसा देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया और म्यांमार में भी नए मामलों में कमी आई है।

पाकिस्तान ने किया बैलेस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण

इस्लामाबाद, प्रेट्र: पाकिस्तान ने गुरुवार को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलेस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया। परमाणु हथियार लेकर हमला करने में सक्षम यह मिसाइल 290 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है।

सेना ने कहा, मिसाइल के सफल परीक्षण से सेना की स्ट्रैटजिक फोर्सेस कमांड को नई ताकत मिलेगी। परीक्षण के समय कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद अली, विज्ञानी और इंजीनियर मौजूद थे। मिलिटरी मीडिया विंग के अनुसार, आर्मी स्ट्रैटजिक फोर्सेस कमांड ने मिसाइल के सभी मानकों पर खरा उतरने पर परियोजना से जुड़े लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और प्रधानमंत्री इमरान खान ने गजनवी मिसाइल के सफल परीक्षण पर कमांड, विज्ञानियों और इंजीनियरों को बधाई दी है।

क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी चोरी के बाद हैकर्स ने 26 करोड़ डालर लौटाए

- हैकर्स ने 60 करोड़ डालर की क्रिप्टोकरेंसी पर किए थे हाथ साफ

लंदन, रायटर: क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी 60 करोड़ डालर (करीब 45 अरब रुपये) की चोरी को अंजाम देने वाले हैकर्स ने इसमें से 26 करोड़ डालर यानी 19 अरब रुपये से ज्यादा वापस कर दिए हैं। ब्लाकचेन शोधकर्ताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अलग-अलग ब्लाकचेंस को जोड़ने वाली कंपनी पाली नेटवर्क ने ट्वीट कर बताया था कि कुछ हैकरों ने उसकी सिक्योरिटी में सेंध लगा दी थी। उन्होंने बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी में हाथ साफ कर दिया था। इस हैकिंग में 60 करोड़ डालर की क्रिप्टोकरेंसी की चोरी की बात कही गई थी, जो क्रिप्टो के इतिहास का सबसे बड़ी चोरी हो सकती है। पाली नेटवर्क ने बाद में हैकर्स से चुराई गई क्रिप्टोकरेंसी को वापस करने को कहा और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी। ब्लाकचेन फोरेंसिक कंपनी चैनालिसिस ने कहा, हैकर्स ने विभिन्न सिक्के के रूप में लगभग 26 करोड़ डालर की क्रिप्टोकरेंसी वापस कर दी है।

ब्लाकचेन विश्लेषक फर्म एल्लिप्टिक एंड चैनालिसिस द्वारा साझा किए गए डिजिट संदेश के मुताबिक, हैकर्स ने कहा कि उन्होंने मजे के लिए इस चोरी को अंजाम दिया। वे क्रिप्टोकेरेंसी की सुरक्षा में खामियों को उजागर करना चाहते थे, ताकि कोई दूसरा उसमें सेंध नहीं लगाने पाए। हालांकि, इस संदेश की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है।

क्रिप्टोकरेंसी फर्म टिथर के एक अधिकारी ने बताया था कि उसकी कंपनी से भी करीब 3.3 करोड डालर टोकंस की चोरी हुई थी, लेकिन अटैक का पता चलते ही इसे इशूअर ने फ्रीज कर दिया। इसका मतलब इन टोकंस का यूज हैकर्स नहीं कर सकते हैं।

कराची में 20 करोड़ रुपये के साथ वैन ड्राइवर फरार

कराची, प्रेट्र: पाकिस्तान के कराची शहर के वित्तीय इलाके वाल स्ट्रीट इलाके में एक सिक्योरिटी कंपनी का वैन ड्राइवर 20 करोड़ रुपये के साथ फरार हो गया।

पुलिस में दर्ज एफआइआर के अनुसार, एक सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर हुसैन शाह वैन से यह धनराशि व्यस्त चुंदरीपुर रोड स्थित स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान की शाखा में जमा कराने के लिए गया था। उसके साथ एक सुरक्षा गार्ड भी था। गार्ड जब बैंक की इमारत में गया तो उसी दौरान ड्राइवर वैन लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक, गार्ड ने जब ड्राइवर को फोन किया तो उसका सेल फोन बंद मिला। वैन बैंक से कुछ दूरी पर मिली, लेकिन रुपये गायब थे। ड्राइवर अभी पकड़ में नहीं आया है। पुलिस ड्राइवर के पिता से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उन्होंने बताया कि परिवार का उससे कोई संबंध नहीं है। उसे छह माह पहले ही घर से निकाल दिया गया था।

जहाज दुर्घटनाग्रस्त

उत्तर पूर्वी जापान के हचिनोहे स्थित समुद्र में क्रिम्सन पोलरिस जहाज दो टुकड़ों में टूट कर डूब रहा है। इससे तेल का रिसाव भी हो रहा है। इस पर सवार सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तेल के रिसाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एपी

अब जडेजा भारत के लिए एक मुख्य गेंदबाज हैं और बल्ले से वह अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब जडेजा पहली बार आए थे, मैं उस समय उप कप्तान था।'
–वीरेंद्र सहवाग, पूर्व भारतीय बल्लेबाज

लाड्र्स टेस्ट में राहुल ने जड़ा शतक, रोहित चूके

इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने दूसरे टेस्ट में बनाए तीन विकेट पर 276 रन, राहुल 127 पर नाबाद, रोहित 83 पर हुए आउट

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : ऐतिहासिक लाड्र्स के मैदान पर भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने टेस्ट शतक जड़ा, जबकि उनके सलामी जोड़ीदार रोहित शर्मा शतक जड़ने से चूक गए। हालांकि, इन दोनों की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 126 रन जोड़कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, जिसकी मदद से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 276 रन का स्कोर बनाया। रोहित 145 गेंदों पर 11 चौके और एक छक्के की मदद से 83 रन बनाकर आउट हुए, जबकि राहुल 248 गेंदों पर 12 चौकों और एक छक्के की बदौलत 127 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दिन का खेल खत्म होने के समय अजिंक्य रहाणे एक रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने दो विकेट लिए, जबकि ओली रोबिनसन ने एक विकेट हासिल किया।

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टास जीता। चूंकि बादल छाये हुए थे, इसलिए रूट ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। हालांकि, बारिश के कारण खेल आधा घंटा देरी से शुरू हुआ। रोहित और राहुल ने सीम और स्विंग गेंदों का डटकर सामना किया। उन्होंने खासकर पहले घंटे में किसी तरह का जोखिम नहीं उठाया क्योंकि पिच में नमी भी थी।

रूट ने अपने मुख्य गेंदबाज जेम्स एंडरसन को 12वें ओवर में दूसरे स्पैल के लिए बुलाया, लेकिन रोहित और राहुल बेहद सजग थे। हालांकि, एंडरसन ने एक-दो अवसरों पर राहुल को जरूर परेशान किया। पारी का पहला चौका 13वें ओवर में रोहित ने सैम कुर्रन पर लगाया, जिससे वह दोहरे अंक में भी पहुंचे। रोहित ने पहली 50 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने गियर बदला और कुर्रन के अगले ओवर में चार चौके लगाकर स्कोर बोर्ड को गति दी। जब वह अपने स्वाभाविक लय में आते दिख रहे थे तभी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। अंपायरों ने कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भोजनकाल की घोषणा कर दी।

रोहित ने पहले घंटे के खेल में सतर्कता बरतने के बाद अपने स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी की। रोहित और राहुल के बीच दूसरे सत्र के दौरान 21वें ओवर में 50 रन की साझेदारी पूरी हुई। जल्द ही रोहित ने 83 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करते ही रोहित ने अगले ओवर में भारतीय पारी का पहला छक्का जड़ा, जो मार्क वुड की गेंद पर 26वें ओवर में आया। उन्होंने वुड के अगले ओवर में दो चौके भी जड़े। 33वें ओवर में मोइन अली पर एक रन के साथ रोहित ने राहुल के साथ शतकीय साझेदारी और भारत के 100 रन पूरे किए। इसके बाद रोहित की रफ्तार कुछ कम हुई और वह काफी रक्षात्मक दिखे। वह 119वीं गेंद पर दो रन लेकर 79 से 81 पर पहुंचे, लेकिन इसके बाद उनका बल्ला एकदम से शांत हो गया। अगली 25 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ दो रन बनाकर गेंदबाजों को खुद पर हावी होने का मौका दिया। नतीजा यह रहा कि अगली गेंद पर एंडरसन ने उन्हें बोल्ड कर शतक से वंचित कर दिया और इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई।

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शतक लगाने के बाद केएल राहुल • एपी

31 साल से भारत का कोई भी सलामी बल्लेबाज लाड्र्स में टेस्ट शतक नहीं जड़ सका था। भारतीय सलामी बल्लेबाज का लाड्र्स में पिछला टेस्ट शतक 1990 में आया था, जो मौजूदा मुख्य कोच रवि शास्त्री ने जड़ा था। इसके अलावा सिर्फ वीनू मांकड (1952 में) ही लाड्र्स में बतौर सलामी बल्लेबाज भारत की ओर से टेस्ट शतक जड़ने में सफल रहे हैं

35000 गेंद टेस्ट क्रिकेट में फेंकने वाले पहले तेज गेंदबाज और कुल चौथे गेंदबाज बने एंडरसन। उनसे पहले मुरलीधरन (44039 गेंदें), अनिल कुंबले (40850) व शेन वार्न (40705) ऐसा कर चुके हैं

स्कोर बोर्ड

टास : इंग्लैंड (गेंदबाजी) — भारत (पहली पारी)

भारत 276/3 (90 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा बो. एंडरसन	83	145	11	01
केएल राहुल नाबाद	127	248	12	01
पुजारा का. बेयरस्टो बो. एंडरसन	09	23	01	00
कोहली का. रूट बो. रोबिनसन	42	103	03,	00
अजिंक्य रहाणे नाबाद	01	22	00	00

अतिरिक्त : (बा–8, लेबा–5, नोबा–1) 14, **कुल :** 90 ओवर में तीन विकेट पर 276 रन, **विकेट पतन :** 1–126 (रोहित, 43.4), 2–150 (पुजारा, 49.6), 3–267 (कोहली, 84.4)

गेंदबाजी
जेम्स एंडरसन 20–4–52–2
ओली रोबिनसन 23–7–47–1
सैम कुर्रन 18–1–58–0
मार्क वुड 16–1–66–0
मोइन अली 13–1–40–0

पुजारा की असफलता का सिलसिला जारी

चेतेश्वर पुजारा (9) की असफलता का सिलसिला इस टेस्ट मैच में भी जारी रहा। उन्हें एंडरसन ने अपना दूसरा शिकार बनाया। पुजारा अब ऐसी लगातार 10 पारियां खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने अर्धशतक नहीं लगाया। वहीं, अगले ओवर में ही राहुल ने रोबिनसन पर तीन रन लेकर 137 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। अब राहुल का साथ देने क्रीज पर कप्तान विराट कोहली आए। कोहली शुरुआत में कुछ असहज दिखे, लेकिन दूसरे छोर से राहुल ने कुछ अच्छे शाट खेलकर कोहली के ऊपर से दबाव कम किया। कोहली ने 64वें ओवर में मार्क वुड पर दो रन बटोरे, जिसके साथ भारत के 200 रन भी पूरे हुए। कोहली जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि वह दिन का खेल खत्म होने पर नाबाद लौटेंगे, लेकिन उनका धैर्य जवाब दे गया और वह रोबिनसन की बाहर जाती गेंद से छेड़छाड़ कर बैठे और पहली स्लिप पर खड़े इंग्लिश कप्तान जो रूट ने भारतीय कप्तान का कैच लेकर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद रहाणे ने राहुल के साथ मिलकर भारत को और कोई नुकसान नहीं होने दिया।

निशानेबाजों के लचर प्रदर्शन की तीन भागों में होगी समीक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : टोक्यो ओलिंपिक में निशानेबाजों के लचर प्रदर्शन के बाद तीन भाग में समीक्षा की जाएगी और भारतीय निशानेबाजी महासंघ (एनआएआइ) के अधिकारियों के प्रदर्शन का भी विश्लेषण होगा।

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआइ) से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि तीन भाग की समीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी है। रियो ओलिंपिक से खाली हाथ लौटने के बाद भारतीय निशानेबाज टोक्यो ओलिंपिक से भी बिना पदक के लौटे। सूत्र ने गुरुवार को बताया, 'समीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी है और यह तीन हिस्सों में होगी। सबसे पहले खिलाड़ी, फिर कोच और सहयोगी स्टाफ और फिर राष्ट्रीय महासंघ के अधिकारियों की समीक्षा होगी।'

मनु भाकर • एपी

यह पूछने पर कि क्या एनआरएआइ अध्यक्ष रनिंदर सिंह का भी विश्लेषण होगा, सूत्र ने इसका सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि महासंघ के प्रमुख इसके लिए तैयार हैं और टोक्यो में खेलों के दौरान भी उन्होंने इसी तरह की बात कही थी। सूत्र ने कहा, 'कोई सही ख्याति वाला व्यक्ति महासंघ के अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। वह इन चीजों को देखेगा कि जहां तक ओलिंपिक की तैयारी का सवाल है तो महासंघ ने कहां कमी छोड़ी। इस समीक्षा में महासंघ को अलग नहीं रखा जाएगा।'

महासंघ के शीर्ष पदाधिकारियों के विश्लेषण से पहले एनआरएआइ निशानेबाजों, कोचों और सहयोगी स्टाफ की समीक्षा करा रहा है। टोक्यो में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय महासंघ की नजरें ढांचे में बड़े बदलावों पर हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'निश्चित तौर पर आप पूरे ढांचे में बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं और यह सिर्फ कोचों तक सीमित नहीं होगा। सभी का विस्तार से आकलन होगा क्योंकि टोक्यो में विफलता के पीछे के कारण ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। निशानेबाजों, कोचों और सहयोगी स्टाफ की समीक्षा एनआरएआइ अध्यक्ष, सचिव (राजीव भाटिया) और महासचिव (डीवी सीताराम राव) करेंगे।'

टोक्यो में भारतीय निशानेबाजों से पदक की काफी उम्मीदें थीं, लेकिन निराशा मिली। टोक्यो अभियान के दौरान विवादों की कहानियां भी सामने आईं, जब स्टार युवा पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर और उनके पूर्व कोच जसपाल राणा के बीच मतभेद की खबरों ने सुर्खियां बटोरीं। अधिकारी ने कहा, 'खेलों से पहले और इसके दौरान जिस तरह चीजें हुईं उससे महासंघ में सभी नाराज हैं।'

भारत के 54 पैरा एथलीटों का दल जापान हुआ रवाना

नई दिल्ली : टोक्यो ओलिंपिक के बाद अब टोक्यो पैरालिंपिक खेलों के लिए 54 पैरा एथलीटों के भारतीय दल को गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जापान के लिए विदा किया। उनका मानना है कि पैरा एथलीट भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ वापसी करेंगे। भारत 24 अगस्त से पांच सितंबर तक चलने वाले पैरालिंपिक खेलों की नौ स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा।

टीम में देवेंद्र झाझरिया (एफ-46 भाला फेंक), मरियप्पन थंगावेलू (टी-63 ऊंची कूद) और विश्व चैंपियन संदीप चौधरी (एफ-64 भाला फेंक) जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो पदक के दावेदारों में शुमार हैं। इससे देश को इस बार पैरालिंपिक खेलों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है। झाझरिया अपने तीसरे पैरालिंपिक स्वर्ण पदक की कोशिश में जुटे हैं। वह 2004 और 2016 में सोने का तमगा जीत चुके हैं। मरियप्पन ने रियो के पिछले चरण में स्वर्ण पदक जीता था, वह 24 अगस्त को उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे।

2016 रियो पैरालिंपिक में 19 भारतीय पैरा एथलीटों ने पांच खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य सहित चार पदक लेकर लौटे थे। बैडमिंटन पैरालिंपिक खेलों में पदार्पण करेगा, जिसमें सात भारतीय शटलर हिस्सा लेंगे। भारतीय प्रशंसक यूरोस्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स पर देश के पैरा खिलाड़ियों के मैच देख सकते हैं। भारतीय दल अपना अभियान 27 अगस्त से पुरुष और महिला तीरंदाजी स्पर्धा में शुरू करेगा।

पिछले साल हुआ पुरस्कार राशि में इजाफा

पिछले साल खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि में काफी वृद्धि की गई थी। खेल रत्न में अब 25 लाख रुपये का पुरस्कार मिलता है, जो पहले के साढ़े सात लाख से काफी ज्यादा है। अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि पांच लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई थी। पहले द्रोणाचार्य (लाइफटाइम) पुरस्कार हासिल करने वालों को पांच लाख रुपये दिए जाते थे, जिन्हें बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया। द्रोणाचार्य (नियमित) पुरस्कार हासिल करने वाले प्रत्येक कोच को पांच लाख के बजाय 10 लाख रुपये मिलते हैं।

> हमारे पैरा एथलीटों की महत्वाकांक्षा व आत्मविश्वास 1.3 अरब भारतीयों को प्रेरणा देते हैं। उनके साहस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां झुकती हैं। आगामी खेलों में भाग लेने वाले हमारे पैरा एथलीटों की संख्या पिछले संस्करण की तुलना में तीन गुना अधिक है। मुझे विश्वास है कि आपका प्रदर्शन भी पिछली बार से बेहतर होगा।
> **अनुराग ठाकुर**, केंद्रीय खेल मंत्री

29 अगस्त को नहीं होगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कार्यक्रम : प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को होने वाला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह इस साल देर से कराया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि चयन पैनल टोक्यो पैरालिंपिक में भाग लेने वाले पैरा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी इनमें शामिल करे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का मानना है कि पुरस्कार विजेताओं को चुनने के लिए चयन पैनल गठित कर लिया गया है, लेकिन चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले वे कुछ और समय इंतजार करना चाहेंगे। ठाकुर ने कहा, 'इस साल के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति गठित कर दी गई है, लेकिन पैरालिंपिक का आयोजन किया जाना है, इसलिए हम पैरालिंपिक के विजेताओं को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे।' राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार हर साल देश के राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिए जाते हैं, जो महान हाकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती भी है।

अब खेलों की राजनीति करेंगे पंकज सिंह

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज का भारतीय तलवारबाजी संघ का निर्विरोध अध्यक्ष और राजीव मेहता का सचिव बनना तय

गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह अब खेल संघों की राजनीति में उतर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को भारतीय तलवारबाजी संघ (एफएआइ) के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। उन्हें इस पद में चुनौती देने के लिए सामने कोई भी नहीं उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ इसलिए उनका निर्विरोध निर्वाचित होना तय है।

भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) के सचिव और वर्तमान में (एफएआइ) के अध्यक्ष राजीव मेहता ने अब सचिव पद के लिए नामांकन भरा है। उनका भी निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। एफएआइ अध्यक्ष पद के लिए पंकज के नाम के प्रस्तावक राजीव मेहता और सचिव बशीर अहमद खान हैं। जल्द ही आइओए के भी चुनाव होने हैं और उसमें भी इस नए चेहरे की धमक दिखाई देगी। पंकज के आने से राजीव मेहता की भी आइओए में स्थिति और मजबूत होगी। मालूम हो कि आइओए में सचिव राजीव और अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के रूप में दो गुट हैं जो कभी-कभी उबाल मारते रहते हैं।

पंकज सिंह • फाइल फोटो, ट्विटर

हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलिंपिक में पहली बार भारत की तरफ से भवानी देवी तलवारबाजी करती नजर आईं थी। वह भारत के लिए इस खेल में ओलिंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली (पुरुष/महिला) एथलीट बनीं थीं। भवानी ने पहले दौर में जीत भी हासिल की थी लेकिन उन्हें बाद में हारकर बाहर होना पड़ा था। अब भारतीय खेल प्राधिकरण और केंद्रीय खेल मंत्रालय भी तलवारबाजी को ओलिंपिक पदक का दावेदार मानने लगा है।

वीडियो को लेकर कोच लैंगर की सीए स्टाफ से बहस

सिडनी, प्रेट्र : आस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) की वेबसाइट पर पोस्ट एक वीडियो को लेकर कथित तौर पर बोर्ड के स्टाफ से बहस की। इस वीडियो में पिछले हफ्ते बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार सीरीज जीतने का जश्न मनाते हुए दिखाया गया है।

द सिडनी मार्निंग हेराल्ड के अनुसार, लैंगर व आस्ट्रेलिया के टीम मैनेजर गेविन डोवी क्रिकेट.काम.एयू वेबसाइट पर वीडियो को लेकर बहस करते हुए दिखे। यह बहस हाल में संपन्न पांच मैचों की टी-20 सीरीज के तीसरे मैच के बाद हुई, जिसे बांग्लादेश ने जीतकर 3-0 की बढ़त बनाई। बाद में मेजबान बांग्लादेश ने टी-20 सीरीज 4-1 से जीती।

10 सेकेंड के लिए घड़ी रुकी तो दिल की धड़कनें भी थम गईं : विवेक

कपीश दुबे (नईदुनिया) • इंदौर

जर्मनी के खिलाफ मैच में निर्णायक मौके पर 10 सेकेंड घड़ी बंद होने की घटना को नहीं भूले विवेक

ओलिंपिक में 41 साल बाद भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मप्र के विवेक सागर प्रसाद के अनुसार कांस्य पदक के लिए मुकाबला अहम था, लेकिन टीम पर कोई दबाव नहीं था। टीम जानती थी कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब है। देश के लिए पदार्पण करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी विवेक के अनुसार अनुशासन और समर्पण के कारण उन्हें सफलता मिली।

विवेक ने विशेष चर्चा में कहा कि 41 साल से भारतीय हाकी टीम ने ओलिंपिक पदक नहीं जीता है और यदि इस बार भी इतने करीब आकर हम पदक नहीं जीतते तो पता नहीं अगला मौका कब मिलता। अंतिम छह सेकेंड के रोमांच के बारे में पूछने पर विवेक ने कहा कि सिर्फ वह छह सेकेंड ही नहीं, बल्कि टाइमआउट के बाद जब मैच शुरू हुआ तो किसी तकनीकी खामी के कारण 10 सेकेंड घड़ी ही शुरू नहीं हुई थी। वह भी एक फैक्टर रहा, लेकिन हमें अंदर से विश्वास था कि हमारे पास दुनिया के श्रेष्ठतम गोलकीपर में से एक पीआर श्रीजेश है। हम पर अतिरिक्त दबाव नहीं था। हम जानते थे कि नकारात्मक सोच रखेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। हमें एक-दूसरे के तालमेल पर भरोसा था।

उम्मीद थी इतिहास रचकर लौटेंगे : उन्होंने कहा कि हमारी टीम टोक्यो में बेहतरीन प्रदर्शन करने के इरादे से गई थी और उम्मीद थी कि पदक जीतेंगे। आस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद भी हमने हौसला नहीं खोया था। कप्तान मनप्रीत ने टीम को बहुत प्रोत्साहित किया। पूरी टीम के सदस्य एक-दूसरे का जोश भर रहे थे। यही कारण है कि हम पदक जीतने में सफल रहे।

भोपाल में गुरुवार को विवेक सागर को गले लगाते हुए मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें एक करोड़ रुपये, घर और डीएसपी के पद से नवाजा • खेल विभाग

डीएसपी की जिम्मेदारी संभालूंगा : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विवेक को डीएसपी की नौकरी देने की घोषणा के बारे में विवेक ने कहा कि मैं अभी पीएसपीबी की ओर से खेलता हूं, लेकिन मप्र शासन में जिम्मेदारी संभालना चाहूंगा। मैं डीएसपी का पद स्वीकार करूंगा। अभी मेरा करियर प्रारंभ ही हुआ है। आगे भी अपने अनुभव का इस्तेमाल कर मप्र की सेवा करना चाहता हूं।

ऐसे थामी हाकी : विवेक ने बताया कि मेरे गांव से कुछ दूर सेना की आर्डिनेंस फैक्ट्री के मैदान पर हाकी खेली जाती थी। मेरा भी मन हुआ और मैं घर से अकेला वहां खेलने जाता था। मेरे पास अच्छी हाकी स्टिक तक नहीं थी। टूटी स्टिक को सुधराता और खेलता था। वर्ष 2012 में मुझे लगा कि अब खेल में करियर बनाया जा सकता है। अगले साल मप्र अकादमी में आया। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पापा शिक्षक हैं और वह चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, जिससे अच्छी नौकरी लगे। हमारे परिवार में भी कोई खिलाड़ी नहीं है मगर मैं खिलाड़ी बनना चाहता था।

पुरस्कारों की बारिश जारी

चौथे स्थान पर रहने वालों को भी कार देगी टाटा मोटर्स, नीरज को अवार्ड देगा वीप्लस इंफ्रास्ट्रक्चर

मुंबई, प्रेट्र : भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने गुरुवार को घोषणा की कि कंपनी उन भारतीय खिलाड़ियों को भी अल्ट्रोज कार देगी जो टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक से चूक गए थे। इस लिस्ट में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक, पहलवान दीपक पूनिया और महिला हाकी टीम शामिल है, जो ओलिंपिक में चौथे स्थान पर रहे थे।

टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने कहा, 'भारत के लिए यह ओलंपिक पदक और पोडियम पर रहने वाले खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। हमारे कई खिलाड़ी पोडियम के करीब पहुंचे। वे भले ही पदक से चूक गए हों लेकिन उन्होंने अपने समर्पण से लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया और वे भारत में उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए सच्ची प्रेरणा हैं।'

वी प्लस भी देगा इनाम : लखनऊ की एक रीयल स्टेट कंपनी वीप्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने भी स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के लिए पांच लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है। वीप्लस के मालिक अजीत वर्मा ने कहा, 'आपको अपने विजयी समारोह में लखनऊ में आमंत्रित करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी, ताकि आपको नकद पुरस्कार और जीवन भर के लिए इंफ्राहार्सडाटको की सभी प्रीमियम सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा सकें।' इंफ्राहार्सडाटको भी वीप्लस की ही एक शाखा है जो आनलाइन रियल स्टेट कंपनी है।

हरमनप्रीत व स्मृति द हंड्रेड से हटीं

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना • फाइल फोटो, बीसीसीआइ

लंदन, एएनआइ : भारतीय महिला क्रिकेटरों स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने द हंड्रेड के मौजूदा सत्र से नाम वापस ले लिया है और ये दोनों अब स्वदेश वापस लौट रही हैं। सदर्न ब्रेव की ओर से खेलने वालीं मंधाना के वापस लौटने का कारण है कि उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना है। वह अपने परिवार से मिलने के बाद आस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगी।

वहीं, हरमनप्रीत चोटिल हो गई हैं। मंधाना की जगह पर आखिरी दो मैचों में आयरलैंड की गैबी लुइस खेलेंगी। वहीं, मैनचेस्टर ओरिजनल्स ने अब तक हरमनप्रीत के कवर के बारे में नहीं बताया है। मंधाना ने मौजूदा सत्र में सात मैच खेले, जिसमें दो अर्धशतक जमाए। उनकी टीम सदर्न ब्रेव ने सात में से छह मैच जीते हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे फाइनल तक रुकने का मन था, लेकिन हम लोग काफी दिनों से अपने घरों से दूर हैं। मैं अपनी टीम को लाड्र्स में खेलते हुए देखूंगी और उम्मीद करती हूं कि वे अपने बेहतरीन फार्म में रहें।'

फुटबाल 13 अगस्त से शुरू होगा फुटवाल का रोमांच, इंग्लैंड की ईपीएल के साथ स्पेन की ला लीगा और जर्मनी की बुंडिशलीगा की भी होगी शुरूआत

आर्सेनल-ब्रेंटफोर्ड के मैच से होगा प्रीमियर लीग का आगाज

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : पिछले महीने संपन्न हुए मिनी विश्व कप यानी यूरो कप के बाद अब फुटबाल का रोमांच फिर से लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) का आगाज शनिवार देर रात से होने वाला है। इसके पहले मैच में आर्सेनल की टीम ब्रेंटफोर्ड का सामना करेगी। 13 अगस्त से शुरू होने वाली इस लीग का अंतिम मैच 22 मई 2022 को खेला जाएगा। हालांकि, इस बार फरवरी में ईपीएल के मैच नहीं होंगे और ऐसा सिर्फ दूसरी बार होगा जब ईपीएल में फरवरी में सर्दी की छुट्टियां रहेंगी।

प्रीमियर लीग के आगाज से पहले ब्रेंटफोर्ड दोस्ताना मैच में वेलेंसिया पर 2-1 से जीत के बाद मैदान में उतरेगी। सेंटर बैक एथन पिन्नाक और नाइजीरियाई मिडफील्डर फ्रैंक ओनेका के गोल से ब्रेंटफोर्ड ने जीत हासिल की थी। वहीं आर्सेनल एक दोस्ताना मैच में टाटनहम से 1-0 से हार गया था। दक्षिण कोरिया के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सोन ह्युंग-मिन के दूसरे हाफ के गोल ने टाटनहम हाटस्पर की जीत आर्सेनल पर सुनिश्चित कर दी थी। इसके अलावा इन दोनों क्लबों के बीच पिछली भिड़ंत वर्ष 2018 के काराबाओ कप के तीसरे दौर में हुई थी, जिसमें आर्सेनल ने ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से मात दी थी। दोनों टीमों के बीच कुल 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें आर्सेनल को पांच में हार तो चार में जीत मिली है, जबकि चार मैच ड्रा रहे हैं। इन आकड़ों के बावजूद कागजों पर आर्सेनल की टीम काफी ताकतवर नजर आ रही है। प्रीमियर लीग के अलावा स्पेन की ला लीगा और जर्मनी की बुंडिशलीगा की शुरुआत भी शनिवार से होगी।

30 वें प्रीमियर लीग सत्र का होगा आगाज
380 मैच खेले जाएंगे प्रीमियर लीग के सत्र 2021–22 में

50 वीं टीम बनेगी ब्रेंटफोर्ड प्रीमियर लीग खेलने वाली, जो कि लंदन की 10वीं टीम होगी

4 बार प्रीमियर लीग का पहला मैच खेलने वाली टीम बनेगी आर्सेनल

15 अगस्त को गत चैंपियन मैनचेस्टर सिटी अपने पहले मैच में टाटनहम का सामना करेगी

आर्सेनल के ग्रेनिट साका • फाइल फोटो ट्विटर

लियोन मेसी को क्रिप्टो करेंसी भी देगा पीएसजी क्लब

टोक्यो, एपी : दुनिया के स्टार फुटबालर लियोन मेसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्रशंसकों में शामिल हो गए हैं। उनके नए क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने बताया है कि मेसी को दिए गए पैकेज में फैन टोकंस शामिल है। मेसी का पीएसजी से सालाना करार करीब 35 मिलियन यूरो (लगभग तीन अरब रुपये) का हुआ है। इसमें कितने प्रतिशत क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा है, इसकी पुष्टि क्लब ने नहीं की है। क्लब का कहना है कि मेसी को बड़ी संख्या में ये टोकन मिले हैं। फैन टोकंस एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है। इसको रखने वाले लोग, इसका इस्तेमाल क्लब के फैसलों में वोटिंग के लिए कर सकते हैं। इस वर्ष इंग्लिश प्रीमियम लीग की चैंपियंस रहे मैनचेस्टर सिटी क्लब और इटली के एसी मिलान क्लब ने भी इसी तरह के टोकन लांच किए हैं। मेसी के पूर्व क्लब बार्सिलोना ने भी पिछले वर्ष टोकन शुरू किए थे। बिटक्वाइन और अन्य डिजिटल करेंसी की तरह फैन टोकंस की भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की जा सकती है। इनके दाम में भी काफी उतार-चढ़ाव होता है। वहीं, मेसी ने पीएसजी के साथ अभ्यास करना भी शुरू कर दिया है।

लियोन मेसी • रायटर

धारावाहिक विघ्नहर्ता गणेश में शिव बने मलखान सिंह

धारावाहिक देवों के देव महादेव में शिव बने मोहित रैना

धारावाहिक ओम नमः शिवाय में शिव बने समर जय सिंह

धारावाहिक राधाकृष्ण में शिव बने तरुण खन्ना

श्रावण मास विशेष

शिव के रूप निराले

श्रावण मास में शिव आराधना में लीन हैं श्रद्धालु। 16 अगस्त को श्रद्धा-भक्ति से मनाया जाएगा सावन का अंतिम सोमवार। हिंदू धर्मग्रंथों में श्रावण को अवढर दानी और महाकाल के रूप में पूज्य भगवान शिव को समर्पित किया गया है। विभिन्न धारावाहिकों में कई कलाकारों ने शिव का किरदार निभाया है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े भगवान शिव के निराले रूप को कैमरे के सामने प्रस्तुत करना कलाकारों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है। बदलते वक्त के साथ तकनीक, कल्पना और नजरिए में भी बदलाव आया। इन सभी पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं प्रियंका सिंह और दीपेश पांडेय...

यूं तो शिव का चित्रण धार्मिक फिल्मों तथा धारावाहिकों में पहले भी किया गया, लेकिन शिव को केंद्र में रखते हुए टेलीविजन पर पहला धारावाहिक 'ओम नमः शिवाय' साल 1997 में दूरदर्शन पर शुरू हुआ था। धीरज कुमार के निर्देशन में बना यह धारावाहिक शिव पुराण पर आधारित था। धारावाहिक में महादेव बने समर जय सिंह ने दर्शकों के मानस पर गहरी छाप छोड़ी थी। उसके बाद साल 2011 में लाइफ ओके चैनल पर प्रसारित धारावाहिक 'देवों के देव महादेव' में महादेव की भूमिका ने मोहित रैना को घर-घर में लोकप्रिय बनाया। महादेव को केंद्र में रखकर अन्य भाषाओं में भी धारावाहिक बनाए गए। साल 2016 में कन्नड़ धारावाहिक 'हर हर महादेव' और साल 2018 में बांग्ला धारावाहिक 'ओम नमः शिवाय' काफी पसंद किया गया। अब जल्द ही एंड टीवी पर शिव महिमा पर केंद्रित धारावाहिक 'बाल शिव' शुरू होने जा रहा है।

धैर्य जरूरी है: भक्ति आधारित कार्यक्रम देखते हुए भक्तिमय माहौल बनाने के लिए खास तैयारी भी करनी पड़ती है, वहीं बाघम्बर, भुजंग, चंद्र और गंगाधर शिव का किरदार कलाकारों के साथ-साथ मेकअप आर्टिस्ट, कास्ट्यूम और आर्ट डिपार्टमेंट के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इस रूप के मेकअप में जहां आम किरदारों की तुलना में लगभग दोगुना समय लगता है, वहीं कास्ट्यूम और सेट डिजाइन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। 'ओम नमः शिवाय' और 'विष्णु पुराण' जैसे धारावाहिकों में शिव का किरदार निभा चुके अभिनेता समर जय सिंह बताते हैं, 'शिव बनने के लिए मुझे रोजाना आधा-पौना घंटा मेकअप में लगता था। 'ओम नमः शिवाय' में मेरे गले में पहने जाने वाले सांप असली होते थे। वे तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील ठंडे खून वाले जीव होते हैं। सेट की लाइट और शरीर के तापमान के आगे वो बहुत जल्दी सुस्त हो जाते थे। इसलिए सेट पर एकसाथ दो-तीन सांप रखे जाते थे। सांप को गले में डालकर एक्टिंग करने में शुरू में थोड़ा असहज रहा, लेकिन बाद में आदत बन गई। शिव के बाघम्बर के लिए तौलिए की तरह कास्ट्यूम तैयार किया गया था। शो में कैलाश पर्वत का सेट नमक का बना था। जब मुझे उस पर बैठकर सीन करना होता था तो नमक उस कास्ट्यूम में घुसता था। इससे कई बार त्वचा पर संक्रमण और चकत्ते भी पड़ जाते थे।'

गुणों को समझना जरूरी: शिव का किरदार प्रस्तुत करने के लिए शिव के गुणों को समझना भी जरूरी होता है। धारावाहिक 'राधाकृष्ण' में महादेव का किरदार निभाने वाले अभिनेता तरुण खन्ना बताते हैं, 'आठ साल पहले जब मैंने पहली बार शिव का किरदार निभाया था तो पहली बार सिर्फ तीन लाइनें दो घंटे की कोशिश के बाद भी नहीं डब कर पाया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बात करते हैं। वह बड़े योगी हैं। मैंने योग करना शुरू किया। मुझे समझ आया कि वह तो देवों के देव महादेव हैं, ऐसे में वह भद्रपुरुष की तरह बात करते होंगे। मैंने वहां से उस सुर को पकड़ लिया। फिर लगा महादेव मेरा हाथ पकड़कर आगे लेकर जा रहे हैं। महादेव एक तरफ तो भोले हैं, दूसरी तरफ गुस्सा इतना है कि संसार को खत्म कर सकते हैं। प्यार इतना करते हैं कि पत्नी के लिए हजारों साल तक वैरागी की तरह घूमते रहे।' इस संबंध में आगामी धारावाहिक 'बाल शिव' में शिव का किरदार निभाने वाले अभिनेता सिद्धार्थ अरोड़ा कहते हैं, 'शिव को समझने के लिए लोगों का जीवन कम पड़ जाता है। उनकी विराट छवि को समझने के लिए मैं अध्यात्म और ध्यान की मदद से खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा हूं।'

ओम नमः शिवाय के 52 गाने...

धारावाहिक 'ओम नमः शिवाय' का संगीत भी काफी चर्चा में रहा। इस शो का संगीत संगीतकार सारंग देव ने तैयार किया था, जबकि इसके गीतकार अभिराज थे। संगीत तैयार करने में शो के निर्देशक धीरज कुमार की पत्नी जुबी कोच्चर का भी बहुत बड़ा योगदान था। धीरज कुमार के मुताबिक, पूरे धारावाहिक में 52 गाने थे। उन गानों के लिए देश के सभी बड़े गायकों को अप्रोच किया और उन्होंने हां किया। मसलन आशा भोसले, कुमार शानू, सोनू निगम, सुरेश वाडकर, उदित नारायण, शंकर महादेवन, शान, कविता कृष्णमूर्ति आदि। इसके टाइटल ट्रैक के लिए क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज से संपर्क किया। उन्होंने कहा टीवी क्या, मैं फिल्म में भी नहीं गाता। जब उन्हें बताया गया कि यह शिव की महिमा पर है। इसमें टाइटल ट्रैक के अंदर सिर्फ नोटेशन है। तब उन्होंने स्वीकृति दी। उन्होंने ओम नमः शिवाय को विभिन्न तरीके से गाया। वह सुपरहिट रहा।'

कठिन शारीरिक परिश्रम: शिव योगी के साथ नर्तक भी हैं। उनके विविध रूपों को समझने के साथ ही स्क्रीन पर शिव बनने के लिए कलाकारों को शारीरिक तौर पर काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सिद्धार्थ अरोड़ा बताते हैं, 'शिव जी की तरह दिखने के लिए लिए मैं रोजाना जिम और डाइट की मदद से सुगठित शरीर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं शिव की आवाज पर भी काम कर रहा हूं। जिससे अगर लोग विजुअल्स न देखें, फिर भी उन्हें आवाज सुनने का मन करे। शिव तांडव के लिए मैंने कई दिनों तक कोरियोग्राफर के साथ बाकायदा ट्रेनिंग की है। इसके लिए आधा दिन मैंने हार्नेस की सहायता से हवा में लटक कर भी अभ्यास भी किया। इस किरदार में खुद को शिव समझना आसान नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि जब किरदार निभाऊं तो कहीं शिव भक्त सिद्धार्थ न दिखे, मेरा किरदार स्वयं शिव दिखे।' इस संबंध में समर जय सिंह कहते हैं, 'मेरी शारीरिक बनावट तो शुरुआत से ही ठीक-ठाक थी, लेकिन शिव के किरदार के लिए मैं घंटों जिम में बिताता था। शिव स्वयं नटराज कहलाते हैं। उनका तांडव व नृत्य से सीधा संबंध है। शो के ओपनिंग सांग के लिए मैंने कोरियोग्राफर माधव किशन जी के साथ लगभग डेढ़ महीना रिहर्सल किया था।'

व्यक्तित्व पर भी असर: शिव के किरदार का कलाकारों के व्यक्तित्व पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। कलाकार किरदार से भले ही कुछ वर्षों में निकल जाएं, लेकिन शिव का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर हमेशा रहता है। धारावाहिक 'देवों के देव महादेव' में शिव का किरदार निभा चुके अभिनेता मोहित रैना कहते हैं, 'इस किरदार के अनुभव ने मुझे बेहतर इंसान बनाया है। मैं जीवन को महत्व देता हूं। मैं प्रकृति के चक्र को समझता हूं। प्रकृति में सभी चीजें एकदूसरे से जुड़ी हुई हैं। सभी लोग बराबर हैं। यह मेरे लिए सिर्फ एक धारावाहिक नहीं, बल्कि सीखने की एक प्रक्रिया थी।' इस बारे में धारावाहिक 'विघ्नहर्ता गणेश' में शिव का किरदार निभाने वाले अभिनेता मलखान सिंह कहते हैं, 'चार सालों से महादेव का किरदार निभाते हुए मेरे व्यक्तिगत जीवन में काफी कुछ बदल गया है। एक ठहराव और समझ आ गई है। मुझे जो लाइनें दी जाती हैं, उनमें अपनी ऊर्जा डालने की कोशिश करता हूं। शिव मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। उनकी इतनी आराधना की है कि अपने आप यह किरदार मेरे पास आ गया।'

छवि तोड़ने की चुनौती: शिव का किरदार निभाने वाले कलाकारों को भले ही उससे लोकप्रियता मिली हो, लेकिन उनके अंदर का कलाकार उन्हें किसी भी एक छवि से निकलने के लिए प्रेरित करता है। इस बारे में समर जय सिंह कहते हैं, 'शिव के किरदार में लोगों ने मेरी कला को कम शिव के रूप को ज्यादा देखा। मैं विविधतापूर्ण किरदार निभाना चाहता था, लेकिन एक किरदार में लोकप्रिय होने के बाद टीवी में आपको टाइपकास्ट कर दिया जाता है। बतौर कलाकार हमारी भी आर्थिक व अन्य जरूरतें होती हैं। इसलिए मैंने बार-बार शिव का किरदार निभाया।' शिव ही नहीं दूसरे भगवान का किरदार निभा चुके कलाकारों के लिए भी अपनी छवि से बाहर निकलना मुश्किल होता है। इस बारे में धारावाहिक 'महाकाली- अंत ही आरंभ है' में शिव का किरदार निभा चुके अभिनेता सौरभ राज जैन कहते हैं, 'मेरे लिए महादेव का किरदार निभाना मुश्किल रहा, क्योंकि मुझे अपनी ही इमेज को तोड़ना था। लोग मुझे कृष्ण और विष्णु भगवान के किरदारों में अपना चुके थे। जब आप एक किरदार में प्रसिद्ध हो जाते हैं तो बार-बार आपको वैसे ही किरदार के लिए बुलाया जाता है।'

धारावाहिकों में शिव का चित्रण

एंड टीवी के नए धारावाहिक 'बाल शिव' में शिव का किरदार निभाएंगे **सिद्धार्थ अरोड़ा।** पूर्व में भक्ति से परिपूर्ण कई अन्य धारावाहिकों में शिव के चित्रण को विभिन्न कलाकारों ने जीवंत किया:

- रामायण (1987) – विजय कविश
- संकटमोचन महाबली हनुमान (2015) – अमित मेहरा
- जय जय जय बजरंग बली (2011) – मुकेश सोलंकी
- नीली छतरी वाले (2014) – हिमांशु सोनी

यादों का झरोखा

कड़ी मेहनत और तैयारियों के बाद बनी चक दे इंडिया

इस साल जापान में आयोजित हुए ओलिंपिक 2020 खेलों में भारतीय महिला हाकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के ऐतिहासिक मौके पर शाह रुख खान अभिनीत फिल्म 'चक दे! इंडिया' (2007) का भी काफी जिक्र हुआ। इसके निर्माण और तैयारियों की कहानियां साझा कर रही हैं फिल्म में हाकी खिलाड़ी कोमल चौटाला और विद्या शर्मा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियां चित्राशी रावत और विद्या मालवदे...

चित्राशी रावत कहती हैं, 'मैंने चौथी कक्षा से ही हाकी खेलना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने स्कूल, कालेज और नेशनल लेवल पर भी हाकी खेला। जबलपुर में हमारा हाकी टूर्नामेंट चल रहा था, उसी समय फिल्म 'चक दे! इंडिया' के निर्देशक शिमित अमीन इस फिल्म में हाकी खिलाड़ियों की टीम के लिए कास्टिंग कर रहे थे। आडिशन में मैं भी गई। वहां उन्होंने जो बोला मैं करती गई। जब उन्हें मेरा काम पसंद आया तो मुझे पिता जी के साथ इस फिल्म के लिए मुंबई बुलाया।

हम सभी कलाकार रोज सुबह चार बजे उठकर मुंबई के चेंबूर इलाके में स्थित मैदान में एक साथ हाकी की प्रैक्टिस किया करते थे। प्रैक्टिस के बाद वहां पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को बुलाया जाता था। वे हमसे मिलकर खेल के विभिन्न बिंदुओं पर बात करते थे। इस तरह करीब छह महीनों तक हमारी प्रैक्टिस चली। उसके बाद शाह रुख सर (शाह रुख खान) ने हमें ज्वाइन किया।

वह सेट पर पहली बार काले रंग की टीशर्ट और ट्रैक पैंट पहनकर आए थे। उन्हें इतना सहज देखना हमारे लिए सरप्राइज था। सभी लड़कियों में सिर्फ मैंने ही नेशनल लेवल पर खेला था तो उस वक्त मेरा एक अलग एटीट्यूड था कि हाकी तो मुझे आती है, बाकी सब देख लेंगे। शाह रुख सर के साथ मेरी पहली मुलाकात कुछ यूं हुई कि प्रैक्टिस के दौरान वह जो हाकी लेकर आए उसे देखकर मैंने कहा कि सर, आपको तो एकदम नौसिखियों वाली हाकी दी है, इस पर वह हंसने लगे। उसके बाद मेरी उनसे अच्छी बातचीत होने लगी। आस्ट्रेलिया की गोलकीपर का किरदार निभाने वाली खिलाड़ी बहुत निपुण थीं, उनके ऊपर से गोल मारना बहुत मुश्किल होता था।

प्रैक्टिस के दौरान शाह रुख सर और हमारी यह शर्त लगती थी कि जो पहले पांच गोल करेगा वही जीतेगा। यह फिल्म सभी की कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस का नतीजा थी। अभ्यास के दौरान हमें चोटें भी लगती थीं। शूटिंग से वापस जाने पर हम सबके शरीर पर चोट के काले, नीले दाग होते थे। आस्ट्रेलिया में शूटिंग के दौरान मेरी गर्दन में दर्द होने लगा था। मैं दर्द में बैठी हुई थी कि पीछे से शाह रुख सर आए और मेरे कंधे और गर्दन को मसाज देने लगे। वहां मौजूद सारी लड़कियां पलटकर मुझे देखने लगीं। मेरे लिए भी यह आश्चर्य की बात थी। उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस तरह की समस्या होती है। सबसे छोटी होने के कारण मुझे खूब लाड-प्यार मिलता था। जब फिल्म रिलीज हुई तो तहलका मच गया, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।'

फिल्म से जुड़ी अपनी यादें साझा करते हुए विद्या मालवदे कहती हैं, 'इस फिल्म से मैं आडिशन के जरिए जुड़ी। हमने करीब डेढ़ साल तक इस फिल्म के लिए ट्रेनिंग की। हाकी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। जिनको हाकी खेलना नहीं आता था, उनकी खेलने की ट्रेनिंग होती थी और जो पेशेवर खिलाड़ी थीं उनको एक्टिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। गोलकीपर की भूमिका निभाने के कारण सेफ्टी किट को सही तरीके से पहनना और गोल का बचाव करना मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था। ट्रेनिंग और स्क्रिप्ट रीडिंग के बाद हमने मुंबई में शूटिंग शुरू की। उसके बाद हमने आस्ट्रेलिया में करीब दो महीने रहकर शूटिंग की। ज्यादातर मुकाबलों की शूटिंग आस्ट्रेलिया में ही हुई थी। अंत में लड़कों के साथ दिखाए गए मैच की शूटिंग दिल्ली में हुई थी।

इस फिल्म से पहले शाह रुख खान सर के साथ मैंने एक विज्ञापन शूट किया था तो मैं उनके साथ काम करने को लेकर सहज थी। वह खुद खेलकूद में बहुत लाजवाब हैं। इस फिल्म में कई लड़किया नई थीं तो वह उन्हें भी लाइट्स, कैमरा एंगल आदि के बारे में बराबर बताते रहते थे। कभी-कभी वह कुछ प्वाइंटर्स भी दे देते थे कि सीन इस तरह करो। आस्ट्रेलिया में शूटिंग के दौरान एक दिन बहुत कड़ाके की ठंड थी। गोलकीपर सेफ्टी किट पहनने की वजह से मैं तो ठंड से बची रही, लेकिन बाकी लड़कियां जो टीशर्ट और स्कर्ट पहनकर दौड़ रही थीं, उन्हें काफी ठंड झेलनी पड़ी। ऊपर से उन्हें पसीने में दिखाने के लिए उन पर पानी के छींटे मारे जाते थे। पैरों पर हाकी का बाल लगने से हमेशा काले-नीले निशान होते थे। बाल लगने की वजह से मेरे पैरों के नाखून उखड़े हुए रहते थे। जब फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो अच्छी लगी थी, लेकिन यह नहीं पता था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट और रिलीज के 14 साल बाद भी प्रासंगिक होगी।'

दीपेश पांडेय

सेलेब स्पीक

जिंदगी को मिल रही है रफ्तार

अब माहौल धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन महामारी का दौर सभी को बहुत कुछ सिखा गया है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं। उनकी आगामी फिल्म 'बेल बाटम' होगी, जिसे पिछले साल स्काटलैंड में शूट किया गया था। पिछले दिनों वेब सीरीज 'महारानी' में भी हुमा के किरदार को काफी सराहना मिली।

पिछले डेढ़ साल में जिंदगी में आए बदलाव को लेकर हुमा कहती हैं, 'हम सब पर इस महामारी का प्रभाव पड़ा है। अब कोशिश यही रहती है कि जो लोग मेरे लिए मायने रखते हैं, उनका ख्याल रखूं। पहले बहुत सोचती थी, पर अब फिजूल की बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। अब बस लक्ष्य यही है कि रोज सुबह उठेंगे, काम पर जाएंगे, अच्छा काम करेंगे। पिछले साल जब कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी की रफ्तार थमी तो मैं तो कुछ महीनों तक बाहर नहीं निकली। मैंने मेडिटेशन किया, सुबह उठकर लिखना शुरू किया जिससे मानसिक शांति मिली। इस दौरान एक मौका मिला कि खुद के साथ जुड़ पाऊं।'

कोरोना काल में फिल्म 'बेल बाटम' का हिस्सा बनने को लेकर हुमा कहती हैं, 'निर्माता जैकी भगनानी ने काल करके इस फिल्म का प्रस्ताव दिया। इस बड़ी फिल्म का मैं छोटा सा हिस्सा हूं, लेकिन मेरे लिए यह अहम फिल्म है। 'बेल बाटम' बड़ी फिल्म है, इस स्केल पर फिल्म बनाना मुश्किल था। मैंने 'महारानी' वेब सीरीज भी लाकडाउन में शूट की। दिक्कतें भी पेश आईं। मन में यही बात आती थी कि क्या मैं आखिरी बार सेट पर जा रही हूं। अपने जीवन को लेकर ही सवाल खड़े हो गए थे। 'बेल बाटम' की शूटिंग के लिए जब मैं स्काटलैंड के हवाई सफर के लिए घर से एयरपोर्ट को निकली तब खुद को महफूज रखने की हर संभव कोशिश की। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने थे, मास्क और फेस शील्ड लगाई। हर जगह को सैनिटाइज करके बैठी। स्काटलैंड पहुंचे तो निर्माता ने हमारा पूरा ध्यान रखा था। बार-बार टेस्ट हो रहे थे, हम क्वारंटाइन में रहे। यह बड़ी फिल्म है, इससे दर्शकों के थिएटर में आने की उम्मीद बढ़ेगी। लोगों को दोबारा रोजगार मिलेगा।'

हुमा आगे कहती हैं, 'खुद की फिल्म से एक एक लगाव जरूर होता है, लेकिन यह फिल्म पूरी इंडस्ट्री के लिए अहम है। पहले जब किसी और की फिल्म रिलीज होती थी तो एक प्रतिस्पर्धा वाला माहौल होता था, लेकिन अब इंडस्ट्री से भी सब चाहते हैं कि लोग एक बार फिर फिल्म देखने आएं। परिवार के साथ बाहर जाना, पापकार्न, समोसा खाना, हम लोग इन यादों के साथ बड़े हुए हैं। बचपन में मैंने सिंगल स्क्रीन थिएटर में 'हम आपके हैं कौन' से लेकर 'जुरासिक पार्क' तक कई फिल्में देखी हैं। बुरा लगता है कि कोविड की वजह से आज के बच्चे वे यादें नहीं बना पा रहे हैं। अब माहौल का सामान्य होना जरूरी है।'

'बेल बाटम' में अपने किरदार के बारे में हुमा ने कहा, 'मैं फिल्म में दुबई की एजेंट का किरदार निभा रही हूं जो अंडरकवर है और एयरपोर्ट पर काम करती है। इस किरदार के लिए मेरे पास कोई रेफरेंस प्वाइंट नहीं था। हमारे लिए जरूरी बात थी कि मेरा लुक, मेरे बाल, लिपस्टिक का रंग उस दौर के मुताबिक विश्वसनीय लगें। फिल्म को शूट करना मुश्किल था, क्योंकि स्काटलैंड के ग्लासगो में बहुत हरियाली है, पूरा बैकग्राउंड तकनीक की मदद से बदलकर पिछली सदी के आठवें दशक के अबू धाबी को दिखाया गया है।'

हुमा बताती हैं, 'मुझे अपने माता-पिता की युवावस्था की तस्वीरें अच्छी लगती हैं। मेरे पापा बेल बाटम पहनते थे, मां के छोटे बाल थे, स्लीवलेस कपड़े पहनती थीं।' उस दौर से लेकर अब तक सिनेमा में अभिनेत्रियों की भूमिका में आ रहे बदलावों पर हुमा कहती हैं, 'अब उनके लिए अच्छे किरदार लिखे जा रहे हैं। महिला प्रधान फिल्में बन रही हैं, डिजिटल प्लेटफार्म पर मैं खुद 'महारानी' वेब सीरीज का हिस्सा रही हूं। जब अभिनेत्रियां अच्छा काम करती हैं तो खुशी होती है। उनको देखकर लगता है कि वे कर सकती हैं तो मेरे लिए भी आगे रास्ता है।'

प्रियंका सिंह

भारत के पहले स्वदेशी विमान एचटी2 ने भरी उड़ान

आजाद भारत में हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत के पहले विमान एचटी2 ने 1951 में आज ही के दिन पहली उड़ान भरी थी। बेंगलुरु में निर्मित इस दो सीट वाले विमान को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षक विमान के रूप में तीन दशक तक प्रयोग किया गया था।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश संसद में पेश किया गया

1784 में आज ही के दिन ब्रिटिश संसद में पिट्स इंडिया एक्ट पेश किया गया था। 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया था। इसके तहत कंपनी के अधीन क्षेत्र ब्रिटेन के क्षेत्र कहलाने लगे और भारत में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू हुई।

इलाज करने वाले डाक्टर से वैजयंती माला को हुआ था प्यार

दक्षिण भारत की सुपरस्टार से राष्ट्रीय स्तर की पहली स्टार बनने वाली वैजयंती माला का जन्म आज ही 1936 में तमिलनाडु के मद्रास (चेन्नई) में हुआ था। उन्होंने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म वड़कई से अभिनय शुरू किया। 1951 में फिल्म बहार से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। मधुमती, संगम और गंगा जमुना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर मिला। उन्हें निमोनिया हो गया था, जिसका इलाज कर रहे डाक्टर चमनलाल बाली से प्यार हुआ और 10 मार्च 1968 को शादी कर ली। शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली।

इधर-उधर की

जब बाढ़ में फंसी कार निकलवाने लगा कुत्ता

भारी बारिश से बाढ़ में फंस गई थी महिला की कार। इंटरनेट मीडिया

एडिनबरा, एजेंसी : इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु यूं ही नहीं बनाया था। वे अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ते। स्काटलैंड के ग्लासगो में बाढ़ में फंसी कार को निकलवाने में मदद करते कुत्ते का वीडियो इसी बात की बानगी है। लोरी नाम की महिला पालतू कुत्ते के साथ टहल रही थी तभी पानी में कार फंसी देखी जिसमें महिला सवार थी। लोरी अकेले ही कार को धक्का देने में जुट गई तभी उनका कुत्ता भी मदद के लिए आ गया और पंजों से कार को धक्का लगाने लगा और दोनों ने कार को बाहर निकाल दिया। एक शख्स ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डाला, जो वायरल हो रहा है। लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

स्ट्रोक पीड़ित सैर से टालें मौत का जोखिम

शोध ▶ सप्ताह में तीन से चार घंटे की वाकिंग से 54 फीसद तक कम होता है मौत का खतरा

मेडिकल जर्नल न्यूरोलाजी में प्रकाशित हुआ अध्ययन

मिनियापोलिस, एएनआइ : टहलना या सैर करना सभी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह जैसे रोगियों को खासतौर पर इसकी सलाह दी जाती है। अब एक नए अध्ययन में बताया गया है कि स्ट्रोक पीड़ित व्यक्ति यदि सप्ताह में तीन से चार घंटे की सैर करे या साइकिल चलाए या इसके बराबर का शारीरिक श्रम करे तो मौत का जोखिम 54 फीसद तक कम होता है।

अध्ययन का यह निष्कर्ष मेडिकल जर्नल न्यूरोलाजी के आनलाइन अंक में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन के मुताबिक, 75 वर्ष से कम उम्र वाले लोग यदि इतने श्रम वाले व्यायाम करते हैं तो उनकी मौत का जोखिम 80 फीसद तक कम होता है। कनाडा में यूनिवर्सिटी आफ कैलगरी के शोधकर्ता तथा अमेरिकन एकेडमी आफ न्यूरोलाजी के सदस्य व इस अध्ययन के लेखक राएड ए. जुंडी बताते हैं कि स्ट्रोक से ठीक से हुए लोगों के स्वास्थ्य के लिए शारीरिक श्रम की भूमिका समझने के लिए बेहतर एक्सरसाइज थेरेपी को डिजाइन करना जरूरी है, ताकि इसके बारे में जागरूकता फैला कर पीड़ितों के दीर्घायु होने में मदद की जा सके। उनके मुताबिक, अध्ययन के परिणाम बड़े उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि सप्ताह में महज तीन से चार घंटे की सैर मौत की जोखिम को काफी कम करता है और स्ट्रोक पीड़ित यह काम आसानी से कर सकते हैं। यह भी पाया गया है कि जो लोग प्रति सप्ताह छह से सात घंटे की सैर करते हैं, उन्हें और भी ज्यादा फायदा होता है। इस निष्कर्ष का इस्तेमाल स्ट्रोक पीड़ितों को दी जाने वाली गाइडलाइन में किया जा सकता है।

सैर से सुधारें सेहत। फाइल फोटो

अध्ययन का आकार और स्वरूप : अध्ययन में 895 ऐसे लोग शामिल थे, जिनकी औसत उम्र 72 साल थी और उन्हें एक बार स्ट्रोक का झटका लग चुका था। जबकि 97,805 ऐसे लोग थे, जिनकी औसत उम्र 63 साल थी और वे स्ट्रोक से बचे हुए थे। उनके शारीरिक श्रम की गतिविधियों का आकलन सैर, दौड़, बागवानी, साइकलिंग और तैराकी जैसे कामों से संबंधित सवाल-जवाब के आधार पर किया गया। उदाहरण के तौर पर उनसे पूछा गया कि पिछले तीन महीने में वे कितनी बार सैर करने को गए और कितनी देर सैर की। इसके आधार पर शोधकर्ताओं ने हरेक गतिविधि की आवृत्ति और अवधि के आधार पर व्यायाम या शारीरिक श्रम का आकलन किया। इसके लिए प्रतिभागियों का करीब साढ़े चार वर्ष तक अध्ययन किया गया। उम्र और धूमपान जैसे मौत के कारकों वाले जोखिमों का भी आकलन करने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि मरने वालों में 25 फीसद लोग ऐसे थे, जो स्ट्रोक से पीड़ित रहे, जबकि स्ट्रोक से बचे रहे लोगों में मौत का फीसद महज छह ही था।

अध्ययन का निष्कर्ष : स्ट्रोक पीड़ित लोगों के ग्रुप में जिन लोगों ने सप्ताह में तीन से चार घंटे की सैर की या उसके बराबर का श्रम किया, उनकी मौत का आंकड़ा सिर्फ 15 फीसद था, जबकि जिन लोगों ने न्यूनतम शारीरिक श्रम भी नहीं किया, उनकी मौत की आंकड़ा 33 फीसद था। वहीं, जिन्हें कभी स्ट्रोक नहीं हुआ और उतना न्यूनतम शारीरिक श्रम किया, उनमें मौत का आंकड़ा 4 फीसद था, जबकि शारीरिक श्रम नहीं करने वालों में मौत का आंकड़ा दोगुना अर्थात 8 फीसद था।

शोधकर्ताओं ने पाया कि मौत के जोखिम में सर्वाधिक कमी स्ट्रोक पीड़ित 75 वर्ष से कम उम्र के लोगों में हुई। ऐसे लोगों में, जिन्होंने न्यूनतम शारीरिक श्रम किया, उनमें मरने वाले 11 फीसद थे, जबकि इसी वर्ग में शारीरिक श्रम नहीं करने वालों में मौत का फीसद 29 रहा। शोधकर्ताओं के अनुसार, 75 साल से कम उम्र वाले स्ट्रोक पीड़ितों में, जिन्होंने न्यूनतम स्तर का शारीरिक श्रम किया, मौत का जोखिम 80 फीसद तक कम रहा। ये सभी आंकड़े अध्ययन अवधि के हैं। हालांकि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों में न्यूनतम व्यायाम के बावजूद बहुत ज्यादा फायदा नहीं देखा गया, फिर भी जोखिम में 32 फीसद कमी रही। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि न्यूनतम शारीरिक श्रम से स्ट्रोक पीड़ित लोग किसी भी सामान्य कारण से होने वाली मौत का जोखिम कम कर सकते हैं।

देश प्रेम के जुनून की कहानी

शेरशाह

प्रमुख कलाकार : सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, शिव पंडित, निकितिन धीर
निर्देशक : विष्णु वर्धन
अवधि : दो घंटे 15 मिनट
डिजिटल प्लेटफार्म : अमेजन प्राइम वीडियो

करीब 22 साल पहले सात जुलाई, 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध के सूरमाओं में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा भी शामिल हैं, उनकी शौर्यगाथा पर ही 'शेरशाह' आधारित है। कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें सांकेतिक नाम शेरशाह दिया गया था। इसी पर फिल्म का शीर्षक है। विक्रम का रोम-रोम जहां देशप्रेम के लिए समर्पित था, वहीं उनकी प्रेम कहानी भी काफी दिलचस्प रही।

हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे विक्रम जुड़वा भाइयों में बड़े थे। यह कहानी उनके छोटे भाई विशाल की जुबानी बयां की जाती है। फिल्म का आरंभ युद्ध के मैदान से होता है। वहां से कहानी विक्रम के बचपन में आती है। क्रिकेट के खेल में बाल वापस लेने को लेकर अपने से उम्र में बड़े बच्चे की मांग के आगे न झुककर उसे हासिल करने के साथ उनके साहस, निर्भीकता, निडरता और जिजीविषा से परिचय होता है। आइएमए देहरादून से कमीशन प्राप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित सोपोर में 13, जम्मू कश्मीर एंड राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट उनकी पहली पोस्टिंग होती है। इस बीच कॉलेज के दिनों में डिंपल चीमा (कियारा आडवाणी) के साथ उनकी प्रेम कहानी भी साथ-साथ चलती है। वहां से कारगिल युद्ध में पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए प्वाइंट 5140, प्वाइंट 4875 को फतह करने के साथ उनकी शहादत की दास्तान से हम परिचित होते हैं। इस दौरान कई ऐसे पल आते हैं, जो भावुक कर जाते हैं।

फिल्म का स्क्रीनप्ले, स्टोरी और डायलाग संदीप श्रीवास्तव ने लिखा है, वहीं दक्षिण भारतीय फिल्मों के निर्देशक विष्णुवर्धन की बतौर निर्देशक यह पहली हिंदी फिल्म है। उन्होंने कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी पकड़ को कायम रखा है। एक दृश्य में अचानक सैन्य काफिले पर हमले के बाद आतंकियों के साथ मुठभेड़ देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा का काम सराहनीय है। उन्होंने देशभक्ति, प्रेम के प्रति समर्पण और यारों के यार के जज्बे को बखूबी आत्मसात किया है। सरदारनी के किरदार में कियारा आडवाणी जंची हैं। बाहर से सख्त और अंदर से नरम कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में शिव पंडित प्रभावित करते हैं।

देशभक्ति से परिपूर्ण 'शेरशाह' प्रेरक कहानी है। यह देशसेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर सैनिकों की गाथा से परिचित कराती है। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देशप्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता... जैसे संदेश देती यह फिल्म अवश्य देखी जानी चाहिए। स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

जान जोखिम में डालकर बिल्डिंग पर चढ़ाई...

लंदन स्थित यूनिक्स टावर पर 21 वर्षीय जार्ज किंग ने जान जोखिम में डालकर चढ़ाई की। विगत सप्ताह वह बगल की स्ट्रैटफोर्ड टावर बिल्डिंग पर चढ़े थे। किंग यहां की सबसे ऊंची इमारत द शार्ड पर चढ़ने के लिए दो साल पहले जेल भी जा चुके हैं। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वह ऐसा कर रहे हैं। एपी

डायबिटीज की दवा से अल्जाइमर में भी फायदा

अनुसंधान

भूलने की बीमारी अल्जाइमर के खतरे को कम करने को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि डायबिटीज की कुछ दवाओं के इस्तेमाल से इस बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, अध्ययन से पता चला है कि टाइप-2 डायबिटीज में ब्लड शुगर कम करने वाली कुछ खास दवाओं का सेवन करने वाले लोगों के मस्तिष्क में एमिलाइड कम पाया गया। यह एक प्रोटीन है, जो अल्जाइमर का बायोमार्कर है। इसका संबंध अल्जाइमर समेत कई बीमारियों के बढ़ने से है। अमेरिकन एकेडमी आफ न्यूरोलाजी पत्रिका में अध्ययन के नतीजों को प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के मुताबिक, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज-4 इंहिबिटर्स नामक इन दवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों में याददाश्त में गिरावट भी कम पाई गई। इन दवाओं को ग्लिप्टिंस भी कहते हैं। टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ितों का शरीर ब्लड शुगर को नियंत्रित नहीं कर पाता है। इन मरीजों में जब डायबिटीज की दूसरी दवाएं काम नहीं कर पाती हैं, तब इन दवाओं की सलाह दी जाती है। ये दवाएं ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। दक्षिण कोरिया की योंसेई यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिसिन के शोधकर्ता फिल ह्यू ली ने कहा, 'डायबिटीज पीड़ितों में अल्जाइमर बीमारी का उच्च खतरा पाया जाता है। यह बीमारी मस्तिष्क में एमिलाइड-बीटा के बनने से संबंधित है।' अध्ययन से साबित हुआ है कि डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज-4 इंहिबिटर्स के इस्तेमाल से न सिर्फ ब्लड शुगर कम रहता है बल्कि मस्तिष्क में एमिलाइड भी कम होता है।' -एएनआइ

दवा के दोहरे फायदे। फाइल फोटो

स्क्रीन शॉट

धाकड़ के निर्देशक ने कंगना से कहा, आपको नहीं जानता

पूरी हुई कंगना अभिनीत धाकड़ की शूटिंग। इंस्टाग्राम

क्वीन अभिनेत्री कंगना रनोट कोरोना महामारी की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अपनी आगामी फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही थीं। बुधवार को उनकी इस स्पाई (जासूसी) एक्शन फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई। यह जानकारी कंगना ने इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा, 'फिल्म की शूटिंग खत्म हुई। मुझे अभी से उनकी (अपनी टीम) याद आने लगी है।' इसके साथ कंगना ने धाकड़ के निर्देशक रजनीश घई को मतलबी डायरेक्टर बताते हुए एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में कंगना रजनीश से पूछती हैं कि आपका आखिरी दिन है तो आप क्या कहना चाहेंगे। इस पर रजनीश हंसते हुए कहते हैं कि आप कौन हैं मैडम, मैं आपको जानता नहीं, आपकी तारीफ? फिर रजनीश कहते हैं कि उन्हें भी अपनी टीम की खूब याद आएगी। इस फिल्म में कंगना एजेंट अग्नि का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में उनके साथ अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं साल 2008 में मुंबई पर हुए 26/11 के आतंकी हमलों में शहीद हुए कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक फिल्म मेजर के अंतिम शेड्यूल की शूटिंग भी गुरुवार को शुरू हो गई। इस फिल्म में तेलुगू अभिनेता अदिवी शेष और अभिनेत्री सई मांजरेकर मुख्य भूमिका में हैं। वहीं दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्माजी नमकीन की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। इस फिल्म की अभिनेत्री जूही चावला ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह फिल्म ऋषि कपूर के बर्थडे चार सितंबर को रिलीज की जाएगी।

पिता की अनुपस्थिति में जाह्नवी ने शुरू की मिली की शूटिंग

रूही और गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल फिल्मों की अभिनेत्री जाह्नवी कपूर फिल्म मिली में पहली बार अपने पिता और निर्माता बोनी कपूर के प्रोडक्शन में काम कर रही हैं। मिली साल 2019 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म हेलन की हिंदी रीमेक है, जिसे मूल फिल्म के निर्देशक माथुकुट्टी जेवियर ही निर्देशित कर रहे हैं। अब खबर है कि जाह्नवी ने पिछले हफ्ते गुपचुप तरीके से मुंबई के एक बंगले में इस रीमेक फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जबकि उनके पिता बोनी फिलहाल लव रंजन के निर्देशन में बन रही रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म की शूटिंग के लिए दिल्ली में हैं। बोनी इस फिल्म में पहली बार अभिनय कर रहे हैं। हालांकि, मुंबई से दूर होते हुए भी बोनी, मुंबई में अपनी बेटी और मिली की शूटिंग पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट की शूटिंग जून में ही शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देरी हुई। फिलहाल मुंबई में चल रहे शेड्यूल के अंतर्गत निर्देशक जाह्नवी, उनके ब्वायफ्रेंड और पिता के किरदारों के साथ पहले इनडोर शूटिंग पूरी करेंगे। इसके अलावा वह फ्रीजर के अंदर वाला सीन भी मुंबई में ही शूट करेंगे। पूरी शूटिंग के दौरान बोनी माथुकुट्टी के साथ बराबर संपर्क में हैं। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग के लिए टीम अगले महीने देहरादून जा सकती है। बता दें कि इस फिल्म की कहानी रेस्तरां में काम करने वाली एक लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक दिन उसका मालिक गलती से फ्रीजर रूम में बंद करके चला जाता है।

पहली बार पिता के प्रोडक्शन में काम कर रही हैं जाह्नवी। इंस्टाग्राम

मेरे पार्टनर में साहस और सेंस आफ ह्यूमर होना जरूरी है : सान्या मल्होत्रा

अपने जीवनसाथी को लेकर हर इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं कि वह कैसा दिखना चाहिए या उसमें किस तरह के गुण होने चाहिए। दंगल गर्ल के नाम से प्रख्यात अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा की भी अपने जीवन साथी को लेकर कुछ प्राथमिकताएं हैं। जिनका रहस्योद्घाटन सान्या ने डिजिटल प्लेटफार्म वूट के सेलिब्रिटी चैट शो फीट अप विद स्टार्स 3 में किया। इस शो में सान्या ने पहले तो खुद को सिंगल बताया। उसके बाद जब उनसे उनके पार्टनर को लेकर प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'रिलेशनशिप में मैं जो तीन चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हूं, उनमें से एक है कम्युनिकेशन (बातचीत), दूसरा मेरा पार्टनर साहसी हो और एडवेंचर करना पसंद करे। यानी घूमना, स्काई डाइविंग और स्कूबा डाइविंग (पानी के अंदर तैरना) पसंद करे, क्योंकि मैं भी इसी तरह की हूं। तीसरी खासियत के तौर में मेरे पार्टनर में सेंस आफ ह्यूमर (हास्य) का होना भी जरूरी है।' इस दौरान सान्या ने अपने घुंघराले बालों के बारे में भी बातें कीं। उन्होंने कहा, 'घुंघराले बालों के साथ मैं जल्दी घर से नहीं निकल सकती हूं। मुंबई के गर्म मौसम में बाहर निकलने के पहले इनमें काफी प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। मेरे बाल जल्दी उलझ जाते हैं। इनकी देखभाल के लिए मुझे इनको धोते वक्त कंडीशनर, जेल और सुखाने जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।' सान्या आगामी दिनों में बाबी देओल और विक्रांत मेस्सी के साथ फिल्म लव हास्टल में नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

आगामी दिनों में फिल्म लव हास्टल में नजर आएंगी सान्या। इंस्टाग्राम

मुगल इतिहास के दौर के किंगमेकर्स पर आधारित शो डिजिटल प्लेटफार्म पर आठ एपिसोड में दिखाया जाएगा।

मैं निर्देश देने वाला निर्माता नहीं हूं : निखिल आडवाणी

डिजिटल प्लेटफार्म के लिए शो बना रहे हैं निखिल आडवाणी • इंटरनेट मीडिया

कल हो न हो, बाटला हाउस जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले निखिल अब डिजिटल प्लेटफार्म के लिए द एम्पायर लेकर आ रहे हैं। इस शो से वह बतौर शो रनर जुड़े हैं। यह एलेक्स रदरफोर्ड की किताब एम्पायर आफ द मुगल: रेडर्स फ्राम द नार्थ पर आधारित है। डिजिटल प्लेटफार्म पर ऐतिहासिक शोज लाने की वजहों, डिजिटल और सिनेमा के दर्शकों की पसंद जैसे कई मुद्दों पर निखिल ने बात की।

• आपने पीरियड ड्रामा फिल्म कभी नहीं बनाई। आपका शो को निर्देशित करने का मन नहीं किया?

-इस शो की निर्देशक मिताक्षरा कुमार बहुत प्रतिभावान हैं। वह संजय लीला भंसाली के साथ पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि पीछे रहकर अपने दिग्गज निर्देशकों को सपोर्ट करूं। बहरहाल, मेरी इतिहास में काफी दिलचस्पी है। मैंने एलेक्स रदरफोर्ड की किताब पढ़ी। वह कमाल की है। मुझे लगा कि इस पर शो बनाने के लिए पहले खुद का तैयार होना जरूरी है, क्योंकि इस किताब के किरदारों, भावनाओं का जो स्तर है, उसे जिम्मेदारी के साथ अगर सही तरीके से नहीं बना पाए, तो कोई फायदा नहीं है।

• शो को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने और शो का नाम मुगल बदलकर द एम्पायर करने की क्या वजह रही?

-मैं इतिहास की क्लास लोगों को नहीं देना चाहता हूं। इस शो की कहानी एक शासक की नहीं है बल्कि किंगमेकर्स की है, जो शासक बनाते हैं, इसलिए हमने शो का नाम बदला। जहां तक लेखन की बात है इसके लिए हम दो-तीन हफ्तों के लिए एक रूम में बैठकर लेखकों के साथ किताब से शो को स्क्रिप्ट में परिवर्तित करना, फिर उसे अपने तरीके से आठ एपिसोड में डालना, लेखन की यह प्रक्रिया मेरे लिए नई रही।

• इतिहासकारों का कहना होता है कि इतिहास आधारित शो या फिल्मों में सिनेमाई लिबर्टी ले ली जाती है। उसे इतिहास के प्रमाण के तौर पर नहीं ले सकते..

-मैं यह कह ही नहीं रहा हूं कि ऐतिहासिक तौर पर यह शो बिल्कुल सही है या नहीं। मैंने किताब के अनुसार इसे बनाया है। जिन्होंने यह किताब लिखी है, वह खुद इतिहासकार हैं। इतिहास को लेकर जो उन्होंने किताब में लिखा है, वह हमने बनाया है।

• आज के आधुनिक दौर में मुगलों के दौर को दर्शाना क्यों जरूरी लगा? उस दौर की महिलाओं को कैसे देखते हैं?

-क्योंकि मुझे कहानी और किरदार बहुत दिलचस्प लगे, इसलिए बनाया है। इतिहास में जिन महिलाओं का जिक्र हैं, वह बहुत पावरफुल रही हैं। फिल्मों में मजबूत तरीके से उनकी भूमिका को नहीं दर्शाया गया है। हमने कोशिश की है उस पावर को दिखाने की। मैं आगे मुंबई डायरीज, राकेट ब्वायज जैसे कंटेंट बना रहा हूं। राकेट ब्वायज वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और होमी भाभा के जीवन पर आधारित है। वह भी इतिहास का अलग हिस्सा रहे हैं। कौन बनेगा शेखावती शो में नसीर साहब (नसीरुद्दीन शाह), लारा दत्ता के साथ शो बना रहा हूं, जो पारिवारिक उतार-चढ़ाव पर कामेडी जोन में है।

• ए एम्पायर के सेट पर आप खुद कितना मौजूद रहे?

-इस शो की बात करूं, तो लेखक और शो रनर के तौर पर तो मैं रहा ही हूं, लेकिन मैंने इसके सारे एक्शन सीन्स भी शूट किए हैं। हालांकि मेरा मानना है कि मेरा सेट पर हमेशा रहना जरूरी नहीं है। हमने जो सिस्टम बनाया है, उसमें हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। हमारे पास सक्षम लोग हैं। मैं उस किस्म का निर्माता नहीं बनना चाहता हूं, जो निर्देश देता रहता है।

• डिजिटल प्लेटफार्म वास्तविक कंटेंट को ज्यादा तरजीह दे रहा है...

-नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर, द फैमिली मैन 2, स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी जैसी जो भी वेब सीरीज बनी हैं, वह भी अच्छी चली हैं। मैं लेखन और शूटिंग का काम जब नहीं कर रहा होता हूं, तब मैं इतिहास पढ़ता हूं। इसलिए एयरलिफ्ट फिल्म में कुवैत से लोगों को बचाकर निकालने वाली या बाटला हाउस फिल्म जैसी कहानियां सामने आती हैं।

• पिछले डेढ़ वर्षों में सिनेमाघर आधे समय तो बंद ही रहे। यह डिजिटल प्लेटफार्म की ओर झुकाव की बड़ी वजह रही..

-हां, यह सही बात है। सिनेमा और डिजिटल प्लेटफार्म के जो दर्शक हैं, वह आपस में ओवरलैप हो गए हैं। मेरा मानना है कि सिनेमा के दर्शक बहुत ज्यादा हैं। जब थिएटर में 19 अगस्त को बेल बाटम फिल्म रिलीज होगी, तो लोग फिल्म देखने के लिए जरूर जाएंगे। हम एक उम्मीद के साथ कंटेंट बना रहे हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं कि लोग सिनेमा देखने वापस नहीं जाएंगे।

(स्मिता श्रीवास्तव)

बालीफंक जानर मेरी ही संकल्पना है : बेनी दयाल

कभी अलग और नए वाद्ययंत्रों के साथ, तो कभी सुर, लय और ताल के विभिन्न प्रारूपों को मिलाकर, संगीत की दुनिया में संगीतकार अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। संगीत प्रेमियों के कुछ इसी तरह के अनोखे प्रयोग दिखेंगे एमटीवी के नए म्यूजिकल शो अनवाइंड में। आज से शुरू हो रहे 10 एपिसोड के इस शो में सोनू निगम, कैलाश खेर, लकी अली, बादशाह और बेनी दयाल समेत देश की कई बड़ी हस्तियां अलग-अलग जानर्स (विधाओं) के गानों पर परफार्म करेंगी। बेनी दयाल इस शो में बालीफंक जानर में परफार्म करेंगे। इस बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में बेनी ने कहा, 'इस शो में सिर्फ अपने देश के ही नहीं, दुनिया के कई अन्य जानर्स के म्यूजिक को भी मिलाकर कलाकार अपने नजरिए के साथ पेश करेंगे। यह कांसेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। इस शो में मेरा जानर है बालीफंक, जिसका मतलब है कि बालीवुड के गानों को फंकी (फैशनेबल) लहजे में गाऊंगा। वैसे भी मेरे ज्यादातर गाने बालीफंक हो ही जाते हैं, क्योंकि मैं बालीवुड का कलाकार हूं और मेरा म्यूजिक फंकी होता है। बालीफंक नाम मेरी ही एक संकल्पना है, लेकिन इस शो के लिए मैंने एमटीवी की टीम के साथ चर्चा करने के बाद जानर का नाम तय किया था।' इसके आगे छूमंतर.., द डिस्को सांग.. और बदतमीज दिल.. गानों के गायक बेनी कहते हैं, 'गानों को लेकर मेरी कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं है, मुझे जो भी मिलता है मैं वह गा देता हूं।'

एमटीवी अनवाइंड शो में परफार्म करेंगे बेनी। टीम स्वयं

27 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी चेहरे

भले ही महाराष्ट्र में अब भी थिएटर्स न खुले हों, लेकिन बेल बाटम फिल्म की रिलीज के ऐलान से बाकी फिल्ममेकर्स का हौसला बढ़ा है। अब फिल्मों की रिलीज तारीख की घोषणाओं का सिलसिला जारी हो गया है। गुरुवार को अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म चेहरे की भी रिलीज तारीख की घोषणा कर दी गई। 27 अगस्त को चेहरे सिनेमाघरों में ही रिलीज होगी। दैनिक जागरण से बातचीत में फिल्म के निर्देशक रूमी जाफरी ने बताया कि हम जानते हैं कि थिएटर हर जगह खुल भी जाएंगे, तब भी सुरक्षा के नजरिये से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे, लेकिन हमने यह फिल्म बड़े पर्दे के लिए ही बनाई है। कामेडी और रोमांटिक कामेडी फिल्मों से अलग मैंने पहली बार थ्रिलर जानर में कोशिश की है। अपने करियर की दूसरी पारी में इंटरवल के बाद मैं खुद में बदलाव लाना चाहता हूं, इसलिए अलग कहानी लिखनी ही थी। चेहरे की कहानी, निर्देशन, बैकग्राउंड म्यूजिक पर बहुत काम किया गया है, जो रोमांच क्रिएट करेंगे। बेस्ट तकनीशियन्स ने इस फिल्म पर काम किया है, ऐसे में फिल्म के साउंड का मजा सिर्फ थिएटर में ही आएगा। निर्माता आनंद पंडित का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फिल्म को रिलीज करने के लिए एक साल तक इंतजार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि थिएटर में लोग इस फिल्म को देखने आएंगे।

फिल्म में मुख्य किरदार में हैं अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी • इंस्टाग्राम